चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

इंसाफ़ की आवाज़ पर पाबंदी

पेज 4

यौन पेशे को क़ानूनी मान्यता देना घातक

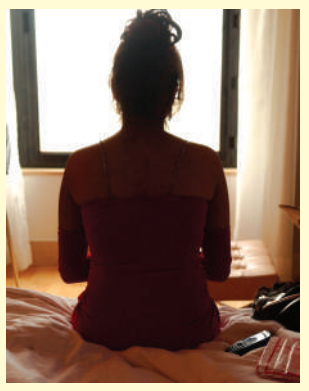

पेज 7

समाज को साईं कृपा की ज़रूरत

पेज 11

अकादमी पुरस्कारों का खेल

पेज 13

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 28 दिसंबर 2009–3 जनवरी 2010

रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट

मुस्लिम आरक्षण का भविष्य?

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने के मसले पर देश में मौक़ापरस्त सियासत की जो फ़िज़ां बनी है उससे एक बात तो साफ़ है कि सियासी दलों के लिए देश का दलित मुसलमान उसकी बिसात का बस एक मोहरा है और उनके हक़ ओ हूक़ूक़ की बात महज़ एक सियासी चाल. इस बहाने सियासतदानों की चाल और चरित्र दोनों सामने हैं.

मनीष कुमार

इतिहास में ऐसे मौक़े कम ही आते हैं, जब किसी अख़बार की वजह से सरकार को वह करने को मजबूर होना पड़ता है, जिसे वह किसी भी हाल में करना नहीं चाहती. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश होने की घटना सरकार की कुछ ऐसी ही मजबूरी को ज़ाहिर करती है. सरकार के पास रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट 22 मई 2007 से थी. उसने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था. मामला दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के आरक्षण से जुड़ा होने के कारण विवादास्पद है. सरकार ने चुनावी नुक़सान और फ़ायदे को देखते हुए इसे दबा रखा था. चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद संसद में हंगामे का सिलसिला शुरू हो गया. चौथी दुनिया की रिपोर्ट की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा. लगभग सभी पार्टी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही सदनों में चौथी दुनिया अख़बार लहरा कर सरकार को रिपोर्ट पेश करने को बाध्य कर दिया. संसद के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिन 18 दिसंबर को सरकार को रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट संसद में रखने को मजबूर होना पड़ा.

लेकिन सवाल यह है कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट संसद में रख देने मात्र से क्या ग़रीब मुसलमानों और ग़रीब ईसाइयों के आरक्षण का रास्ता साफ़ हो गया? सरकार ने जिस तरह चुपके से संसद में रिपोर्ट को रखा और जिस तरह से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आगामी कई चुनावों में यह मुद्दा सबसे प्रमुख बनकर उभरेगा. मुसलमानों और ईसाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर हर पार्टी में भ्रम की स्थिति है. दरअसल इसमें कई पेंच हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण किस कोटे से दिया जाएगा. क्या इन्हें सामान्य कोटे से 15 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा? या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे से काट कर अल्पसंख्यकों के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा? रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट का सरकार ने राजनीतिकरण कर दिया है. अल्पसंख्यकों के आरक्षण के विषय को जीवित रखकर हर पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है. सवाल यह है कि राजनीति की बिसात पर ग़रीब और ज़रूरतमंद अल्पसंख्यकों के हक़ के लिए लड़ने वाला कौन बचेगा?

मुसलमानों और ईसाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर हर पार्टी में भ्रम की स्थिति है. इसमें कई पेंच हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें आरक्षण किस कोटे से दिया जाएगा?

मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक़ अल्पसंख्यकों का है. यूपीए सरकार के कार्यकाल में रंगनाथ कमीशन का गठन हुआ. अफ़सोस की बात यह है कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरह से संसद में रखा गया, उससे तो यही लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में घोर विरोधाभास है. सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि उसने रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट के साथ कोई एटीआर नहीं रखी. सरकार ने यह भी नहीं बताया कि इस रिपोर्ट को कैसे लागू किया जाएगा और कब लागू किया जाएगा. हैरानी की बात यह है कि जिस वक़्त यह रिपोर्ट संसद में पेश की जा रही थी, उस वक़्त प्रधानमंत्री ग्लोबल वार्मिंग की पहले से असफल बैठक में हिस्सा लेने कोपेनहेगन में मौजूद थे.

अजीबोग़रीब बात यह है कि सरकार ने रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन देश की जनता को यह पता भी नहीं चल पाया कि सरकार इस रिपोर्ट का क्या करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी का रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर रवैया क्या है. हैरानी की बात है कि इस बारे में अभी भी कुछ पता नहीं है.

इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण क्या होगा, यह समझना आसान है. भाजपा इसका विरोध कर रही है, लेकिन कई

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सियासत की बिसात

रूबी अरुण

सियासतदानों की कलई उतरने लगी है. रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं के बहाने सियासी पार्टियां अपनी-अपनी गोटी फिट करने की जुगत में हैं. इस कोशिश में दलित ईसाई और मुसलमानों की कोई फ़िक्र नहीं है. अगर कुछ है तो वह है ख़ुद का फ़ायदा कराने का तिकड़म. हर पार्टी इन दिनों रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं का गहन अध्ययन कर रही है. पार्टियों को उन मुद्दों की तलाश है, जिनकी बिना पर वह आम अवाम की नज़रों में वीर्यवान नायक बन सकें. हालांकि इस उठापटक और जोड़-तोड़ की राजनीति में फ़िलहाल कोई भी पार्टी अपना रुख़ खुले तौर पर साफ़ करने से परहेज कर रही है. हालात संशय के भी हैं और उधेड़बुन के भी. लेकिन झंझावात सबके ज़ेहन में है. लिहाज़ा इस मसले पर भारतीय राजनीति में दंगल मचने के पूरे आसार हैं. हमने इस मुद्दे पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से बात की. सवाल सिर्फ़ इतना कि क्या सरकार कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करेगी? और अगर लागू कर देती है तो यह 15 फ़ीसदी आरक्षण सरकार को किस कोटे से देना चाहिए- जनरल, ओबीसी या एससी-एसटी कोटे से? हमें जो जवाब मिले, उनसे रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने के मसले पर मचे सियासी घमासान का परिदृश्य साफ़ हो गया.

ख़ुद को दलितों का मसीहा कहलाना पसंद करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

हम आंदोलन कर सरकार को आरक्षण देने के लिए बाध्य कर देंगे.

मुलायम सिंह यादव

हर हाल में अनुशंसा लागू करनी होगी, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे.

लालू प्रसाद यादव

रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट का पहले बारीकी से अध्ययन तो कर लें, फिर बोलेंगे.

प्रकाश कारात

उन्हें आरक्षण सामान्य कोटे से देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए.

रामविलास पासवान

हम इस आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं.

सुषमा स्वराज

रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप आरक्षण लागू होना चाहिए.

बुद्धदेव भट्टाचार्य

केंद्र सरकार अपने फ़ैसले ले. हम तो मुसलमानों को आरक्षण दे ही रहे हैं.

नीतीश कुमार

पार्टी में विचार विमर्श करने के बाद ही हम अपना रूख़ साफ़ करेंगे.

डी. राजा

सरकार दलित मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी कोटे से दे.

अली अनवर अंसारी

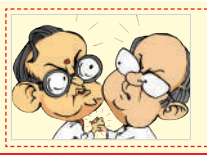

योजना आयोग के सदस्य एवं मुद्रास्फीति पर कोमोडिटी फ्यूचर्स के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत सेन इसकी जोरदार सिफ़ारिश करते हैं कि दोनों ही गतिविधियां एक दूसरे से संबंधित हैं

दिल्ली का बाबू

किसके बाबू जीतेंगे?

भूपेंद्र सिंह हुड्डा, *मुख्यमंत्री, हरियाणा*

पंजाब के राज्यपाल एस एफ रोड्रिग्स का कार्यकाल पिछले माह समाप्त हो चुका है. इसके बावजूद केंद्र सरकार को अभी नए महामहिम की घोषणा करनी है. विलंब की वजह मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के बीच इस बात को लेकर तनातनी है कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ पर नियंत्रण किसका होगा. केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण चंडीगढ़ पहले मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता था, लेकिन पंजाब में आतंकवाद के दौर में यहां शासन की ज़िम्मेवारी पंजाब के राज्यपाल को सौंप दी गई, ताकि शहर के प्रशासन पर सही तरीक़े से नियंत्रण रखा जा सके.

बहरहाल रोड्रिग्स के विवादों से भरे कार्यकाल के दौरान पंजाब के राज्यपाल को सौंपी गई शक्ति वापस लेने की कोशिश का आधार तैयार हुआ. चिदंबरम केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के पक्षधर हैं. जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि अंतिम नियंत्रण तो पंजाब के राज्यपाल का ही होगा, क्योंकि तमाम व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए चंडीगढ़ तो पंजाब का है. ज़ाहिर है, इससे प्रभावित होने वाला दूसरा राज्य हरियाणा भी इस विवाद में कूद पड़ा है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के प्रस्ताव की प्रकाश सिंह बादल ने जमकर आलोचना की है. इसकी जगह बादल ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वह चंडीगढ़ से अपने अधिकारियों को हटाना शुरू करे, ताकि चंडीगढ़ को पंजाब के ज़िम्मे किया जा सका. बहरहाल हुड्डा ने इसका जवाब यह कहकर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख का पद एक निश्चित समयावधि के लिए बारी–बारी से हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल को सौंपा जाना चाहिए. तो किसके बाबू जीतेंगे–चिदंबरम के, हुड्डा के या फिर बादल के?

दिलीप चेरियन

एक टकराव यह भी

मालगोदाम (वेयरहाउस) को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अधीन लाने के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय टकराव की राह पर हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वस्तुओं को वित्तीय बाज़ार के पूर्व नियामक सेक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के अधीन लाने के वित्त मंत्रालय के पूर्व प्रस्ताव का विरोध किया है. उसने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह मुंबई की तर्ज पर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनाएं, जो वस्तुओं के व्यापार और तमाम वेयर हाउस का भी नियामक हो. उसका मुख्य उद्देश्य वस्तु व्यापार से जुड़ी तमाम गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उसे देशव्यापी स्तर पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना हो.

मंत्रालय संभवत: यह महसूस कर रहा है कि कोमोडिटी फ्यूचर्स और पूंजी बाजार नियमन दो अलग चीजें हैं, क्योंकि इन दोनों के हितधारक एक नहीं हैं. बहरहाल, योजना आयोग के सदस्य एवं मुद्रास्फीति पर कोमोडिटी फ्यूचर्स के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष अभिजीत सेन इसकी जोरदार सिफ़ारिश करते हैं कि दोनों ही गतिविधियां एक दूसरे से संबंधित हैं और इन्हें एक मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए. इस पर अंतिम फ़ैसला क्या होगा, यह तो सरकार को तय करना है.

मुस्लिम आरक्षण का भविष्य?

सियासत की बिसात

पृष्ठ एक का शेष

धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होने वाला है. मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की मांग है कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू किया जाए. सरकार से उनकी शिकायत यह है कि रिपोर्ट के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी होनी चाहिए थी. कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि मुस्लिम आरक्षण में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है. पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा जाना है, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही यह फ़ैसला किया जा सकता है कि रिपोर्ट को किस हद तक मंजूर किया जा सकता है. यह सब करने में काफ़ी वक़्त लगेगा. हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के पूरे विश्लेषण तक हमें इंतज़ार करना चाहिए.

अगर इस तरह के बयान आएंगे तो सरकार और कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल उठना लाज़िमी है. दो सालों तक इस रिपोर्ट को सरकार ने अपने पास रखा. क्या दो सालों तक सलमान खुर्शीद ने इसे खोलकर नहीं देखा कि इसमें क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को यह याद नहीं रहा कि रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश करना है और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ऐसा करना ज़रूरी है? अगर यह रिपोर्ट दो साल तक सरकारी आलमारी में यूं ही धूल फांकती रही तो यह कहना ग़लत नहीं होगा कि अगर चौथी दुनिया ने इस रिपोर्ट को लीक नहीं किया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह सरकार इसे भुला देती. सरकार अल्पसंख्यकों के आरक्षण को कितना गंभीर मान रही है, यह इससे भी साबित होता है कि जब इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया तो इसके साथ कोई एटीआर नहीं रखी गई. सरकार ने यह बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि ज़रूरतमंद मुसलमानों को किस तरह आरक्षण दिया जाएगा. इस मामले में सरकार का रवैया काफ़ी ढुलमुल है. एटीआर नहीं रखने के पीछे सरकार वैधानिक और तकनीकी कारणों का हवाला दे रही है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद मुसलमानों के आरक्षण पर कोई ठोस बात करते नज़र नहीं आए. सलमान खुर्शीद का तर्क यह है कि कार्रवाई रपट इसलिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन जांच आयोग क़ानून के तहत नहीं किया गया था. वक़ालत और राजनीति में फ़र्क़ होता है. जब अल्पसंख्यकों के हितों की रखवाली के ज़िम्मेदार मंत्री महोदय वकीलों की तरह तर्क देने लग जाएं तो यही मतलब निकलता है कि दाल में कुछ काला है. रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करने के लिए सलमान खुर्शीद दूसरा तर्क देते हैं. वह कहते हैं कि इसे लागू करने के लिए क़ानून में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी. काश, मंत्री जी ने इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया होता. इस रिपोर्ट में साफ़–साफ़ कहा गया है कि इन सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यह वैधानिक या प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा पूरी तरह से कार्यान्वित हो सकती है. तो सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र से ज़्यादा क़ानून की जानकारी है?

यहां एक और घटना के बारे में जानना ज़रूरी है. गुजरात विधानसभा में जब मोदी सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने रंगनाथ मिश्र आयोग पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया. ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी वैचारिक बहस की शुरुआत होती है तो कांग्रेस पीठ दिखाकर भाग जाती है. क्या कांग्रेस की विचारधारा खोखली हो गई है? प्रधानमंत्री जी तो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं. उनको यह समझना चाहिए कि ऐसी घटनाओं से अल्पसंख्यकों का विश्वास टूटता है. मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को आगे आना चाहिए. प्रधानमंत्री के विश्वास को मज़बूत करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा और मुस्लिम आरक्षण का भविष्य अधर में लटक जाएगा.

manish@chauthiduniya.com

पृष्ठ एक का शेष

अध्यक्ष रामविलास पासवान इस सवाल पर छूटते ही कहते हैं, रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसा तो हर हाल में लागू होनी ही चाहिए. और रही कोटे की बात, तो सामान्य कोटे से ही 15 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए. पर पासवान जी, अगर सामान्य श्रेणी में से 15 फीसदी आरक्षण दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को देने के लिए सरकार राजी हो जाती है तो देश में कैसा सामाजिक तूफ़ान उठेगा, इसका अंदाज़ा है आपको? रामविलास पासवान फरमाते हैं, देखिए जब भी कोई नई पहल होती है, तो थोड़ी उथलपुथल होती है. लेकिन यह मसला मज़लूमों की तरक्की से जुड़ा है, इसलिए हम इसकी लड़ाई पुरज़ोर तरीक़े से लड़ेंगे. मतलब साफ़ है कि रामविलास पासवान अपने परंपरागत दलित–पिछड़ों के वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहते. अब बात करते हैं उस पार्टी की, जो ख़ुद को ग़रीबों के अधिकारों की जंग लड़ने वाला अकेला वीर–बांकुरा साबित करने की हर वक़्त जद्दोजहद में रहती है. इसके महासचिव प्रकाश कारात फ़िलहाल इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं. इसके लिए उनके पास एक बड़ा माकूल सा जवाब है, मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, इसलिए अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. अब प्रकाश कारात ऐसा कह रहे हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन एक सहज जिज्ञासा होती है कि क्या वाकई सच यही है? प्रकाश कारात जैसे बुद्धिजीवी और बेहद सजग नेता क्या सचमुच कमीशन की रिपोर्ट से अभी तक नावाक़िफ़ हैं? हालांकि प्रकाश यह ज़रूर कहते हैं कि उनकी पार्टी पहले रिपोर्ट के हर पहलू पर ग़ौर करेगी, फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी.

हालांकि रुख़ इनका सकारात्मक ही है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पार्टी की लाइन के मुताबिक़ उद्घोष भी कर रहे हैं. बुद्धदेव कहते हैं कि देश में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को विकास का एक समान मौक़ा मिलना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रवैये पर ही क़ायम है. वह कतई नहीं चाहती कि इन अनुशंसाओं को लागू किया जाए. यह अलग बात है कि भाजपा भी सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह के साथ इस बात के पक्ष में है कि रिपोर्ट पेश की जाए. पर रिपोर्ट लागू हो, ऐसी मंशा भाजपा की नहीं है. भाजपा नेता सुषमा स्वराज कहती हैं कि इससे कई दुश्वारियां पैदा होंगी. भारतीय संविधान में, संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षण है. यदि इस अनुशंसा को लागू कर दिया जाता है तो दलित श्रेणियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा की इन सीटों पर ईसाई या मुसलमान जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे. इससे उन्हें दोहरा लाभ होगा, जो भारतीय समाज के हित में नहीं है. भाजपा नेता अरुण जेटली भी सुषमा स्वराज की बात पर हामी भरते हैं. अरुण जेटली कहते हैं कि यह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सोची– समझी रणनीति की पहली कड़ी है. अनुशंसा लागू होगी तो आरक्षण का फ़ायदा उठाने के लिए धर्मांतरण के मामले बढ़ेंगे. सामाजिक समीकरण बिगड़ेगा. जिस प्रदेश में ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहां वे सत्ता संभालने की स्थिति में भी आ सकते हैं. ऐसी हालत में भारतीय समाज की दलित जातियों में निराशा–हताशा फैलेगी. उनके उत्थान में अवरोध पैदा होगा. इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि इस साजिश को शुरुआत में ही तोड़ा जाए.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद डी राजा की दलील भी बिल्कुल प्रकाश कारात की तर्ज़ पर है. वह दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की तरक़्क़ी तो चाहते हैं, पर फ़िलहाल कुछ भी कहने से बचना चाहते हैं. वजह वही, जो प्रकाश कारात फरमा रहे हैं. अभी रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, उन्होंने उसकी बारीकी नहीं समझी है. लिहाज़ा अभी कुछ बोलना मुनासिब नहीं. ज़ाहिर है, मुस्लिम आरक्षण के नाम पर सियासी दलों ने अपनी–अपनी हांडी चढ़ा रखी है.

हैरानी इस बात की है कि इस मुद्दे पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती ने ख़ामोशी साध रखी है. लालू यादव और मायावती, दोनों ही ख़ुद को दलितों और मुस्लिमों का फरमाबदार साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते. फिर यह चुप्पी क्यों? क्या पक रहा है इनके ज़ेहन में? लालू यादव ने तो इतना भी कहा कि वह अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे, पर मायावती तो पूरे परिदृश्य से ग़ायब हैं.

हालांकि यह वही मायावती हैं, जिन्होंने वर्ष 2006–07 में इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास चिट्ठियों का पुलिंदा भेजा था. क्या डर है मायावती को? अपना वोट बैंक खिसकने का या अगड़ी जातियों के नाराज़ होने का? क्यों उहापोह की स्थिति में हैं मायावती?

रही बात लालू यादव की, तो अभी शायद वह तेल और तेल की धार देख रहे हैं. वाजिब भी है. फ़िलहाल वह प्रदेश और देश की राजनीति में कहीं नहीं हैं. बिहार में वह दोबारा अपने पैर जमाने की कशमकश में हैं. लाजिमी है, ऐसे संजीदा मसले पर वह पूरी तरह ठोक–बजाकर ही मुंह खोलेंगे.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी वेट एंड वॉच का रुख़ अपना रखा है. हालांकि वह और उनकी पार्टी पूरी तरह इस आरक्षण के पक्ष में हैं. जदयू के ही राज्यसभा सांसद अली अनवर की लंबी लड़ाई का ही नतीज़ा है कि यह मसला यहां तक पहुंचा और सरकार पर इतना दबाव बन सका कि वह रिपोर्ट संसद में पेश करने को मजबूर हो गई.

पर इन सभी सियासी दांव–पेंचों के बीच सरकार और कांग्रेस पार्टी की स्थिति दोधारी तलवार पर चलने जैसी हो गई है. सरकार ने सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और अन्य नेताओं के दबाव में इसे संसद में पेश तो कर दिया, पर उसे डर है कि कहीं उसकी हालत वी पी सिंह सरकार जैसी न हो जाए. हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी इस पर बड़े एहतियात से बात करते हैं. वह कहते हैं कि सरकार इसे लागू करने की हर संभावना पर ग़ौर कर रही है. जब सरकार ने इसे संसद में पेश कर दिया है तो इसके हरेक पहलू पर विचार कर लागू कराने की भी कोशिश करेगी. लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता सच कह ही जाते हैं. फरमाते हैं कि सरकार ने संसद में गुमनाम तरीक़े से तो इस रिपोर्ट को रख दिया, पर इसे लागू करने की हिम्मत वह नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसे पता है कि इससे मंडल–कमंडल का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा. सामान्य श्रेणी से आरक्षण तो सरकार देगी नहीं. मंडल आयोग ने जो 27 फीसदी आरक्षण पिछड़ों को दिया है, उसी में से आरक्षण देने का रास्ता निकालने की कवायद होगी. मतलब यह कि एक पिछड़ा दूसरे पिछड़े के पेट पर लात मारेगा. संविधान में भी कई बदलाव करने होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में ही दलित को परिभाषित किया गया है. दूसरा सवाल यह कि शैक्षणिक संस्थानों में 15 फीसदी आरक्षण कहां से आएगा? क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटे से तो अल्पसंख्यकों को लाभ नहीं दिया जा सकता और न ही सामान्य श्रेणी के 50 फीसदी कोटे से. दोनों ही स्थितियों में देश में आग लग जाएगी. सबसे बड़ा सवाल यह कि आख़िर सरकार करेगी क्या? सरकार इसे लागू कर कुंए में गिरना पसंद करेगी या फिर लागू न करके खाई में छलांग लगाना या फिर रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सियासत की बलि चढ़ जाएगी?

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 42,
दिल्ली, 28 दिसंबर 2009 –3 जनवरी 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग

कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश – 201301

कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

फोन न.
संपादकीय 011–23418962
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अली अनवर अंसारी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करवाने की ख़ातिर कमर कसकर तैयार है.

फोटो– प्रभात पाण्डेय

आरक्षण इस्लाम की मूल विचारधारा के ख़िलाफ़ : नक़वी

शशिशेखर

मुख्तार अब्बास नक़वी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. बात जब रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट और करोड़ों अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ देने की आती है तो वह पार्टी लाइन से अलग बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. चौथी दुनिया ने जब रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की तो संसद के दोनों सदनों में पक्ष–विपक्ष के सांसदों ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सुर में सरकार पर दबाव डाला. लगभग सभी दलों के मुस्लिम सांसदों ने रिपोर्ट पेश कर उसकी अनुशंसाओं को लागू करने की मांग की. चुप रही तो केवल भाजपा. ऐसे में देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों को यह सोचना पड़ेगा कि आख़िर उनका सच्चा हमदर्द कौन है? चौथी दुनिया के साथ एक बातचीत में रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं पर भाजपा और ख़ुद की राय बता रहे हैं मुख्तार अब्बास नक़वी.

रंगनाथ मिश्र आयोग 2007 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है, लेकिन ढाई साल के बाद भी केंद्र सरकार संसद में इस पर चर्चा कराने से बचती रही. वजह क्या थी?

देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार है, उसकी एक पॉलिसी है कि कुछ मत करो. अगर कुछ करोगे ही नहीं तो लोगों को लगेगा कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है. रंगनाथ मिश्र आयोग जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को संसद में लाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए इसके तमाम पहलुओं पर. हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर कोई सहमत हो और कोई असहमत, लेकिन सरकार की नीति में खोट है.

लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो गई. चौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित किया, लेकिन इस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकी. इन दोनों रिपोर्ट्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं?

लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में बुनियादी फ़र्क़ है. लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट तनाव पैदा करने वाली थी, जो इस सरकार को सूट करती है. रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट तनाव को कम करने वाली है, क्योंकि यह लोगों के सरोकार से, लोगों के रोज़गार से और लोगों की समस्याओं के समाधान से जुड़ी रिपोर्ट है. इसके बहुत से पहलुओं से हम सहमत नहीं हैं. बहुत से पहलुओं पर हो सकता है कि सरकार भी सहमत हो या न हो.

रंगनाथ मिश्र आयोग ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की अनुशंसा की है. 15 प्रतिशत आरक्षण, जिसमें 10 प्रतिशत मुसलमानों को देने की बात कही गई है. आप क्या कहते हैं?

केवल आरक्षण मात्र से मैं यह नहीं मानता कि किसी भी समाज या संप्रदाय के आर्थिक–सामाजिक हालात बेहतर हो सकते हैं. जहां तक बात है आरक्षण की, तो मंडल कमीशन के आरक्षण के दायरे में आज भी मुसलमानों की बड़ी संख्या है. लेकिन, मेरी समझ से आरक्षण का आधार अगर आर्थिक होगा तो उससे मुसलमानों को भी बहुत फ़ायदा होगा.

आयोग ने कहा है कि मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसकी हालत किसी हिंदू दलित से कमतर नहीं है. आयोग ने संविधान से पैरा 3 हटाने की भी बात की है (अनुसूचित जाति से संबंधित राष्ट्रपति आदेश 1950), जिसकी वजह से अब तक सिर्फ़ हिंदू, बौद्ध और सिखों को ही अनुसूचित जाति का दर्ज़ा मिल रहा है. यानी यह भी तो एक तरह से धर्म के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है.

इस्लाम में ऊंच–नीच और छुआछूत की कल्पना नहीं है. इस्लाम में बहुत स्पष्ट है कि वे सभी लोग चाहे जो काम कर रहे हों, उनको बराबर सामाजिक अधिकार हैं.

मान लीजिए कि आरक्षण विकास के लिए अगर एक साधन साबित होता है, जैसा कि अभी तक हुआ है ओबीसी या अन्य वर्गों के लिए, तो मुसलमानों को भी अगर 10 फ़ीसदी आरक्षण मिल जाता है तो इसमें क्या...

(बीच में रोकते हुए) देखिए, आरक्षण कभी भी किसी समाज की प्रगति के लिए टूल साबित नहीं हुआ है. आरक्षण उस समाज के कुछ नेताओं की प्रगति के लिए ज़रूर टूल साबित हो गया होगा. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के लिए, बिहार में पासवान जी के लिए या लालू प्रसाद यादव जी के लिए या अन्य कहीं किसी के लिए. मैं मानता हूं कि, हालांकि धार्मिक लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इस्लाम का एक अलग कांसेप्ट है बराबरी का, सामाजिक एकता का. छुआछूत की जो बीमारी थी, उसके ख़िलाफ़ ही एक सोशल मूवमेंट के रूप में इस्लाम शुरू हुआ था. फिर वही सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, जो इस्लाम में कहते हैं कि नहीं हैं. यह तो इस्लाम के मूल सिद्धांतों और राजनैतिक सिद्धांतों के बीच की लड़ाई है. इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते.

मतलब अगर मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्ज़ा दिया जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए तो यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ होगा?

देखिए, मैं कोई इस्लामिक विद्वान नहीं हूं, लेकिन यह तो सीधा–सीधा झगड़ा है न.....राजनैतिक सिद्धांतों और इस्लाम के सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं वे जाने.. लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि लोगों को आर्थिक रूप से प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से आरक्षण हो तो हम उसका समर्थन करेंगे.

रंगनाथ मिश्र आयोग भी सामाजिक–आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देने की बात कर रहा है.

हां तो, सामाजिक–शैक्षणिक आधार पर मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है. इसमें सिर्फ़ मुसलमान–हिंदू मत जोड़िए.

इसमें मुसलमान भी हैं और ईसाई भी.

(बीच में रोकते हुए) इसमें क्या है, जिस समय आप किसी धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जिसको लाभ मिलना होता है, उसको नहीं मिलता है. फिर वे राजनैतिक विरोध के सुपुर्द हो जाते हैं सारे के सारे मुद्दे.

संसद में जब इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी तो क्या रुख़ होगा आपकी पार्टी का?

देखिए, हम धर्म के नाम पर आरक्षण के विरोधी हैं. आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर आरक्षण का क्राइटेरिया है... उसमें मुसलमान भी आते हैं तो हम उसके समर्थक हैं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

आख़िरी दम तक लड़ेंगे

सांसद अली अनवर अंसारी

फोटो– प्रभात पाण्डेय

हक़ बात में, एक ग़रीबी ताक़त होती है.

जदयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर इस वाक्य को हमेशा अपने ज़ेहन में ताज़ा रखते हैं, क्योंकि यह उन्हें ग़रीबों के हक़ ओ हुकूक़ के लिए लड़ने का जज़्बा देता है. जब कभी भी अली अनवर अंसारी ने राज्यसभा में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को पेश करने की आवाज़ उठाई तो हमेशा यह बात उनके दिल ओ दिमाग़ में तैरती रही कि उन्हें यह जंग जीतनी है, क्योंकि इस जीत से बेबस और लाचार दलित मुसलमानों की ज़िंदगी जुड़ी है. बार–बार लगातार अली अनवर अंसारी ने अपनी आवाज़ बुलंद की. अकेले अपने बूते, इस मसले पर तीन–तीन बार राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करा दी. आख़िरकार सरकार को झुकना पड़ा. लोकसभा में ही रिपोर्ट पेश हुई. अब बहस जारी है कि आरक्षण कहां से दिया जाए. सबकी अपनी राय है, पर अली अनवर साफ़ कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वह 8.4 फ़ीसदी आरक्षण उस 27 फ़ीसदी में से दे, जो पहले से ओबीसी को दिया गया है. वह यह भी कहते हैं कि चूंकि यह ग़रीबों का मसला है, इसलिए मज़हब की दीवार हटाकर सभी को दलित श्रेणी में शामिल कर देना चाहिए. वैसे भी हमारा संविधान धर्म आधारित राजनीति की इजाज़त नहीं देता. अली अनवर ने इस अभियान की शुरुआत ज़रूर की, तेवर भी आक्रामक अपनाए, पर उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि आरक्षण के मुद्दे पर देश–समाज में अशांति फैले. अनवर कहते हैं कि वह अमन के पैरोकार हैं और इन सिफ़ारिशों को लागू करवाने की ज़द्दोज़हद भी इसलिए है कि देश में ख़ुशहाली क़ायम रहे. क्योंकि, जब देश का ग़रीब और दलित तबका तरक़्क़ी करेगा, तभी देश में अमन और चैन क़ायम रह सकेगा. अली अनवर अंसारी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रंगनाथ मिश्र कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करवाने की ख़ातिर कमर कसकर तैयार है. रिपोर्ट पेश होने के बाद अली अनवर अंसारी की ज़िम्मेदारियां और बढ़ गई हैं. उनकी नज़र इस बात पर है कि अब सरकार का रवैया इस रिपोर्ट पर क्या रहता है. बहस और विवादों में फंसाकर सरकार इस रिपोर्ट को टालने का तिकड़म न कर दे.

बहरहाल जिस मसले को अली अनवर अंसारी ने अपने बूते पेश करवाया, उसे अंजाम तक पहुंचाने की हर लड़ाई लड़ने को वह पूरी तरह तैयार हैं.

रुबी अरुण
ruby@chauthiduniya.com

सफ़र के मुश्किल से ढ़ाई घंटे गुज़रे थे कि उनकी गाड़ियां कांकेर पुलिस द्धारा रोक ली गईं. हुक्म हुआ कि सभी लोग गाड़ियों से बाहर आएं, वरना गोली मार दी जाएगी.

इंसाफ़ की आवाज़ पर पाबंदी

तलाशी के नाम पर पुलिस द्धारा बस से जबरन उतारे गए प्रतिनिधियों का दल

अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हुए पदयात्री

आदियोग

अपनी मर्ज़ी की मालिक हो चुकी सरकारें ख़ुद के गिरहबान में ताकझांक की इजाज़त भला क्यों देंगी? वह क्यों चाहेगी कि उनके कामकाज की चीरफाड़ हो, उनकी नीयत की चिंदी-चिंदी उड़े? ज़ाहिर है, वह तो ऐसी हिमाकत को रोकने की हरसंभव कोशिश करेगी और उसे क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई का ही नाम देगी. विकास के लिए शांति चाहिए और उनके लिए शांति का मतलब मरघटी ख़ामोशी से है.

इसी कड़ी में बस्तर का हाल सुनें. दंतेवाड़ा में 14 से 26 दिसंबर तक पदयात्रा का आयोजन तय था. पदयात्रा के बाद सत्याग्रह का सिलसिला शुरू होना था, जिसका समापन अगली सात जनवरी को जन सुनवाई के रूप में होना था. जन सुनवाई में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के शामिल होने की भी चर्चा थी. वह ख़ुद भी ऐसी इच्छा रख चुके थे. 14 दिसंबर से सात जनवरी तक का यह कार्यक्रम बस्तर को जंग का मैदान बनने से रोकने के लिए बनाया गया था.

चिंता यह कि ऑपरेशन ग्रीन हंट की धमक ने आदिवासियों को आतंक और असुरक्षा के गहरे अंधेरे में धकेल देने का काम किया है. नतीजा यह कि गांव के गांव उजड़ रहे हैं. बेशक़, पदयात्रा के ज़रिए यह जायज़ा लिया जाना था कि माओवादियों को खदेड़ने की सरकारी मुहिम में ग़रीब आदिवासियों ने अब तक क्या कुछ झेला, क्या कुछ खोया. लेकिन पदयात्रा का पहला मक़सद सदमे और बेगानेपन के ज़ख्मों की सिलाई करना था. सुरक्षाबलों और सलवा जुडुम के वहशी पराक्रमों से डर-सहमे आदिवासियों को यह भरोसा दिलाना था कि संकट की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं, अमन और इंसाफ़ के पैरोकार उनके साथ हैं. पदयात्रा आदिवासियों में यह जज़्बा और हौसला भरने के लिए होनी थी.

इसी ताक़त से जन सुनवाई को सचमुच जन सुनवाई का दर्ज़ा दिया जा सकता है. सात जनवरी को आयोजित जन सुनवाई की कामयाबी इसी से नापी जानी थी. वरना तो छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक में देखा यही गया है कि विकास बनाम विनाश से जुड़ी जन सुनवाइयां दरअसल सरकारी ढोंग से अधिक नहीं रही हैं. उनका आयोजन परियोजना स्थल से कहीं दूर और सुरक्षा के चुस्त बंदोबस्त के साथ होता रहा है, जिसमें भागीदारी के लिए भाड़े के या बंधुआ लोग ढोकर लाए जाते हैं और जिसमें प्रभावित लोगों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती या भय-प्रलोभन जैसे हथियारों से उनकी बोलती बंद कर दी जाती है. विकास के मोहक नज़ारों की भावी तस्वीर पेश की जाती है. चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज़ पर पूरी कार्रवाई घंटे-डेढ़ घंटे में निपटा दी जाती है और जन सुनवाई कामयाब हो जाती है. लेकिन सात जनवरी की जन सुनवाई में तो जनता का सिक्का चलता. आदिवासी अपनी दर्दभरी दास्तान बयां करते. उनकी दास्तान ख़ुद में सवाल होती कि यह कैसा विकास है, जो पहले से ग़रीब लोगों को और अधिक ग़रीब बना देने की जिद पर तुला हुआ है. कल्याणकारी सरकार किसकी है, किसके हितों के लिए है. क्या उनके घर और फ़सलें आग के हवाले हो जाने के लिए अभिशप्त हैं. किसके इशारे पर और किस गुनाह के लिए उन्हें अपमानित-प्रताड़ित और यहां तक कि शव में बदल दिया जाता है. महिलाओं के शरीर को मर्दानगी का जौहर दिखाने का मैदान बनाया जाना कब थमेगा. उनकी दास्तान ही यह मांग करती कि उन्हें उनकी ज़मीन, संस्कृति और सामाजिक तानेबाने से बेदख़ल न किया जाए. सुरक्षाबलों पर लगाम कसे और सलवा जुडुम पर रोक लगे. मुनाफ़े की लूट के लिए क़ुदरत के नायाब तोहफ़ों के साथ छेड़छाड़ और उसका व्यापार बंद हो.

यह डॉ. रमन सिंह की सरकार को भला कैसे हजम होता? वह तो कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाने के लिए आतुर रहती है. लोगों के भारी विरोध के चलते उड़ीसा और झारखंड में आर्सेलर मित्तल को ज़मीन हासिल करने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है, जिसके कारण उसकी एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं अधर में फंस गई हैं. ऐसे में अभी हाल में कंपनी ने कर्नाटक का रुख़ करने के बाद छत्तीसगढ़ की ओर ताका तो प्रतापगढ़ के पुराने जमींदार ठाकुर साहब चहक कर बोले, हमारी सरकार हर निवेशक का स्वागत करेगी और उनका काम आसान करेगी. वैसे, क्या उलटबांसी है कि मुख्यमंत्री चाउरवाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, हालांकि उनका धान का कटोरा अकाल की लगातार मार से ख़ाली होता जा रहा है.

ख़ैर, जन सुनवाई से राज्य सरकार की प्रभुता पर आंच आने का ख़तरा था. पदयात्रा से हक़ और इंसाफ़ की आवाज़ बुलंद होती तथा उससे जन प्रतिरोध की आग को हवा मिलती. हुआ वही, जिस बात का अंदेशा था. सरकार ने पदयात्रा के आयोजन पर ही पानी फेर दिया. 12-13 दिसंबर को रायपुर में यौन हिंसा और सरकारी दमन विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ था. सम्मेलन ने यह तस्वीर खींची और उस पर चिंता ज़ाहिर की कि माओवाद के सफ़ाए के नाम पर किस तरह आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है. इसके लिए हत्या, लूट और आगजनी का बर्बर खेल खेला जा रहा है तथा आदिवासी महिलाओं को यौन हमले का निशाना बनाया जा रहा है. सम्मेलन ने उन महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिन्होंने ख़ौफ़ और शर्म से निकल कर अपने साथ हुए बलात्कार को जगज़ाहिर किया और इंसाफ़ की मांग की.

इसी कड़ी में सम्मेलन के आख़िरी दिन यानी 13 दिसंबर को रात 10 बजे 39 प्रतिनिधि दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए. इस जत्थे में छह पुरुषों को छोड़कर बाक़ी सभी महिलाएं थीं. यह जत्था 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था. सफ़र के मुश्किल से ढ़ाई घंटे गुज़रे थे कि उनकी गाड़ियां कांकेर पुलिस द्वारा रोक ली गईं. हुक्म हुआ कि सभी लोग गाड़ियों से बाहर आएं, वरना गोली मार दी जाएगी. इसके बाद गाड़ियों और उस पर लदे हरेक सामान की तलाशी ली गई. कुछ हाथ नहीं लगा तो नाम-पते नोट किए गए और उन्हें छोड़ दिया गया.

लेकिन समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई थी. बीस मिनट बाद उन्हें फिर रोक लिया गया. जत्थे को लेकर आई गाड़ियों के जो काग़ज़ात पिछली जांच में सही निकले थे, वे नई जांच में अधूरे क़रार दिए गए. ड्राइवरों को डराया-धमकाया गया. नतीजे में उन्होंने आगे जाने से इंकार कर दिया और अपनी गाड़ियां लेकर वापस हो गए. सुबह तीन बजे के क़रीब जत्थे को जगदलपुर जा रही दो बसों में जगह मिली. मुसाफ़िरों की तलाशी के बहाने इन बसों को भी दो जगह रोका गया. लेकिन पुलिस जांच का पिंड अभी भी नहीं छूटा. दो घंटे के सफ़र के बाद जगदलपुर से लगभग सौ किलोमीटर पहले बसों को एक बार और रुकने का हुक्म मिला. 39 लोगों के जत्थे को उतार कर बस को आगे रवाना कर दिया गया. जांच-पड़ताल का नाटक एक बार फिर चालू हुआ. प्रतिनिधियों की एक नहीं सुनी गई. तब तक सुबह के छह बज चुके थे. जत्थे के एक सदस्य ने प्रदेश के पुलिस प्रमुख विश्वरंजन से फोन पर बात की. जवाब मिला कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है और वह जत्थे को रोके जाने का कारण जानने के बाद ही कुछ कर सकते हैं.

दो घंटे बाद पुलिस अधीक्षक पधारे और जत्थे को यह समझाने की कोशिश करने लगे कि उन्हें कतई रोका नहीं गया है, यह तो महज़ रुटीन चेक का हिस्सा है और वे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं. पुलिस तो इस जत्थे और ख़ासकर इसकी महिला सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. पदयात्रियों का विरोध करने के लिए बीच रास्ते में पांच हज़ार आदिवासी एकत्र हैं. ऐसे में उनका आगे बढ़ना ठीक नहीं. इससे शांति भंग होगी और पुलिस नहीं चाहती कि उनके साथ कोई अनहोनी घटे. जमावड़े की यह ख़बर सच थी.

बावजूद इसके जत्थे ने जगदलपुर जाने और मीडिया के सामने पूरे मामले का ख़ुलासा करने का फ़ैसला किया, लेकिन किसी बस में उन्हें जगह नहीं दी गई. यह मनाही पुलिस के इशारे पर की गई. इसी बीच मोटर साइकिलों से सलवा जुडुम के तमाम कार्यकर्ता आ धमके और थोड़ी ही देर में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी हथियार लहराते हुए इकट्ठा हो गए. एक मीडियाकर्मी ने जत्थे के सामने यह हक़ीक़त बयान की कि इलाक़े की पुलिस बहुत सख्त है और इसलिए यहां सच पर तगड़ा पहरा है.

चिंता यह कि ऑपरेशन ग्रीन हंट की धमक ने आदिवासियों को आतंक और असुरक्षा के गहरे अंधेरे में धकेल देने का काम किया है. नतीजा यह कि विस्थापन की भगदड़ बेतहाशा फैल रही है, गांव के गांव उजड़ रहे हैं.

यह नाटक तीन घंटे चला. इस दौरान थाने का शौचालय इस्तेमाल करने तक की इजाज़त नहीं दी गई.

आख़िरकार, लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए जत्थे ने वापस लौटने का फ़ैसला किया और रायपुर के लिए बस पकड़ी. बस कांकेर के स्टैंड पर रुकी तो कोई 15 लोगों ने उसे घेर लिया. उनके हाथों में प्ले कार्ड थे और वे माओवादियों के ख़िलाफ़ नारे लगाने लगे. बस किसी तरह स्टैंड से बाहर निकली तो उसे बीच बाज़ार में भी रोका गया. बस का टायर पंक्चर कर दिया गया और यह काम उसने किया, जो ख़ुद को एक हिंदी दैनिक का प्रतिनिधि बता रहा था. वैसे भी इस अख़बार की कुल छवि भाजपा के अनौपचारिक मुखपत्र और सलवा जुडुम समर्थक वाली है. इस हंगामे के बीच दो फोटोग्राफर बस में चढ़े और हरेक की तस्वीर खींची गई.

ख़ैर, जत्था किसी तरह रायपुर पहुंचा. आनन-फानन में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपाई हुड़दंगी भी एकत्र हो गए और नारे लगाने लगे- माओवादियों के समर्थकों को गिरफ़्तार करो. इस हंगामे के दौरान पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन चुप रही. यह भांपकर कि अमन और इंसाफ़ के पैरोकारों पर हमला भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मज़दूर कार्यकर्ता समिति) ने अपने मज़दूर साथियों को जुटा लिया. इन्हीं मज़दूरों की घेराबंदी के बीच इस जत्थे को सुरक्षित भारत जन आंदोलन के सूत्रधार प्रो. बी डी शर्मा के आवास ले जाया गया. प्रसंगवश, भाजपा के योद्धाओं के निशाने पर प्रो. बी डी शर्मा भी रहे हैं. गांधीवाद से प्रभावित प्रो. बी डी शर्मा रिटायर्ड आईएएस हैं और भारत सरकार के अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं. वह दिल्ली में रहते हैं और रायपुर में उनका ख़ाली पड़ा आवास आंदोलनकारियों को आश्रय देने के लिए हमेशा खुला रहता है.

पदयात्रा वनवासी चेतना आश्रम के हिमांशु कुमार की अगुवाई में निकलनी थी. इसे रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन और सलवा जुडुम ने हरसंभव तरीक़े आज़माए. ज़रूरत पड़ने पर अक़्सर शैतान भी पवित्र मंत्रों का जाप करने लगते हैं. सलवा जुडुम ने भी यही किया. गांधीवाद की दुहाई दी और पदयात्रा के विरोध में रैली करने के लिए 10 दिसंबर का दिन चुना. रैली को सफल बनाने के लिए पुलिस भी जुटी. सलवा जुडुम मानव अधिकारों का अपहरण करने के मामले में कुख्यात है, इसलिए उसने रैली के आयोजक के तौर पर अपने छाया संगठन को पैदा किया-दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमान मंच, यानी नई बोतल में पुरानी शराब.

इस तरह मानवाधिकार दिवस के मौक़े पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमान मंच उर्फ सलवा जुडुम-2 ने रैली निकाली. इसमें भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस के लोगों ने भी बराबर की शिरकत की. रैली में मानव अधिकारों की हिमायत कर रहे लोगों और उनके संगठनों को कोसा गया. उन्हें विकास और शांति का दुश्मन, आदिवासियों के हितों में बाधक और माओवादियों का समर्थक बताया गया. फ़ैसला किया गया कि गांधीवादी तरीक़े से पदयात्रा का विरोध किया जाएगा. इसी दिन बिलासपुर हाईकोर्ट में सलवा जुडुम के ख़िलाफ़ दायर बलात्कार के मामले की सुनवाई भी हो रही थी और दंतेवाड़ा में आदिवासियों के स्वाभिमान का बेहूदा राग अलापा जा रहा था.

इधर रैली हुई और उधर पदयात्रा की तैयारियों में जुटे आदिवासी कार्यकर्ता कोपा कुंजाम और उनके वकील अलबन टोप्पो को गिरफ़्तार कर लिया गया. दोनों को बुरी तरह पीटा गया. ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़े अलबन को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन कोपा पर हत्या का आरोप मढ़ दिया गया. दंतेवाड़ा पहुंच कर पदयात्रियों को जिस धर्मशाला में ठहरना था, कलेक्टर के आदेश पर उसकी बुकिंग रद्द करवा दी गई. हिमांशु कुमार का आश्रम पहले ही बुलडोज़रों से रौंदा जा चुका है. तबसे वह और उनके साथी अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं. अचानक पुलिस को उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी. सुरक्षा दिए जाने की पेशकश हुई, जिसे हिमांशु कुमार ने फौरन ठुकरा दिया. फिर भी 14 दिसंबर को कैंप के बाहर सादे कपड़ों में ज़बरन पुलिस तैनात कर दी गई या कहें कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया. बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बजेगी.

बहरहाल, पदयात्रा नहीं हो सकी. बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि पदयात्रा नहीं होने दी गई.

feedback@chauthiduniya.com

फ्लू में भी लाभकारी
कासमधु®

आयुर्वेदिक डाक्टर का बनाया हुआ फार्मूला
खांसी, नजला, जुकाम के लिए
आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का योग
- कासमधु एल्कोहल रहित है। यह फेफड़ों व गले की नली में जमें बलगम को पतला करके बाहर निकालता है।
- सूखी व बलगमी खांसी में तुरन्त राहत पहुँचाता है।
- यह नजला व जुकाम में भी गुणकारी है।
- बच्चों के लिए भी सुरक्षित है।
43 YEARS OF TRUST HEALTH CARE
ISO 9001 : 2000 & G.M.P. Certified Co
Mfd. by : TULISON® PHARMA
118H, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007
Helpline : 011-23697278, 23694235 Fax : 011-23693500 E-mail : tulisonpharma@rediffmail.com Website : www.kasmadhu.in
Dealers : ● DELHI : Green Cross Herbals : 9899161855, ● U.P. : Ankit Enterprises, Noida : 9868416900, ● HARYANA : Medicine House, Panipat : 2648805, G.M. Medicine Centre, Rohtak : 256023, Gupta Pharma, Gurgaon : 9818564820, ● PUNJAB : Mukim Medical Agency, Ludhiana : 9417215515, Sh. Mukut Krishna, Bhatinda : 9463628512, Prakash Aushdhalaya, Chandigarh : 9888076156, Shiva Medical Agencies, Panchkula : 9872333733, Dinesh Pharma, Pathankot : 9855333755, Barumal Bhagwandas, Patiala : 9888069321 ● UTTRANCHAL : Tayal Agencies, Haridwar : 223085, Hitkari Vastu Bhandar, Dehradun : 2654802, Priya Sales, Haldwani : 9837543362, ● M.P. : Matadeen Medicos, Gwalior : 4077083, ● H.P. : Pittamber Medical Agencies, Kangra : 9816066189, Happy Medical Store, Una : 9418497477, Aaree Medical Agency, Joginder Naagr : 222127, ● RAJASTHAN : Aggarwal Ayurvedic & Medicals, Jaipur : 9351584411, Bhikha Ram Ram Dayal, Dholpur City : 9414584974 ● MAHARASTRA : Mumbai : Mitoba Biotech : 9820661700, ● THANE : Paras Medico : 9821061098, Rajesh Medical & Gen Store : 25449697 ● AKOLA : Chaudhary Ayushdhyala : 9422893089.

माया‌वती ने उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर छोटे राज्य बनाने की बात कही है. उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की बात कह कर सत्ता के गलियारे में सनसनी फैला दी है.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

बुंदेलखंड को राज्य बनाने के नाम पर सियासत

फोटो–पीटीआई

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा कर दिया है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उन्होंने बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की. बसपा यह मांग कई सालों से कर रही है. मार्च 2008 में मायावती ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की बात कही थी. उन्होंने दोनों क्षेत्रों के लोगों से अपील की कि वे अलग राज्य बनाने की अपनी मांग केंद्र के समक्ष जोरदार तरीके से रखें. मायावती ने कहा कि यदि केंद्र बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर सहमत हो तो वह विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव लाने की कोशिश करें. उन्होंने तर्क दिया कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रबंधन करने के लिए इसे बांटना ज़रूरी है.

खंड–खंड नहीं, अखंड बुंदेलखंड चाहिए. जब तक हमें पूरा बुंदेलखंड नहीं मिलता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा. यह बात बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बुंदेला ने चौथी दुनिया से कही. उन्होंने मायावती के बुंदेलखंड को लेने से इंकार करते हुए कहा कि हमें महाराजा छत्रसाल की सीमाओं वाला बुंदेलखंड चाहिए. 1948 में गृहमंत्री सरदार पटेल के साथ एक मसौदे पर बुंदेलखंड के 35 राजा–रजवाड़ों के साथ समझौता हुआ था. इस समझौते में बुंदेलखंड राज्य की सीमा तक तय हो गई थी, लेकिन संधिपत्र को लागू नहीं किया गया. बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की जाएगी.

बुंदेला ने कहा कि बुंदेलियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ. उन्हें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछवाड़े के रूप में बांटकर सारी गंदगी वहीं उड़ेल दी गई. इसी कारण आज बुंदेलखंड बीमार और बेबस है. खनिज और पुरातत्व संपदा से परिपूर्ण इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं. खनिज रॉयल्टी के रूप में सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये देने वाला यह क्षेत्र ख़ुद अपने विकास के लिए कटोरा लेकर खड़ा है. इतनी नाइंसाफ़ी तो किसी के साथ नहीं होती. हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी मूर्तियां और हमारी श्रमशक्ति का दोहन तो हो रहा है, लेकिन इसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है. बच्चे शिक्षा के अभाव में भटक रहे हैं. बेरोज़गारों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है. बुंदेलखंड राज्य बन जाने से हमें प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपने विकास का मॉडल चुनने का मौक़ा मिलेगा. लखनऊ से निर्देश आते हैं कि बुंदेलखंड में केले की खेती की जाए, लेकिन यहां पानी नहीं है. अब किसान बेचारा क्या करे? लेकिन अनुदान के खेल में काग़ज़ों पर केले की खेती होती है और अंगूर उगाए जाते हैं. यही हाल लगभग सभी सरकारी योजनाओं का है. बुंदेलखंड के बदहाल और बेहाल होने की असली वजह सही योजनाओं का न होना है. विकास के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बुंदेलखंड का शोषण पिछले छह दशकों से होता रहा है. जो बुंदेलखंड आजादी की लड़ाई में सबसे आगे था, वही बुंदेलखंड अपनी बदहाली, भुखमरी, सूखे और बेरोज़गारी के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है. विकास योजनाएं तो 63 सालों से लगातार बुंदेलखंड के नाम पर आती रहीं, पर सरकारों में दूसरे क्षेत्रों का वर्चस्व होने की वजह से उनका लाभ कभी बुंदेलखंड को नहीं मिला. यदि आंकड़ों पर विश्वास करें तो 62 प्रतिशत लोग बुंदेलखंड से पलायन कर चुके हैं. बुंदेलखंड राज्य की मांग 1948 से चल रही है. टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में मधुकर पत्र का बुंदेली राज्य अंक निकालकर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, जिसका नेतृत्व 1960 में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, पंडित ब्रजकिशोर पटेरिया, तत्कालीन विधायक डालचंद जैन एवं तत्कालीन मंत्री नरेंद्र सिंह जूदेव ने किया. 1968 में सागर (मध्य प्रदेश) में बुंदेलखंड राज्य के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सम्मेलन तत्कालीन मंत्री नरेंद्र सिंह जूदेव, साहित्यकार डॉ. बशंदावनलाल वर्मा, तत्कालीन विधायक डालचंद जैन एवं पूर्व गृहमंत्री बृजकिशोर पटैरिया के नेतृत्व में हुआ था. इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि उदल गरजे दसपुरवा में, दिल्ली में कांपे चौहान को फलित करने के लिए सभी को एक झंडे के नीचे आना होगा, लेकिन भोपाल के राजधानी बनते ही बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को उतनी गति नहीं मिल पाई, जितनी ज़रूरत थी, बुंदेलखंड राज्य के लिए झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना और सागर में कभी तेज तो कभी धीमी गति से आंदोलन चलता रहा.

पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण नायक, तत्कालीन विधायक देव कुमार यादव एवं कामता प्रसाद विश्वकर्मा की बुंदेलखंड प्रांत निर्माण समिति, विधायक एवं अब मंत्री बादशाह सिंह की इंसाफ़ सेना और बुंदेलखंड विकास सेना समय–समय पर आंदोलन करती रही हैं. 1989 में शंकर लाल मल्होत्रा के नेतृत्व में नौगांव छावनी में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के साथ ही आंदोलन ने और गति पकड़ी. फ़िल्म अभिनेता एवं कांग्रेस नेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में चित्रकूट से खजुराहो तक जनजागरण यात्रा की जा रही है. तिंदवारी (बांदा) के विधायक विशंभर प्रसाद निषाद बुंदेलखंड राज्य का समर्थन विधानसभा के अंदर और बाहर पूरे जोशोखरोश से करते हैं. वहीं भाजपा न तो हामी भर पा रही है और न ही वह इन्कार कर पाने की स्थिति में है.

खनिज संपदा के लिए मशहूर बुंदेलखंड के अकेले पन्ना जनपद से ही केंद्र सरकार को 700 करोड़ और मध्य प्रदेश सरकार को 1400 करोड़ रुपये बतौर राजस्व प्राप्त होते हैं. राजा बुंदेला कहते हैं कि बुंदेलखंड का आमजन बदहाली और बेबसी का शिकार है. संपन्न एवं मध्यम वर्ग का किसान क़र्ज़, ट्रैक्टर की किस्त और नमक–रोटी न जुटा पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है. संपन्न एवं मध्यम वर्ग के किसानों की अगर यह हालत है तो ग़रीब एवं भूमिहीन परिवारों की हालत क्या होगी, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है. कांग्रेस के झांसी ज़िलाध्यक्ष सुधांशु त्रिपाठी कहते हैं कि बुंदेलखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त है. दस साल से अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारकों को राशन नहीं मिल रहा है. बुंदेलखंड में भुखमरी की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं. ग़रीब एवं वंचित वर्ग के लगभग 40 प्रतिशत लोगों का काम की तलाश में पलायन इसका प्रमाण है.

दो दशक से बुंदेलखंड राज्य मुक्ति मोर्चा मुहिम चला रहा है. इसी के तहत चित्रकूट से पैदल यात्रा शुरू हुई. यूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र दो राज्यों में विभाजित है–उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, लेकिन भू–सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र एक–दूसरे से विभिन्न रूपों में जुड़ा हुआ है. रीति–रिवाजों, भाषा और विवाह संबंधों ने इस एकता को मजबूत कर दिया है.

उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर और जालौन के अलावा इस क्षेत्र में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, पन्ना, दमोह, सतना और गुना जैसे ज़िले भी शामिल हैं. बुंदेलखंड के बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात और मध्य प्रदेश के 21 ज़िले आते हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के योजना आयोग द्वारा घोषित बुंदेली पिछड़े क्षेत्र को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य गठित किया जा सकता है.

कभी अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार बना बुंदेलखंड खंड–खंड होकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहनुमाओं के आगे कटोरा लेकर खड़ा है. यहां के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें? सत्ता पाते ही बुंदेलखंड के तथाकथित नेता मंत्री पद के मोहपाश में ऐसे जकड़ जाते हैं कि उन्हें अपनी मिट्टी का क़र्ज़ याद नहीं रहता. लालू यादव और नीतीश कुमार को अपनी मातृभाषा बोलने में तनिक भी शर्म नहीं आती, लेकिन बुंदेली राजनेता दिल्ली जाते ही अंग्रेजी जुबान बोलने लगते हैं और यहां के बेबस भूखे लोगों से किनारा कर लेते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अखंड बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के लिए पद यात्रा का नेतृत्व करते राजा बुंदेला

ऐतिहासिक तथ्य

बुंदेलखंड राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई. इसके संस्थापक पंचम सिंह (गढ़ कुंडार) थे. वर्ष 1128 में हेमकरण ने इसकी राजधानी ओरछा बनाई. अकबर के समय वीर सिंह बुंदेला ने इस राज्य का विस्तार किया.

- महाराजा छत्रसाल ने अपने बाहुबल के आधार पर बुंदेलखंड राज्य की पुनर्स्थापना की और तब सीमाएं चंबल, नर्मदा, यमुना और टोंस नदी की परिधि में थी.
- द्वापर युग में भी बुंदेलखंड का अलग अस्तित्व रहा. तब यह चेदि प्रदेश राजा शिशुपाल एवं दंतवक्र के अधीन था. दोनों ही श्रीकृष्ण की बुआ के पुत्र थे.
- 1955 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए इसे अलग राज्य बनाने की सिफ़ारिश की थी.

प्रस्तावित ज़िले

उत्तर प्रदेश : बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन और ललितपुर.
मध्य प्रदेश : छतरपुर, पन्ना, सतना, दतिया, टीकमगढ़, दमोह और सागर.
क्षेत्रफल : 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर (उत्तर प्रदेश में 30 हज़ार वर्ग किलोमीटर).
आबादी : लगभग 3 करोड़ 5 लाख 75 हज़ार.
समस्याएं : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने के लिए 200 से लेकर 350 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है. हाईकोर्ट के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है.
केंद्र और राज्य सरकारों को बुंदेलखंड से हर वर्ष लगभग 500 अरब रुपये राजस्व के रूप में मिलते हैं, लेकिन यहां विकास के लिए मिलने वाला बजट इसका चौथाई भी नहीं होता. उत्तराखंड के आठ ज़िलों को 425 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 350 करोड़ रुपये मिलते हैं. जबकि बुंदेलखंड के सात ज़िलों को मात्र 12 करोड़ और मध्य प्रदेश में आने वाले बुंदेलखंड के छह ज़िलों को मात्र 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित होता है.

बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाम बुंदेलखंड विकास परिषद

बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण

- 1981–82 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वी पी सिंह द्वारा गठन.
- राज्य सरकार के अधीन.
- मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष.
- निर्णय राज्य मंत्रिमंडल के समान.
- मंत्रि परिषद की अनुमति ज़रूरी नहीं.
- धन राज्य सरकार देगी.
- क्षेत्र को लाभ ऊंट के मुंह में जीरा समान.
- बीस करोड़ का बजट, मिला एक करोड़.

बुंदेलखंड विकास परिषद

- 1989–90 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ख़त्म की.
- संवैधानिक संस्था.
- अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार बाधक नहीं.
- केंद्र देगा विशेष क्षेत्र का दर्ज़ा.
- अध्ययन के उपरांत प्रदेश के औसत विकास स्तर पर धन आवंटित.
- 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से.
- शेष दस प्रतिशत राज्य सरकार देगी.

देहरादून में आईएमए के पासिंग आउट परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि नेपाल के सेना प्रमुख छत्रमान सिंह गुरूंग ने अकादमी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैन्य अकादमी बताते हुए इसकी सराहना की.

वतन के लिए मर-मिटने का जज़्बा

फोटो – पीटीआई

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड की पावन धरती से प्रशिक्षण प्राप्त करके 518 सैन्य अधिकारी राष्ट्रसेवा को समर्पित हुए. मौक़ा था देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का, जिसमें कुल 536 कैडेटों ने भाग लिया. इनमें 18 विदेशी भी शामिल थे. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के सेना प्रमुख छत्रमान सिंह गुरूंग ने परेड की सलामी ली. उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारी सेना की महान परंपरा को आगे बढ़ाएं. मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सुरक्षा का सवाल सभी राष्ट्रों के लिए सबसे अहम हो गया है, इसलिए सेना में शामिल हो रहे हर अधिकारी को इस चुनौती का मुक़ाबला करने के लिए हर समय तैयार रहना होगा.

देशप्रेम किसी बाज़ार में नहीं बिकता और यह सबको मयस्सर भी नहीं है. यह पवित्र भावना जन्मती है संस्कारों से. आईएमए ने पिछले दिनों ऐसे ही लगभग सवा पांच सौ सैन्य अधिकारी राष्ट्रसेवा में समर्पित किए, जो वतन के लिए किसी भी समय मर-मिटने का जज़्बा लेकर अपने घरों से निकले हैं.

भारतीय सेना की महान परंपरा की सराहना करते हुए गुरूंग ने कहा कि भारतीय सैन्य अधिकारी सतत समर्पित भाव से उत्कृष्ट सेवाओं द्वारा अपनी विरासत की रक्षा करें. त्याग, बलिदान, समर्पण, देशभक्ति और साहस सेना के मूल्य एवं आदर्श हैं. नए सेनाधिकारी अपने साथियों एवं कनिष्ठों के लिए प्रेरणास्रोत बनें. उन्होंने अपने प्रशिक्षण काल के स्वर्णिम दिनों को याद कर भारतीय सैन्य अकादमी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैन्य अकादमी बताते हुए इसकी सराहना की.

गुरूंग ने अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया. इस मौक़े पर उनके साथ आईएमए के कमांडेंट जनरल राजेंद्र एस सुजलाना, डिप्टी कमांडेंट ब्रिगेडियर एल के रामपाल भी थे. अगवानी परेड कमांडर एडजुटेंट कैडेट अभिषेक सिंह ने की. इस अवसर पर गुरूंग ने स्वार्ड ऑफ़ ऑनर एवं गोल्ड मेडलिस्ट कैडेट पंडित रवि शुक्ला को सम्मानित किया. हर्षवर्धन पाठक को रजत और रोहित पंडित को कांस्य पदक प्रदान किया गया. टेक्निकल कोर्स के कैडेट राकेश सिंह को रजत पदक मिला. समारोह में अतिथियों के अलावा कैडेटों के परिजनों ने भी हिस्सा लिया. उत्तराखंड ने इस बार अपने चार दर्ज़न युवा सैन्य अधिकारी राष्ट्रसेवा में समर्पित किए.

मुख्य अतिथि गुरूंग ने भारत–नेपाल संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि यह दोस्ती हम नहीं छोड़ सकते हैं. भारत के अपनापन के लिए नेपाल सदैव इसका क़र्ज़दार रहेगा. भारत–नेपाल की दोस्ती की नींव बहुत गहरी है. उन्होंने कहा कि अकेले आईएमए ने ही नेपाल को अब तक 120 योग्य सैन्य अधिकारी दिए हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भारत के साथ नेपाल के सैन्य एवं सामरिक रिश्तों में और भी गर्माहट आएगी. दोनों देशों में सैन्य स्तर पर कभी भी कड़वाहट नहीं आई और न ही कभी आने की आशंका है. नेपाली सेना सदैव भारतीय सेना से प्रेरणा लेती रही है. भारत से मिले सहयोग को नेपाल कभी भूल नहीं सकता.

स्वॉर्ड ऑफ़ ऑनर से सम्मानित कैडेट रवि शुक्ला अपनी सफलता का श्रेय पिता को देते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक सामान्य किसान होते हुए उनमें देशप्रेम का जो भाव जगाया, उसी का परिणाम है कि वह सफलता की बुलंदियों को छूते चले गए. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के ग्रामीण परिवेश में पले–बढ़े रवि कहते हैं कि उनकी मां देवकी देवी ने उन्हें सहर्ष देशसेवा के लिए समर्पित किया है. 16 दिसंबर 1987 को जन्मे रवि को पहले एनडीए में सफलता मिली और फिर आईएमए में. रजत पदक पाने वाले भगवानपुर (गुजरात) निवासी हर्षवर्धन पाठक का कहना है कि सेना देश के युवकों को एक सूत्र में बांधने का सशक्त माध्यम है. उन्होंने अपने दिवंगत पिता को बड़ी श्रद्धा से याद किया. इस अवसर पर उनकी मां बासुरी देवी उनके साथ मौजूद थीं.

सिहावर (लुधियाना) निवासी रजत पदक विजेता इक़बाल जीत सिंह का मानना है कि सेना में सेवा करने का क्रेज़ सदैव ही रहेगा. ईमानदारी से किसी भी मुक़ाम को हासिल किया जा सकता है. उत्साहित इक़बाल कहते हैं कि आर्मी इज़ द बेस्ट.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... भाजपा अध्यक्ष! ...धीर

इस पेशे से जुड़ी 10–12 लाख से ज़्यादा बाल यौनकर्मियों को क्या यह हक़ देना जायज़ होगा? बच्चियां जो काम कर रही हैं, उस पर हम क़ानून की मुहर कैसे लगा सकते हैं?

यौन पेशे को क़ानूनी मान्यता देना घातक होगा

फोटो–पीटीआई

बिमल राय

जब आप कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना पेशा है और जब आप क़ानून बनाकर इसे ख़त्म कर पाने में अक्षम हैं तो इसे क़ानूनी मान्यता क्यों नहीं दे देते? इससे आप पेशे पर निगरानी रख सकेंगे और इसमें शामिल लोगों का पुनर्वास कर सकेंगे. दिसंबर के पहले सप्ताह में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह राय ज़ाहिर की. इससे उन करोड़ों यौनकर्मियों के दिलों में उम्मीद जगी है, जो दिन के उजाले में समाज की हिकारत और रात में पुलिस, गुंडों, दलालों एवं मौसियों की चांडाल चौकड़ी का दंश झेलती हैं.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ओलेगा तेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामले (1985 एसएससी–3ए 535) में यह फ़ैसला सुनाया था कि कोई भी व्यक्ति जीविका के साधन के रूप में जुआ या वेश्यावृत्ति जैसे अवैध व अनैतिक पेशे का सहारा नहीं ले सकता. इसके बावजूद समलैंगिकता पर आए हाल के फ़ैसले और अब यौन पेशे को क़ानूनी मान्यता देने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की राय पूरी दुनिया में बदल रही फिज़ां और बुराइयां रोक पाने में क़ानून की विफलता की ओर इशारा करती है. ज़ाहिर है, कोर्ट की राय से यौन पेशे को क़ानूनी मान्यता देने की बहस फिर शुरू हो गई है. मानवाधिकार संगठनों के साथ–साथ देश के लाखों यौनकर्मी क़ानून बनाने वाली मशीनरी पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं तो दूसरा खेमा भी अपने पुराने हथियारों से लैस होकर बीच मैदान में डटा है. सवाल यह है कि इस पेशे से जुड़ी 10–12 लाख से ज़्यादा बाल यौनकर्मियों को क्या यह हक़ देना जायज़ होगा? सवाल इसलिए अहम है कि खेलने, पढ़ने और एक आम औरत की तरह पारिवारिक ज़िंदगी जीने के मौलिक अधिकार से महरूम बच्चियां जो काम कर रही हैं, उस पर हम कैसे क़ानून की मुहर लगा सकते हैं? क्या क़ानूनी मान्यता मिलने से यौनकर्मियों की संख्या अचानक बढ़ नहीं जाएगी? बीच बहस में इन सब सवालों की बौछार हो रही है. बेहतर है कि हम दोनों पक्षों की राय जान लें.

1986 में संसद में चली बहस में सांसदों ने कहा था कि जब तक समाज से लिंग भेद, विषमता, महिलाओं पर अत्याचार व अपमान दूर नहीं किया जाता, इस पेशे को ख़त्म करना संभव नहीं होगा. आज 20 साल बाद भी हालात जस के तस हैं.

यौनकर्म को क़ानूनी मान्यता और यौनकर्मियों को श्रमिक का दर्ज़ा देने की मांग के बीच वर्ष 2006 में केंद्रीय नारी एवं शिशु कल्याण विभाग ने आईटीपी एक्ट (इटपा क़ानून) में संशोधन का फ़ैसला किया. इसके लिए बनी कमेटी की मुखिया मंत्री रेणुका चौधरी की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि समाज से कटी ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां केवल यौन पेशे में आती हैं. संशोधन के मक़सद के तौर पर दो बातों का उल्लेख किया गया. पहली यह कि इस पेशे में नाबालिग लड़कियों को आने से रोका जा सकेगा और दूसरी यह कि यौनकर्मियों पर अत्याचार रोकना. इसी वजह से पहले के क़ानून की आठ और 20 नंबर की धाराएं हटाकर नई धाराएं जोड़ी गईं. इन धाराओं पर एक नज़र डालना ज़रूरी है. क़ानून की धारा 2–डी के मुताबिक़, यदि कोई ग्राहक यौनसंपर्क के लिए यौनकर्मी से मोलभाव करता है तो इसे यौनकर्मी का शोषण माना जाएगा और उसे पुलिस पकड़ लेगी. क़ानून की धारा 5–सी में कहा गया है कि यौनकर्मी चूंकि हालात की शिकार हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो ग्राहकों का है. तभी ग्राहक पर 20 रुपये से लेकर 50 हज़ार रुपये तक के जुर्माने और ढाई से छह माह तक की जेल का प्रावधान किया गया. धारा 5–सी लागू होने के बाद ग्राहक रेड लाइट एरिया में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. क़ानून की धारा 13/2 के मुताबिक़ पहले इटपा विभाग के प्रशिक्षित पुलिसकर्मी एवं अधिकारी ही नाबालिग लड़कियों को पकड़ने के लिए राउंड लेते थे. जबकि नए प्रस्तावित क़ानून के मुताबिक़ इलाक़े के थाने का कोई पुलिसकर्मी कभी भी छापा मार सकता है और वारंट के बिना ही नाबालिग लड़कियों को पकड़ सकता है.

क़ानून की धारा 2–एफ के मुताबिक़ पहले यौनकर्मी संगठित होकर एक इलाक़े में रहती थीं तो उन्हें कमर्शियल सेक्स वर्कर्स कहा जाता था. नई धारा के मुताबिक़ उन्हें कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लायटेशन कहा जाएगा. क़ानून की धारा 2–के में कहा गया है कि तस्करी के ज़रिए इस पेशे में आई यौनकर्मी के साथ कोई ग्राहक मोलभाव करता है तो उसे भी तस्करी का एक रूप माना जाएगा. यौनकर्मियों का सवाल है कि ग्राहक कैसे समझेगा कि कौन सी युवती तस्करी के ज़रिए लाई गई है और कौन नहीं? क़ानून की धारा 5–ए के मुताबिक़ कोई महिला अगर रोज़गार के लिए इस पेशे में आना चाहती है तो उसे भी तस्करी का रूप माना जाएगा.

क़ानून की पुरानी धाराओं की तुलना नई धाराओं से करते हुए यौनकर्मियों के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने दिल्ली में एक विशाल रैली की और तब सांसदों का मानवाधिकार प्रेम जागा. परिणाम यह निकला कि क़ानून मंत्रिमंडल में पारित नहीं हुआ. यौनकर्मियों का कहना था कि इटपा में संशोधन नामक नागनाथ भले ही ठंडे बस्ते में चला गया, पर सांपनाथ के रूप में मौजूद धाराएं 3,1,4,8,18 और 20 जस की तस रह गईं. अब यौनकर्मी इनके ख़िलाफ़ मैदान में उतर चुकी हैं.

क़ानून की धारा 3/1 में प्रावधान है कि अगर कोई मकान मालिक किसी यौनकर्मी को घर किराए पर देता है तो उसे भी अभियुक्त माना जाएगा. सजा रखी गई है ढाई लाख रुपये तक का जुर्माना और सात साल तक की क़ैद. यौनकर्मियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो दो–तीन मकान मालिकों के गिरफ़्तार होने के बाद कोई भी यौनकर्मियों को कमरा किराए पर नहीं देगा. इससे बिना किसी बाधा के यौनकर्मी इलाक़े से हटाई जा सकती हैं. बहुत सारे इलाक़ों में मकानों की क़ीमत किराए की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है और वे यौनकर्मियों को हटाना चाहते हैं. क़ानून लागू होने के बाद वे आसानी से विस्थापन का केस जीत जाएंगे.

क़ानून की धारा–4 में कहा गया है कि 18 साल से ऊपर की यौनकर्मियों के पैसे का कोई उपयोग करता है तो उसे भी अपराधी माना जाएगा. सवाल है कि उनका पैसा तो उनकी संतानें ही खाती हैं. तो क्या उनकी संतानें माध्यमिक या उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त कर नई ज़िंदगी शुरू कर पाएंगी? धारा 18 में कहा गया है कि किसी इलाक़े के 200 मीटर के दायरे में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और अस्पताल आदि रहने से कार्यपालक मजिस्ट्रेट यौनकर्मियों के घरों को सील कर सकते हैं. यौनकर्मियों का पक्ष यह है कि पुरानी यौनबस्तियों के पास अगर भू–माफ़िया और प्रोमोटर धार्मिक स्थल बना देते हैं तो यौनकर्मियों को बेदख़ल करना कितना आसान हो जाएगा.

धारा 20 में कहा गया है कि यदि किसी रेड लाइट इलाक़े के आसपास रहने वाले लोग यौनकर्मियों के अत्याचार की शिकायत करते हैं तो शिकायत की कॉपी लेकर पुलिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और यौनकर्मियों को इलाक़े से हटाने का काम आसान हो जाएगा. यौनकर्मियों के मुताबिक़ इस तरह अगर जबरन इलाक़े ख़ाली होंगे तो शहर की यौनकर्मी क़स्बों, उपनगरों के लॉज व होटलों की शरण लेंगी. इन सब इलाक़ों में यौनकर्मियों के साथ पशुओं जैसा सलूक होगा. इस तरह मानव तस्करी रोकने के लिए बना यह क़ानून रिश्वत कमाने का एक बड़ा ज़रिया बन जाएगा.

यौनकर्मी आईटीपी एक्ट की धाराओं–3,1,4,8,18 और 20 को ख़त्म करने की मांग कर रही हैं. वे सोचती हैं कि अभी अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस और गुंडों का अत्याचार बढ़ेगा, कम नहीं होगा. आईटीपी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को रोकने के लिए दुर्वार महिला समन्वय समिति के बैनर तले कोलकाता, पटना और भुवनेश्वर में यौनकर्मियों ने रैलियां निकाली थीं. अब संस्था के प्रतिनिधि दिल्ली में सांसदों से मिलकर इटपा की छह धाराओं को हटाने की मांग को लेकर लाबिंग कर रहे हैं. यह साबित हो चुका है कि यौन पेशे से जुड़े अपराधों को रोकने में भारतीय दंड संहिता से कहीं ज़्यादा कारगर आईटीपी एक्ट है. समस्या क़ानून लागू करने को लेकर है, यौनकर्मियों के प्रति नज़रिए को लेकर है. गृह मंत्रालय की सिफ़ारिश है कि इन मामलों की छानबीन और अपराध तय करने में सहानुभूति का रवैया अपनाना चाहिए. छापे के दौरान दो स्वतंत्र लोग होने चाहिए, जिनमें इलाक़े की एक महिला होनी चाहिए. यही नहीं, तलाशी या छापे में एक महिला पुलिस अफसर साथ होनी चाहिए. आईटीपी एक्ट की धारा 15(6–ए) में साफ़ कहा गया है कि पकड़ी गई यौनकर्मी से पूछताछ महिला कांस्टेबल ही करेगी और इस दौरान एक स्वयंसेवी संस्था की महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए. पकड़ी गई यौनकर्मी के साथ पीड़िता जैसा व्यवहार होना चाहिए, न कि अपराधी जैसा. उक्त सारी सलाहें हैं, पर केंद्र की भूमिका भी सीमित है, क्योंकि राज्य सरकार की पुलिस के पास अपना एक क़ानून होता है. समझा जा सकता है कि क्यों यौनबस्तियों के दायरे में आने वाले थानों में तबादले को प्रमोशन माना जाता है और इसके लिए लाखों की रिश्वत क्यों दी जाती है? इसीलिए यौनकर्मी ख़ुद के लिए श्रमिक का दर्ज़ा चाहती हैं, ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें. मानवाधिकार की नज़र से उनकी मांगें भले ही जायज़ लगती हों, पर इसमें कोई शक़ नहीं कि इस पेशे को क़ानूनी मान्यता मिलने के बाद लड़कियों के पेशे में आने का प्रवाह बढ़ेगा और समाज का नैतिक स्तर रसातल में चला जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

यौनकर्मियों ने बजाया था बगावत का पहला बिगुल

क्रांतिकारियों की भूमि रहे पश्चिम बंगाल में यौनकर्मियों ने ही अंग्रेजों के अत्याचार के ख़िलाफ़ सबसे पहले बग़ावत का बिगुल फूंका था. 1850 के दशक में क्रीमिया की लड़ाई में इंग्लैंड के कई श्रमिक यौन रोग के शिकार हो गए और अंग्रेज सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि यौनकर्मियों की वजह से ही रोग फैला है. 1864 में ब्रिटेन में यौनकर्मियों के रजिस्ट्रेशन और उनके रोग परीक्षण को बाध्यता मूलक करने के लिए संक्रामक रोगों के संबंध में एक क़ानून बना. बाद में एक अप्रैल 1869 को कोलकाता में यह 14 नंबर के नाम से कुख्यात क़ानून लागू किया गया. यौनकर्मियों ने अपनी इच्छा से माह में चार रुपये ख़र्च कर यौन रोगों की जांच करवानी शुरू की, पर जल्द ही इस जांच की हक़ीक़त सामने आ गई. हर यौनकर्मी की जांच की प्रक्रिया आदिम किस्म की और दर्दनाक थी. प्राय: सबके सामने यौनकर्मी को नंगा कर उसके यौनांग में लोहे की छड़ और पिचकारी जैसा कोई उपकरण डाला जाता था. इस प्रक्रिया से आतंकित यौनकर्मियों ने कोलकाता छोड़कर फ्रांस के आधिपत्य वाले चंदन नगर, जो अब हुगली ज़िले में है, में अपना बसेरा बनाना शुरू किया. उस समय 1418 यौनकर्मियों को पुलिस ने पकड़ा. जो यौनकर्मी भाग नहीं पाईं, उन्होंने आत्महत्या कर ली. आख़िर में 2026 यौनकर्मी अंग्रेजों के इस क़ानून की चपेट में आईं. सभी ने इस क़ानून और पुलिस के अत्याचार के ख़िलाफ़ अदालत में मामला दायर किया. इस वारदात की ख़बर विभिन्न अख़बारों में प्रकाशित होने के बाद लोग भी दो भागों में बंटे. कुछ पक्ष में थे, तो कुछ ने ख़िलाफ़त की. एक पक्ष का मानना था कि यौनकर्मी इस क़ानून को नहीं मान रही हैं और भाग रही हैं. इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ खामी है. उसी समय से उन्हें अपराधी मानने की प्रक्रिया शुरू हुई. हालांकि दूसरे खेमे के लोगों ने डॉक्टरों व पुलिस के इस तरह के अत्याचार को असभ्यता और बर्बरतापूर्ण कहा. विरोध करने वालों की संख्या बढ़ते ही अंग्रेज सरकार त्रस्त हो उठी. सरकार ने यह भी देखा कि क़ानून के लागू होने के बावजूद सैनिकों के यौन रोगों से ग्रस्त होने की दर और बढ़ गई. मजबूर होकर सरकार ने वर्ष 1888 में इस 14 नंबर क़ानून को वापस ले लिया.

यौनकर्मियों को अपराधी मानने की प्रक्रिया का दूसरा चरण वर्ष 1946 से शुरू हुआ. वर्ष 1949 में देह व्यवसाय और महिलाओं की तस्करी रोकने के लिए राष्ट्र संघ के कंवेंशन प्रोग्राम के तहत भारत में कार्रवाई शुरू हुई. 1956 में यहां सीटा क़ानून लागू हुआ. इस पर संसद में बहस हुई कि दो वयस्क लोगों के बीच यौन संपर्क रोकने के रास्ते में क्या–क्या बाधाएं हैं. संसद में एक पक्ष ने यह भी कहा कि देह व्यापार रोकने से लाभ के बदले नुक़सान ज़्यादा होगा. इसी वजह से सीटा क़ानून में इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया. इसके बाद वर्ष 1978 एवं 1986 में क़ानून में संशोधन किए गए. इसका नया नाम पड़ा पिटा या इटपा.

दर्द, जो दवा बन गया

मेरा नाम साधना मुखर्जी है. मैं रामबागान में रहती हूं. मैं 16 वर्ष की उम्र से पेशे में आई. शाम होते ही देखा कि एक आदमी अपने दोस्त से बोल रहा था कि यह औरत यहां कब आई? यहां कबसे खड़ी हो रही है? मुझे बताया गया कि यह इलाक़े का दादा है. उसका नाम लाल्टू था. उसे निहारते देखकर मैं वापस अपने कमरे में लौट आई. पीछे–पीछे लाल्टू भी आया. मैंने पानी से भरी बाल्टी उठा ली और कहा कि अब अगर एक क़दम भी बढ़ाया तो बाल्टी चला दूंगी. उसने तुरंत छुरा निकाल लिया. मगर मेरे माथे पर ख़ून चढ़ चुका था. शायद मेरा रौद्र रूप देखकर लाल्टू चला गया, पर डर मुझे था. मैं एक दूसरी लड़की के साथ उसके घर में सो गई. रात में वह आया और घर में मुझे न पाकर गालियां देता हुआ वापस चला गया. अगले दिन दोपहर का भोजन कर मैं अपनी सखी दीप्ति के साथ रास्ते की पान की दुकान पर खड़ी थी. देखा कि अचानक मेरे सामने लाल्टू खड़ा था. सबक सिखाने की नीयत से उसने छुरा निकाल लिया. दीप्ति और मैंने तुरंत उसका एक हाथ पकड़ लिया. इस झगड़े में छुरा दीप्ति के मुंह पर लग गया. गाल कट गया, दांत दिखने लगे. हम लोगों की मारामारी देखकर दूसरी लड़कियां भी आ गईं. दीप्ति को उठाकर ले जाते ही मैं उठी. पान वाले के पास पत्ते धोने के लिए बाल्टी रखी हुई थी. मैंने बाल्टी उठाई और लाल्टू के सिर पर दे मारी. ख़ून से उसका पूरा शरीर लाल हो गया. मेरा काली रूप देखकर लाल्टू और उसके दोस्त तरह–तरह की धमकियां देते हुए चले गए. मेरे मन में भय समा गया. सोचा कि कल किसी भी समय वह मुझे मारने आ सकता है. यह सोचकर हम सब डॉ. स्मरजीत जाना के पास गए, जो बाद में दुर्वार के संस्थापक बने. उनकी सलाह थी, आप लोग तुरंत एक महिला समिति का गठन करो और उस समिति की ओर से थाने के बड़े बाबू को लाल्टू के अत्याचार की चर्चा करते हुए एक ज्ञापन दो. उस पर बस्ती की सारी यौनकर्मियों के दस्तख़त और अंगूठे के निशान लगवा लेना. मैं, दीप्ति पाल, मुन्नी सिंह एवं कमला सिंह डॉ. जाना से चिट्ठी लिखवाकर ले गए और सबके हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान भी लगवाए. रामबागान की समस्त यौनकर्मी शाम को ज्ञापन देने थाने गईं. एक पुलिस वाले से बकझक की आवाज़ सुनकर बड़े बाबू प्रकट हुए. हमने विस्तार से लाल्टू के अत्याचार के बारे में बताया. अगली रात ख़बर मिली कि लाल्टू गिरफ्तार कर लिया गया है. बाद में सुना कि उसे छह माह की जेल हुई. जेल से लौटने पर उसका गिरोह तितर–बितर हो चुका था. इसके बाद वह हम लोगों से नहीं लगता था. हम लोग वहां अमन–चैन से रहने लगे.

देश ही नहीं, विदेशों में भी यौनकर्मियों में जागृति लाने के लिए नाम कमा चुकी दुर्वार महिला समन्वय समिति के जन्म की यही संक्षिप्त कथा है.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

वेश्यावृत्ति अवैध है, फिर भी भारतीय शहरों और उनके बाहर यह व्यवसाय फलफूल रहा है. एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक़, पूरे देश में महिला यौनकर्मियों की संख्या दो मिलियन से भी अधिक है.

आसिफ़ अली ज़रदारी ने सेना की असाधारण शक्तियों में कटौती की बात सोची. इसके लिए उन्होंने अमेरिका को मनाया कि वह सेना की अपेक्षा सिविलियन सरकार की मदद करे.

नई विश्व व्यवस्था और बदलता नज़रिया

एम जे अकबर

जब किसी वर्ष के साथ दशक का अंत होता हो तो एक स्तंभकार की ज़िम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं. इनमें अधिकांश एक स्मृति लेख की तरह उबाऊ होते हैं, लेकिन किसी के ज़ेहन में एक असामान्य सवाल आया कि पिछले दस वर्षों में किसी चीज़ के बारे में आपने अपना विचार बदला?

जब बर्लिन की दीवार गिरी तो मैंने उत्सव मनाया. इसके अलावा 1990 के दशक में दो ग़ैर ज़रूरी वजहों, सिद्धांत और स्वार्थ के कारण सोवियत संघ का पतन हुआ तो भी मैं ख़ुश था. यदि पीछे मुड़कर देखें तो दूसरा पहले की अपेक्षा अधिक बोधगम्य है. एक पत्रकार होने के नाते कहूं तो पहले में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का निहित स्वार्थ था. इसके विपरीत सोवियत शासन उबाऊ था. लेकिन यह तो पिछली सदी की बात है. आज वहां एक खालीपन है, जहां कभी सोवियत संघ की परछाई फैली थी, जिसने अपने ही नागरिकों को घेरेबंदी में रखा था. और, अभी तक अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए एंग्लो-अमेरिकन कट्टरपंथियों में पर्याप्त भय पैदा किया. यदि क्रेमलिन में स्टालिन या यहां तक कि ब्रेज़नेव का शासन होता तो 2003 में बुश और ब्लेयर ने इराक में जो किया, उसके लिए क्या उन्हें इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाती?

सिद्धांतों में मेरा विश्वास एक बेवकूफ़ी थी. सिद्धांतों का पालन सिर्फ़ सद्दाम हुसैन के लिए होता है और टोनी ब्लेयर के लिए नहीं तो सिद्धांत एक नपुंसक मानदंड है. कुछ शासक अपने छलकपट से चतुराईपूर्वक उदासीन बने रहते हैं, यही काम ब्लेयर ने इराक मसले पर किया. एक राजनेता जिसने अपनी पार्टी की इच्छा के विपरीत ब्रिटेन को युद्ध में धकेला, उसी ने ब्रिटिश टेलीविज़न को कुछ दिन पहले बताया कि यदि वह जन विनाश के हथियार के छल में पकड़े जाते तो कोई दूसरा बहाना बना लेते. अब ब्लेयर यह स्वीकार करते हैं कि हम सभी यह जानते थे कि इराक युद्ध की जो वजह बताई जा रही है, वह इसकी असलियत कभी थी ही नहीं.

इत्तेफ़ाक़ से राष्ट्रपति ओबामा ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार लेते समय अपने भाषण में युद्ध की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित किया. यदि इराक का युद्ध एंग्लो-अमेरिकी झूठ पर आधारित था तो वे कौन लोग थे, जिन्होंने एक अनुचित युद्ध के लिए अमेरिकी सेना का प्रतिरोध किया? ब्लेयर और बुश ने ऐसे और कितने मुल्क़ फतह करने के लिए खोजे थे, जहां उन्हें इराक की तरह किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता?

जब ओबामा ने विश्वास के साथ एक प्रस्ताव में कहा कि एक पवित्र युद्ध महज़ युद्ध नहीं हो सकता तो इसके साथ वह ख़ुद को अज्ञात क्षेत्र में ले गए. यक़ीनन वह जिहाद के मसले पर एक साथ कई विचार रख रहे थे. यह साफ़ ज़ाहिर है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ वह मुस्लिम हठधर्मिता की अपेक्षा अमेरिकी विचार के क़रीब दिखने की कोशिश कर रहे थे. इसी प्रक्रिया में उन्होंने हिंदुत्व पर हमला बोला. इसके दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत युद्ध महाकाव्य हैं. एक हिंदू यह सुनकर हैरान हो जाएगा कि भगवान राम ने लंका और श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के जो पवित्र युद्ध लड़े, वे अनुचित थे. लेकिन वे विश्वास अभी भी हमारे नैतिक मूल्यों में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं. इस तरह हम विश्वासी बने रहते हैं. ओबामा यह जानकर संभवत: हैरान हो जाएंगे कि पवित्र क़ुरान में प्रतिष्ठित योद्धा दाउद हैं, जो यहूदियों के राजा थे. दूसरे विश्वयुद्ध के प्रमुख विजेताओं में अमेरिकी और सोवियत संघ की अगुवाई वाला गठबंधन था.

इनके बीच शक्ति संतुलन एक असंतुलित रास्ता सामने लाया, जिसमें संतुलन की सारी मान्यताएं तोड़ दी गईं. इसे कार्यान्वित तो निजी एजेंडे के तहत किया गया, लेकिन इन्हें इकट्ठा किया गया था राष्ट्रीयता के नाम पर. देशभक्ति धार्मिक गतिविधियों को मज़बूती देती है. यही कहानी इराक में थी. अफ़ग़ानिस्तान में इसी कहानी का स्थानांतरण किया गया. इराक में सबसे अधिक विद्रोहियों को ही सहयोगी के तौर पर चुना गया, जहां वे अधिक समय तक रहे. साथ ही इन विद्रोहियों ने स्थानीय नेताओं की बर्बादी और अमेरिकी सेना के जाने का इंतज़ार किया. जब उन्हें मौक़ा मिलेगा तो वे अपने सांचे में इराक को ढालेंगे. अफ़ग़ानिस्तान में इतिहास और भूगोल दोनों इनके साथ हैं.

आतंकवादी डेविड कोलमैन जैसे गुमनाम लड़ाकुओं के लिए अस्पष्ट युद्ध क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र होता है. क़साब जिस तरह लगातार अपने बयान बदल रहा है, हमें उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए. हेडली लश्कर-ए-तैयबा में कहीं अधिक ऊंचे पद का ओहदेदार है. आतंकियों को तैयार करने में उसकी विशेषज्ञता ज़ाहिर है. क्या वह अमेरिकियों को डबल क्रॉस या ट्रिपल क्रास कर रहा था? (भारत के लिए कोलमैन को महज़ एक सीमा रेखा पार करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने ख़ुशीपूर्वक उसे वीज़ा दे दिया). कोलमैन ने ख़ुद को एक आवरण से ढक लिया, जिसे एक बढ़िया जासूसी की कहानी से सिला जा सकता था. वह अमेरिकी ड्रग इंफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और एफबीआई का एक ख़बरी बन गया. अब वह अमेरिकी रहमोकरम से मुंबई और अफ़-पाक (अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान) के बीच दवा व्यापार कर सकता है. शायद, हमें इस क्षेत्र को मफ़-पाक (मुंबई-अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान) कहना चाहिए.

सबसे बेहतरीन तो यह होता कि आज हमारे पास अर्द्ध समाजवादी सोवियत गणराज्य में ब्रेज़नेव जैसा शासक होता. अब हमारे पास एक ही महाशक्ति अमेरिका है, जो आक्रामक-सुरक्षात्मक दोनों स्थितियों में है. अमेरिका हमेशा अपनी ही सुरक्षा को केंद्रित करता है, चाहे इसकी भरपाई उसे सहयोगियों की ही क़ीमत पर क्यों न करनी पड़े. यह एक ऐसी नीति लगती है, जो अनुकरण करने लायक़ है.

feedback@chauthiduniya.com

वेश्यावृत्ति वैध होनी चाहिए!

रवि किशोर

हाल में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस दलवीर भंडारी और ए के पटनायक की खंडपीठ ने सरकार से इस बात पर विचार करने को कहा कि यदि वह वेश्यावृत्ति को रोक नहीं सकती तो इसे क़ानूनी वैधता दे देनी चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि महिलाओं की तस्करी रोकने की दिशा में सेक्स व्यापार को क़ानूनी मान्यता देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इससे यौनकर्मियों के पुनर्वास में भी मदद मिलेगी. एक ग़ैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जब आप यह कहते हैं कि वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना पेशा है और आप इस पर लगाम लगाने में असक्षम हैं तो आप इसे क़ानूनी मान्यता क्यों नहीं दे देते हैं? इससे आप इस व्यवसाय पर निगरानी भी रख सकते हैं. उच्चतम न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को वैध करने की सलाह देकर दुनिया के सबसे पुराने पेशे के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या इसे भारत में वैध कर देना चाहिए. इस विवाद के पक्ष और विपक्ष में लोग अपना तर्क मज़बूती से रख रहे हैं. इसकी मुख़ालफ़त करने वाले पुरज़ोर तरीक़े से अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि इससे मानव तस्करी में और अधिक इज़ाफ़ा ही होगा. जबकि इस मसले पर सकारात्मक रुख़ रखने वाले कहते हैं कि सेक्स व्यापार को वैध बनाने से भेदभाव तो दूर होगा ही, इसके अलावा जो यौनकर्मी आज ख़ुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें भी क़ानूनी मान्यता मिल जाएगी. साथ ही क़ानून को लागू करने वालों मसलन पुलिस के ज़रिए इनका होने वाला शोषण भी रुकेगा. इसे क़ानूनी मान्यता देने से एचआईवी/एड्स से लड़ने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे सेक्स वर्कर्स को एहतियाती तौर पर मेडिकल सुविधा भी मुहैया होगी.

यौनकर्मियों के अधिकारों के मसले पर पूरी दुनिया में हमेशा से विवाद रहा है. वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करने अथवा इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विशिष्ट क़ानून नहीं है. भारत में वेश्यावृत्ति से संबंधित क़ानून हैं भी, तो वे ख़ासकर महिलाओं के अनैतिक व्यापार और गर्ल एक्ट-1956, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम-1956, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम-1956 और आईटीपीए अधिनियम-1956 से संबंधित हैं. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन के लिए वर्ष 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने संसद में एक विधेयक पेश किया था. अब भारत सरकार ने एक नया क़ानून प्रस्तावित किया है, जिसके तहत यह अपराध नहीं रह जाएगा. यौनकर्मियों को कोई मकान से बाहर नहीं निकाल पाएगा. यौनकर्मियों के ग्राहकों को जेल और 50,000 रुपये तक का दंड भुगतना पड़ सकता है. उनकी आय को बंद करना ग़ैर क़ानूनी होगा. जो भी यौनकर्मियों के मकान को किराए पर उठाएगा, उसे जेल या 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा होगी. प्रस्तावित विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा. जबकि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने इस संशोधन के फ़ैसले की आलोचना की है. उसके मुताबिक़, यौनकर्मियों के ग्राहकों को दंडित करने का केंद्र का फ़ैसला किसी भी मायने में सकारात्मक क़दम नहीं है. मौजूदा क़ानून के मुताबिक़ यौनकर्मियों को ही दंडित किया जाता है, जो ख़ुद भुक्तभोगी हैं. लगभग अस्सी फ़ीसदी यौनकर्मी ग़रीबी, क़रीबियों के झांसे में आने और मानव तस्करी आदि की वजह से इस पेशे में हैं.

वेश्यावृत्ति को क़ानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इसका जवाब देना काफ़ी कठिन है. ख़ासकर तब, जबकि आप भारत जैसे देश में रहते हों. भारत में यदि किसी चीज़ का संबंध सेक्स, ख़ासकर वेश्यावृत्ति से जुड़ा हो तो इसे अनैतिक माना जाता है. और, कोई भी इस पेशे में शामिल होता है तो उसे अपराधी करार दिया जाता है. आज वेश्यावृत्ति ग़ैर क़ानूनी सिर्फ़ इसलिए है, क्योंकि यह एक राष्ट्र के सख्त नैतिक मूल्यों के ख़िलाफ़ है. वेश्यावृत्ति के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को वेश्या बनने से रोकना है. लेकिन वेश्यावृत्ति अधिनियम को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है वेश्याओं को दंडित करना. इस अधिनियम में इसका भी ज़िक्र है कि आख़िर क्यों एक महिला इस तरह की ज़ोखिम भरी जीवनशैली अपनाती हैं. जो महिलाएं वेश्यावृत्ति में हैं, वे आमतौर पर हताशा में ही इस पेशे में शामिल होती हैं. इसलिए सरकार उनके लिए कम से कम सुरक्षा का बंदोबस्त तो कर ही सकती है. वेश्याएं सामाजिक और क़ानूनी तौर पर अपनी गतिविधियों को छिपाती हैं, इसलिए भारतीय महिलाएं जो इस पेशे में शामिल हैं, उनकी सही तादाद का पता लगाना आसान नहीं है.

हालांकि वेश्यावृत्ति अवैध है, फिर भी भारतीय शहरों और उनके बाहर भी यह व्यवसाय फलफूल रहा है. एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक़, पूरे देश में दो मिलियन से भी अधिक संख्या महिला यौनकर्मियों की है. इनमें अधिकतम की उम्र काफ़ी छोटी है. कुछ की उम्र तो 12 साल से भी कम है. अनुमान है कि देश की 25 फ़ीसदी से अधिक वेश्याएं सिर्फ़ आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है. भारत में वेश्यावृत्ति को वैध करने की सलाह देकर महिलाओं और लड़कियों के सेक्स व्यापार में चिंताजनक वृद्धि से निपटने का सुझाव दिया गया है.

जिस समाज में वेश्यावृत्ति वैध है, उससे नतीजा निकला है कि इस पर निगरानी रखने में आसानी हुई है. भारत को भी इनसे सीख लेनी चाहिए, न कि वकालत करनी चाहिए कि भारत में वेश्यावृत्ति नाम की चीज़ ही नहीं है. पूरी दुनिया के अनुभव से यह ज़ाहिर है कि वेश्यावृत्ति को वैध बनाकर एचआईवी/एड्स पर काफी हद तक लगाम लगाई और जागरूकता लाई जा सकती है. दुनिया के कुछ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नीदरलैंड और अमेरिका में यौन व्यापार को वैध बनाया जा चुका है. इससे संबंधित क़ानून में ऐसी गतिविधियों

में शामिल लोगों को नियमित चिकित्सकीय जांच कराना अनिवार्य किया गया है. आज यही क़दम भारत में भी उठाए जाने की ज़रूरत है. ऐसा इसलिए, क्योंकि यहां क़ानून बनाने वालों, उसे लागू करने वालों और इस व्यापार को चलाने वालों के बीच एक ख़तरनाक गठजोड़ है.

चाहे वह कोई भी सरकार रही हो और उसने कितनी भी कोशिश की हो, वेश्यावृत्ति को पूरी तरह ख़त्म करने में उसे कभी सफलता नहीं मिली. वेश्यावृत्ति को वैध बनाकर यौन संचरित रोग और एड्स की महामारी के ख़िलाफ़ हम वैध तरीक़े से लड़ सकेंगे. ठीक उसी तरह, जैसे हमने अस्पृश्यता के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है. वेश्यावृत्ति को क़ानूनी मान्यता मिलने से यौनकर्मी न सिर्फ़ स्वाभिमान की ज़िंदगी जी पाएंगी, बल्कि अब तक उनके साथ दोयम दर्ज़े के नागरिक की तरह हो रहे व्यवहार में भी सुधार होगा. यौन व्यापार को वैधता देकर इस व्यवसाय को एक मानवीय चेहरे की शक्ल दी जा सकती है. जबकि अभी उनके साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है मानों वे इंसान नहीं, दूसरे ग्रह के प्राणी हैं. यौनकर्मियों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. साथ ही जब कोई इस पेशे में आए तो उसके पास स्वास्थ्य प्रमाणपत्र होना अनिवार्य हो. किसी दूसरी फ़र्म की तरह वेश्यालयों पर भी टैक्स लगना चाहिए और यौनकर्मियों की चिकित्सा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा एक निश्चित राशि भी तय होनी चाहिए. यौनकर्मियों के परिवार, ख़ासकर उनके बच्चों की देखभाल ज़रूर होनी चाहिए. यौनकर्मियों को क्षेत्र विशेष में ही काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, यानी वेश्यालय रिहायशी और शैक्षणिक इलाक़ों से दूर होने चाहिए.

वहीं दूसरी ओर वेश्यावृत्ति को वैध बनाने का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे फ़ायदा वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले को होगा, न कि यौनकर्मियों को. भारत में महिलाओं को जबरन और मजबूरन इस व्यापार में धकेल दिया जाता है तथा उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है. ऐसे में इन क़दमों से उन्हें फ़ायदा बहुत ही कम होगा. व्यवसायिक यौन शोषण एक तरह की गुलामी है और गुलामी को कभी भी वैध करार नहीं दिया जा सकता है. यह निहायत ज़रूरी है कि सेक्स उद्योग को भी दूसरे उद्योग की तरह माना जाए और इसे क़ानूनी सुरक्षा कवचों के ज़रिए मज़बूत किया जाए, जिससे यौनकर्मियों को कार्यस्थल पर शोषक और अस्वास्थ्यकर तरीक़ों से निजात मिल सके. भारत में एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या और मासूमों को इस व्यवसाय में धकेलना एक चिंता की बात है. क़ानून निर्माताओं के लिए अब वक़्त आ गया है कि वे इस मसले पर गंभीरता से सोचें. उनके सामने जो समस्या है, उसका जवाब है वेश्यावृत्ति को क़ानूनी मान्यता देना. इसलिए भारत को या तो वेश्यावृत्ति को वैध करना होगा जो कि सबसे उपयुक्त है, या फिर कुछ ऐसे फ़ैसले लेने पड़ेंगे, जिससे वेश्यावृत्ति की समस्या पर रोक लगाई जा सके. क़ानून ऐसे न हों कि वह वेश्यावृत्ति की जगह वेश्याओं को ही मिटा दें, बल्कि उन्हें ऐसा होना चाहिए कि लोगों की मानसिकता बदले, जिससे कोई भी इसमें शामिल होने की सोचे ही नहीं. कुछ लोग सेक्स व्यापार को वैध बनाने की वकालत कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारा भारतीय समाज इतना परिपक्व हो चुका है कि वह ऐसी वकालत करे. क़ानूनी ढांचे में कुछ इस तरह संशोधन होना चाहिए कि इससे महिलाओं का शोषण बंद हो और उन्हें इस काम के लिए मजबूर न किया जा सके. इससे भी अधिक यह कि भारत की सामाजिक संरचना को नुक़सान न पहुंचे. सख्त नियंत्रण की दरकार इसलिए भी है, ताकि अवयस्क लड़कियों को इस काम के लिए मजबूर न किया जा सके.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आरएसएस और भारत

लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का क़दम न उठाया जाना अचरज में डालता है. देश ही नहीं, अब पूरी दुनिया को मालूम हो गया है कि बाबरी ध्वंस में किसका हाथ था, लेकिन फिर भी हर तरफ ख़ामोशी का आलम है. यही इस देश का दुर्भाग्य भी है कि दोषी नज़र में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सज़ा देने में व्यवस्था के हाथ कांपने लगते हैं.

राजकुमार सिंह, *फीलखाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

बिहार-झारखंड पर विशेष

चौथी दुनिया ने बिहार और झारखंड पर आधारित चार पृष्ठ अतिरिक्त देकर एक सराहनीय काम किया है. इससे क्षेत्रीय ख़बरों के साथ न्याय हो सकेगा. समाचारपत्रों में अक़्सर होता यह है कि राष्ट्रीय ख़बरों के चक्कर में क्षेत्रीय ख़बरें महत्वपूर्ण होते हुए भी उपेक्षित रह जाती हैं. ऐसे में चौथी दुनिया के उक्त विशेष चार पृष्ठ कारगर साबित होंगे.

विवेकानंद झा, *कलुआही, मधुबनी, बिहार.*

ग़रीबों की आवाज़ उठाई

आपने रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट को अपने अख़बार में छापकर ग़रीब अल्पसंख्यकों का दिल जीत लिया है. अगर आप इस मुद्दे को नहीं उठाते तो संसद में इसकी चर्चा भी नहीं होती. आपने तो अपना काम कर दिया, बाकी का खेल अब सियासी लोगों के हाथों में है.

इम्तियाज मुरादाबादी, *मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश.*

एकजुटता ज़रूरी

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाश में लाने का श्रेय निश्चित रूप से चौथी दुनिया को जाता है. आपने तो दलित मुस्लिमों और दलित ईसाइयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा दी. अब इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है.

आसिफ, *मुखर्जी नगर, नई दिल्ली.*

मुस्लिम महिलाएं और हम

मुस्लिम महिलाओं की आवाज़... लेख में मुस्लिम समाज में महिलाओं की हालत का वर्णन किया गया है. किसी भी सभ्य-शिक्षित समाज में ग़ैर बराबरी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. यह तो मानवीय दृष्टि से भी अपराध सरीखा है.

एस रजनीकांत, *द्वारका सेक्टर-आठ, नई दिल्ली.*

राजनीति की खरी बातें

चौथी दुनिया अख़बार पढ़ा. इसका साहित्यिक पृष्ठ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. इस अख़बार में सच्ची घटनाएं और राजनीति की खरी बातें पढ़ने को मिलती हैं. इसके लिए चौथी दुनिया को धन्यवाद देना चाहता हूं.

कन्हैया राउत
रोहिणी, देवघर, झारखंड.

द्रविड़ का अहम दायित्व

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने बल्लेबाज़ी के क्षेत्र में शानदार मुक़ाम हासिल किया है. हाल ही में श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने लगातार दो शतक लगाकर यह साबित किया है कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है. चयनकर्ताओं को उनकी क़ाबिलियत की क़द्र करनी चाहिए.

अमित धर्मू, *सहरसा, बिहार.*

प्रतियां उपलब्ध कराएं

पश्चिम बंगाल में चौथी दुनिया की प्रतियां नहीं मिल पा रही हैं. कृपया इसे उपलब्ध कराने की कृपा करें.

शैलेश प्रताप सिंह, *दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल.*

बहुत अच्छा अख़बार

मैं पिछले एक माह से चौथी दुनिया पढ़ रहा हूं. यह बहुत अच्छा अख़बार है. मैं इस पत्र का प्रसार पूरे विदिशा ज़िले में करना चाहता हूं.

लियाकत भाई, *गंजबासौदा, विदिशा, मध्य प्रदेश.*

शानदार संपादकीय

चौथी दुनिया में राजबब्बर के जज़्बे की जीत अच्छा लेख था. मीडिया की एकजुटता पर आपका संपादकीय भी बहुत अच्छा था.

सतीश गोपाल गुरहा, *कानूनगोयान, बरेली, उत्तर प्रदेश.*

अखबार राष्ट्रधर्म पर

चौथी दुनिया गंभीरता से पढ़ा. यह राष्ट्रधर्म के पथ पर है. इसे दैनिक पत्र बनाने पर विचार कीजिए.

प्रदीप सिंह राठौर, *मेडिकल कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

देश तोड़ने वालों से सावधान रहें

संतोष भारतीय

देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी. सत्रह साल बाद आई रिपोर्ट अख़बारों की कतरनों का सिलसिलेवार संकलन जैसा लगा, नया ख़ुलासा कुछ नहीं. इस रिपोर्ट ने ख़ुलेआम उन्हें बोलने का मौक़ा दे दिया कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई जो पहले यह बात कहने में डरते थे. इसके बाद भी न आम आदमी ने इसका समर्थन किया और न ही कोई सड़क पर उतरा. भाजपा भी दल के तौर पर खुला विरोध करने का साहस न जुटा पाई. विवेक का परिचय मुस्लिम समाज ने दिया, जिसने कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और बाबरी मस्जिद के दोषी लोगों को गिरफ़्तार करने की सार्वजनिक मांग नहीं की. यदि यह मांग उठ जाती तो देश में सांप्रदायिक ताक़तों को उभरने का एक खुला मौक़ा मिल जाता.

पर यह तो वह पक्ष है जो सुंदर है और सांत्वना देने वाला है, लेकिन इसका एक पक्ष और है, और वह चिंतित करने वाला है. सनातन धर्म से अलग हिंदू धर्म का नाम प्रचलित करने वाली ताक़तें, जिन्होंने अपने संगठन के साथ हिंदू नाम लगा रखा है, एक रणनीति बना रही हैं. रणनीति भारत को अस्थिर करने की, भारत के लोगों के बीच अलगाव की भावना पैदा करने की और नए सिरे से भारत में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की. अभी तक यह केवल संभावित समाचार था, पर अब यह हक़ीक़त बनने जा रहा है. हमेशा की तरह सरकार या तो अनजान है या जानबूझ कर सो रही है. वैसे ही, जैसे वह नरसिंहाराव के प्रधानमंत्रित्व काल में बाबरी मस्जिद गिरने के समय सो रही थी.

लोकसभा चुनाव में हार के बाद निराशा से निकलने में वक़्त ज़रूर लगा, पर अब वे सब उससे उबर गए हैं जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने का दांव खेला था. आडवाणी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, भाजपा भी आधी-अधूरी योजना ही, अपने को पुनर्गठित करने की, पूरी कर पाई. पर संघ ने अपने दूसरे संगठनों को खुली छूट दे दी कि वे भाजपा से अलग देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की रणनीति बनाएं. रणनीति बन चुकी है और एक महीने के भीतर उसे कार्यान्वित भी किया जाएगा.

देश में सबसे पुराने मेलों में एक कुंभ इस बार हरिद्वार में होने जा रहा है. एक महीने चलने वाला यह मेला जनता की आस्था की वजह से लगता है, जिसमें करोड़ों लोग जाते हैं. इसी मेले को रणनीति के कार्यान्वित करने का प्रारंभ बिंदु बनाया जा रहा है. यहां साधु-संतों को इकट्ठा किया जाएगा और उनसे राम मंदिर बनाने का आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कराई जाएगी. साधु-संतों का भारतीय समाज में आम तौर पर आदर किया जाता है, उनकी बातों पर एक वर्ग ध्यान भी देता है. अक़्सर हम देखते हैं कि कथा सुनाने वाले बापुओं के पंडाल में हज़ारों की भीड़ होती है. क्या इसका यह मतलब निकालना चाहिए कि लोगों के वोट भी उसी तरह से पड़ते हैं या लोग उनके राजनैतिक निर्देशों को सुनते हैं? यह सही नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग सभी चर्चित साधुओं और बापुओं ने आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को वोट देने का फ़रमान जारी किया था. किसी ने उसे नहीं माना. साधुओं-संतों को इससे सीख लेनी चाहिए, जो वे नहीं ले रहे.

आसाराम बापू और नरेंद्र मोदी का झगड़ा तो निचले स्तर पर पहुंच गया है. नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचाने की धमकी आसाराम बापू ने दी है और नरेंद्र मोदी आसाराम बापू को गिरफ्तार करना चाहते हैं. दोनों ही हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं. साधु-संत अगर सत्य नहीं समझे तो भविष्य में उनका स्वागत भारतीय समाज में कितना होगा, कहा नहीं जा सकता. साधु-संतों को समाज में नैतिकता, प्यार, स्नेह, सहिष्णुता, अपरिग्रह का बुनियादी संदेश, जो सनातन धर्म का आधार है, फैलाना चाहिए. उन्हें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया याद रखना चाहिए, जो भारतीय समाज का पांच हज़ार वर्ष से ज़्यादा समय से आधार रहा है, पर वे तो इसे भूलते जा रहे हैं. वे राजनीतिज्ञों की तरह उनके इशारे पर उनके स्वार्थ पूर्ति का साधन बनने की होड़ लगाने जा रहे हैं.

साधु-संतों को समाज में नैतिकता, प्यार, स्नेह, सहिष्णुता, अपरिग्रह का बुनियादी संदेश, जो सनातन धर्म का आधार है, फैलाना चाहिए. उन्हें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया याद रखना चाहिए, जो भारतीय समाज का पांच हज़ार वर्ष से ज़्यादा समय से आधार रहा है, पर वे तो इसे भूलते जा रहे हैं.

क्षमा के साथ, जिनके बारे में लिखा है, वे बहुत कम हैं. ज़्यादा साधु-संत ऐसे नहीं हैं. ज़्यादा संख्या उनकी है, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और जिनका विश्वास प्यार, मुहब्बत, साथ-साथ रहने में, जीव-जंतु, पेड़-पौधों से प्यार करने में, इंसान-इंसान को बराबर समझने में है. लेकिन ऐसे लोग ख़ामोश रहते हैं और साथ नहीं आते. जबकि साधु-संतों के नाम पर भटके लोग एक होकर शोर मचाते हैं तो लगता है कि भारतीय समाज की वे आवाज़ हैं. सत्य यह नहीं है, वे आवाज़ नहीं हैं. इसलिए अगर फ़ैसला होना है तो हरिद्वार कुंभ में होना चाहिए कि सनातन धर्म को मानने वाले साधु- संत ज़्यादा हैं या हिंदू धर्म का नाम लेने वाले, साधु-संतों का चोला पहनने वाले लोग. हम बताना चाहेंगे कि पूजा पद्धति सनातन धर्म की है, जिसका पालन ये लोग भी करते हैं जो हिंदू धर्म का नाम लेते हैं.

पर देश के उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, जो देश के मूलभूत आदर्शों में भरोसा करते हैं, जिनमें भारत के लोकतंत्र की ख़ुशबू को बचाए रखने की ताक़त है. देश के सामने महंगाई है, बेकारी है, भूख है, विकास की चुनौती है, लोकतंत्र को बचाए रखने का सवाल है. वहां ऐसे लोगों को रास्ता नहीं देना चाहिए जो देश में भटकाव पैदा करने में अपनी ताक़त लगाते हैं, न कि देश की समस्याएं हल करने में. इनसे वैचारिक बहस करनी चाहिए, लेकिन ये लोग बहस करने में भरोसा नहीं करते. इनके यहां बहस करना दिमाग़ी दिवालियापन माना जाता है. भारत में रहने वालों को और भारत से प्यार करने वालों को ऐसे लोगों और ऐसी ताक़तों से काफी सावधान रहने की ज़रूरत है.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

दोराहे पर पाकिस्तान का लोकतंत्र

आयशा सिद्दिका

अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (एनआरओ) से जुड़े विवादों को सुलझा लिया गया है और लोग ख़ुशी से झूम रहे हैं. कुछ राजनीतिक समीक्षक यह मान रहे हैं कि इससे पाकिस्तान की व्यवस्था और लोकतंत्र को मज़बूती मिलेगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का यह फ़ैसला अभिमानी, अति महत्वाकांक्षी और भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेताओं के लिए एक चेतावनी है.

निश्चित तौर पर यह एक उल्लेखनीय फ़ैसला है, लेकिन राष्ट्रहित चाहने वाले राजनीतिज्ञों के लिए इससे सीख लेने वाली क्या बात है? और, क्या इससे पाकिस्तान की राजनीति के भविष्य पर कोई असर पड़ेगा? इस पर विचार करने के लिए दो मूल बातें हैं. हालांकि एनआरओ हमेशा से विवादित रहा है और इस मुद्दे पर बहस हो सकती है. इसके अलावा लोग इस अध्यादेश के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही इसे सुलझा लेने के लिए बेचैन थे. राजनीतिक तर्कों के कारण इस मुद्दे के दरकिनार होने की आशंका हमेशा से थी. इसे कतई नकारा नहीं जा सकता कि यदि आसिफ़ अली ज़रदारी और पीएमएल-एन (ख़ासकर, शरीफ़ बंधुओं) के बीच संबंध बेहतर होते तो संभवत: यह समझौता सफल हो सकता था. इसके अलावा यदि राष्ट्रपति सिविल-मिलिट्री संबंधों में बदलाव की कोशिश की घातक ग़लती नहीं करते और अधिनियम के तहत दोषी नहीं होते तो उनके कई विरोधी उनके ख़िलाफ़ एकजुट नहीं होते.

ऐसा नहीं है कि इस फ़ैसले का स्वागत नहीं किया गया. फिर भी, यह एक तथ्य है कि कुछ गुप्त ताक़तें राष्ट्रपति के संदिग्ध व्यवहार, फ़ैसले और दूसरी कई गुप्त बातों को लेकर उन्हें उजागर करने के लिए अपना पक्ष तैयार कर रहे थे. इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आसिफ़ अली ज़रदारी ने एनआरओ मामले में सहयोग किया और कोई भी जानकारी छुपाने की कोशिश नहीं की. हालांकि एनआरओ से संबंधित मामलों में वित्तीय भ्रष्टाचार का भी मसला शामिल था और आपराधिक मामलों में सैनिक तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ़ भी शामिल थे, पर तकनीकी तौर पर इसका ज़िक्र नहीं किया गया.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उच्चतम न्यायालय वास्तव में इस मुद्दे पर अपनी पूछताछ के ज़रिए किस निष्कर्ष पर पहुंचता है. ज़ाहिर तौर पर, यह मुशर्रफ़ और उनके क़रीबियों, जिन्होंने उनके संदिग्ध कामों में साथ दिया, को अपनी जद में लेगा. अब शीर्ष न्यायालय ने राज्य की संस्थाओं को सहयोग देना शुरू किया है. पहले यह बिखरी हुई थीं, यदि ये सही होतीं तो यह समझौता बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता. आम लोगों की धारणाओं को कोई दरकिनार नहीं कर सकता है. न्याय में लोगों की आस्था बरकरार रहने के लिए भी यह काफ़ी अहम है. साथ ही इसलिए भी कि लोग किसी न्याय को राजनीतिक या दूसरे पूर्वाग्रह से ग्रसित न समझें. न्यायिक व्यवस्था में विश्वास की बहाली बहुत ही अहम है. इसके अलावा राज्य की दूसरी सभी संस्थाओं के प्रति ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी है, ताकि इन संस्थाओं को मज़बूत किया जा सके. एनआरओ का फ़ैसला विश्वास और क़ानून को मज़बूत करने वाला था.

लेकिन यदि एक सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सिविल संस्थाओं को मज़बूत करने के फ़ैसले से जुड़ा हो, तो जवाब नकारात्मक ही होना चाहिए. आम धारणाओं के प्रति हमारा यह नज़रिया है कि नकारात्मक जवाब सैन्य शक्तियों और उनकी क्षमता को मज़बूत करता है, ताकि राजनीतिक हितों के साथ छेड़छाड़ की जा सके. यह फ़ैसला सिविलियन सरकार के ख़िलाफ़ सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बढ़ रहे गुस्से से मेल नहीं खाता है. यह अपेक्षा से कहीं अधिक है. कैरी-लुगर क़ानून और दूसरे मसलों पर इस्लामाबाद और जीएचक्यू (सैन्य मुख्यालय) के बीच टकराव बढ़ा है. यदि कुछ नहीं भी होता है तो संयोग से सेना ही उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले की लाभार्थी होगी. एक अपमानित राष्ट्रपति के पास बेहद ही कम संभावनाएं हैं कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी संस्था से निपट सके.

प्रेसिडेंसी और सेना मुख्यालय के बीच तनाव यह ज़ाहिर करता है कि यह तीसरी बार है, जबकि राजनीतिक वर्ग ने सेना की शक्तियों में कटौती की कोशिश की है. पहला प्रयास जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, जिनके अधिकार क्षेत्र में अपेक्षाकृत कमज़ोर सेना थी और उन्होंने इसकी शक्तियों में कटौती की पर्याप्त कोशिश की थी. उन्होंने यह कोशिश आंशिक तौर पर संस्थागत तंत्र मसलन ज्वाइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ कमिटी और रक्षा मंत्रालय के ज़रिए की. उन्होंने यह भी कोशिश की कि सभी सेवा प्रमुखों को प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंदर रखा जाए. हालांकि उन्होंने दिल से इन सुधारों की कोशिश नहीं की और सेना के सशक्तिकरण के साथ ही उनका अंत हो गया.

नवाज़ शरीफ़ ऐसे दूसरे नेता थे, जिनके पास इस तरह का समान अवसर था. यह माना गया कि इस संबंध में वह कुछ कड़े फ़ैसले लेंगे, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली जाति समूह से ताल्लुक़ रखते थे और सेना के शीर्ष रैंक के अधिकारियों में अपनी पैठ जमाने में भी सफल हो गए थे. संभवत: सेना ने उनकी योग्यता पर इसलिए शक़ किया, क्योंकि उन्होंने आंशिक और अस्थायी तौर पर अधिकारियों में विभाजन कर दिया. जनरल मुशर्रफ़ की जगह सेनाध्यक्ष पद पर जनरल ज़ियाउद्दीन की नियुक्ति से लगा कि इस फ़ैसले में सेना के कई शीर्ष अधिकारियों की सहमति है. फिर भी, शरीफ़ ने यह मौक़ा इसलिए गंवा दिया, क्योंकि उनके आख़िरी फ़ैसले की धज्जियां उड़ा दी गईं.

उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह सभ्य समाज, जिसने सेना की मुख़ालफ़त की थी, वही आईएसआई और सेना को कमज़ोर करने वाले अधिनियम कैरी-लुगर के प्रावधानों का भी विरोध करने लगेगा. बहुत से राजनीतिज्ञ यह समझने में असफल रहे कि रक्षा मंत्रालय की क्षमताओं को बढ़ाने, इसकी शक्तियों को सभ्य समाज के अनुरूप बनाने और फ़ैसला लेने वाला तंत्र बनाने के लिए इसमें नई जान फूंकने की ज़रूरत है.

हाल में आसिफ़ अली ज़रदारी ने सेना की असाधारण शक्तियों में कटौती की बात सोची. इसके लिए उन्होंने अमेरिका को मनाया कि वह सेना की अपेक्षा सिविलियन सरकार की मदद करे. ज़रदारी ने यह सहज आकलन किया कि उनकी ओर से फैसला लेने का यह सही समय है. एक दशक तक मुशर्रफ़ के शासन की वजह से सेना अंधेरे में छुपी हुई थी और लोग राजनीतिक संस्थाओं को मज़बूत करने तथा सैन्य बलों की शक्तियों में कटौती की बात कर रहे थे. ज़रदारी की तरकीब थी कि इस काम के लिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन की साझेदारी ज़रूरी है.

लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ज़रदारी सेना को न समझ पाने की कमज़ोरी का शिकार हो गए. साथ ही इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संस्थागत गतिशीलता, आंतरिक भागीदारी और संस्थागत सुरक्षा अवरोधों को न समझ पाना भी उनके लिए समस्या बनी. उदाहरण के लिए उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह सभ्य समाज, जिसने सेना की मुख़ालफ़त की थी, वही आईएसआई और सेना को कमज़ोर करने वाले अधिनियम कैरी-लुगर के प्रावधानों का भी विरोध करने लगेगा. दरअसल, बहुत से राजनीतिज्ञ यह समझने में असफल रहे कि रक्षा मंत्रालय की क्षमताओं को बढ़ाने, इसकी शक्तियों को सभ्य समाज के अनुरूप बनाने और फ़ैसला लेने वाला तंत्र बनाने के लिए इसमें नई जान फूंकने की ज़रूरत है. रक्षा मंत्रालय राजनीतिक सरकार और सेना के बीच महज़ संस्थागत कड़ी भर है. इसकी क्षमता दयनीय है. पाकिस्तानी राजनेता समय और मुद्दे के अभाव में ख़ुद को असुरक्षित महसूस करते हैं.

अब राष्ट्रपति 17वें संशोधन को निरस्त करने की समय सीमा बढ़ा सकते हैं, ताकि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने या फिर उसकी नियुक्ति में अपना अहम किरदार निभा सकें. यह उनका आख़िरी, लेकिन अस्थायी जीवनदान है. वह अमेरिका के ख़िलाफ़ तीखे तेवर अपना कर भी अपने लिए कुछ वक़्त ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये सभी अस्थायी रणनीतियां हैं. वह वक़्त अभी दूर है, जब एक बार फिर से जम्हूरियत को नेतृत्व का अगला मौक़ा मिले.

(लेखिका पाकिस्तान की स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

सर्वे में 58 प्रतिशत भागीदारों का मानना था कि पूरी नींद नहीं लेने के कारण इसका असर उनके काम पर पड़ता है, 11 फ़ीसदी लोग काम करने के दौरान ही सो जाते हैं.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

मोसाद यानी ख़ौफ़ का दूसरा नाम

इज़रायल का ख़ुफ़िया आतंक

(बाएं)मोसाद के मौजूदा निदेशक मीर डागन और (दाएं) पूर्व निदेशक मीर अमित

इज़रायल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव. यहीं एक ऐसी एजेंसी का मुख्यालय है, जिसे हम मोसाद कहते हैं. मोसाद यानी दुनिया की सबसे ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसी. मोसाद को क़रीब से जानने वालों की मानें तो यह दुनिया की सबसे ख़ौफनाक क़ातिल मशीन की तरह काम करती है. इस क़ातिल एजेंसी के मुखिया की सोच कैसी होगी, यह सोचकर ही रूह कांप उठती है. यह बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं. अपने पेशेवर क़ातिलाना मिशन की हक़ीक़त का ख़ुलासा ख़ुद मोसाद के मुखिया भी करते हैं. वर्ष 2000 से अभी तक मोसाद की कमान संभाल रहे मीर डागन का बयान हमारी उस बात की तस्दीक करता है, जिसमें हम अभी तक मोसाद के ख़तरनाक, बेरहम और क़ातिलाना मिशन की बात करते आ रहे थे.

मीर डागन कहते हैं, *जब मैं लेबनान में लड़ रहा था तो उस वक़्त हमारे जेहन में मिशन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था. हमारा मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही था, दुश्मनों का ख़ात्मा. चाहे इसके लिए किसी भी रास्ते को अख्तियार करना पड़े.* मीर डागन अपनी बात कुछ इस तरह समझाते हैं, जो महज़ एक मिसाल नहीं, बल्कि उनकी क्रूर और क़ातिल सोच का नतीजा है. डागन बताते हैं कि लेबनान में एक मिशन के दौरान वह एक घर में घुसे. अंदर घुसते ही उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब उन्होंने गोलियों की बरसात बंद की तो देखा कि एक शख्स के सिर में इतनी गोलियां लगी थीं कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया था. उसके शरीर के पास उसकी बीवी और चार बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं. इतनी बेरहमी से हत्या के बावजूद उनके चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं थी और न ही अफ़सोस की कोई भावभंगिमा. यानी अपने दुश्मनों के ख़ात्मे के लिए वह औरत और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे. मोसाद के मिशन की ज़द में जो कोई भी आएगा, उसका अंजाम भी कुछ इसी तरह या इससे भी ख़ौफ़नाक होगा. यही बात कही थी मीर डागन ने. दरअसल, मोसाद के नायकों या कहें कि ख़लनायकों की मानें तो यदि उनके दुश्मन के परिवार का एक भी शख्स ज़िंदा बच निकला तो एक न एक दिन वह भी मोसाद और इज़रायल के ख़िलाफ़ अपना सिर उठाएगा. इस तरह वह उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आएगा. नतीजतन मोसाद इस मुसीबत की नौबत ही नहीं आने देती है और इसीलिए वह अपने दुश्मन के परिवार को भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देती है.

महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है सेक्स. इस दौरान इधर-उधर की बातें करना इनके लिए बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए भी ख़ास साहस की ज़रूरत होती है. बात सिर्फ़ दुश्मन के साथ सोने की नहीं, बल्कि ख़ुफ़िया जानकारी हासिल करने की होती है.

मोसाद पर कई बार इल्ज़ाम लगा कि वह अपने दुश्मनों के साथ बड़ी ही क्रूरता से पेश आती है और उनके ख़ात्मे के अलावा उसके जेहन में कुछ होता ही नहीं. इस पर मोसाद के ऑपरेशनल कमांडर का कहना है कि हमारे दुश्मन हत्या की कई वारदातों को अंजाम देकर पड़ोसी अरब देशों में छिप जाते हैं, जिससे उन पर मुक़दमा चलाना मुमकिन हो ही नहीं सकता. यही वजह है कि हम जवाब उन्हें उनकी ही भाषा में देते हैं. उन्हें खोज निकालना सिर्फ़ मोसाद के ही बूते की बात है, इसीलिए हम ही उन्हें सज़ा देने के हक़दार हैं और यह सज़ा होती है, मौत के बदले मौत. मोसाद का यह निदेशक कहता है, मैं जब कभी भी किसी शख्स की आंखों में चालाकी और साज़िश की भूख देखता हूं तो हमेशा उसे ख़त्म कर देने की ही कोशिश करता हूं, ताकि उसकी आंखों में ख़ौफ देख सकूं. उसके जेहन के ख़ौफ़ को उसकी सांसों में महसूस कर सकूं. इसके लिए मैं कभी अपने हाथ, कभी चाकू तो कभी साइलेंसरयुक्त बंदूक़ का इस्तेमाल करता हूं. और, हत्या की अपनी इस कोशिश पर मुझे कभी कोई मलाल नहीं होता.

मीर अमित, जो 1963 से 1968 के दौरान मोसाद के निदेशक रहे, ने एक बार कहा कि हम एक सरकारी जल्लाद की तरह हैं, जिसके जेहन में उसके काम के अलावा कुछ भी नहीं रहता है. हमें जो निर्देश दिया जाता है, हम वहीं करते हैं. हमारे सारे मिशन इज़रायल के हित में होते हैं और जब मोसाद किसी की हत्या करती है तो वह कोई क़ानून या नियम नहीं तोड़ती, बल्कि वह इज़रायली प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन कर रही होती है. इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोसाद के सारे क्रियाकलाप इज़रायली प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित होते हैं.

मीर अमित मोसाद के सबसे ख़तरनाक और कुछ अलग सोचने वाले प्रमुखों में से एक था. वह अपने मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता था. यहां तक कि उसने इसके लिए महिलाओं को भी तैयार किया. हम आपको बता दें कि महिलाओं का इस्तेमाल उसने सैनिक के तौर पर नहीं किया. फिर भी मीर अमित का यह हथियार एक सैनिक के जज़्बे, जासूस की जांबाजी से कहीं अधिक कारगर था. उसके इस हथियार का निशाना हमेशा अचूक होता. मीर अमित के इस हथियार का नाम तो आप जान ही चुके हैं, वह है औरत. लेकिन महिलाएं किस तरह मोसाद के काम आती थीं, इसका ख़ुलासा ख़ुद मीर अमित ने किया. मीर अमित के मुताबिक़, महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार है सेक्स. इसके ज़रिए वे किसी राज़ या ख़ुफ़िया जानकारी को बड़ी आसानी से हासिल कर सकती हैं. वह कहते हैं, महिलाएं यह जानती हैं कि उन्हें इस हथियार यानी सेक्स का इस्तेमाल कैसे करना है. मीर अमित के मुताबिक़, ख़ुफ़िया गतिविधियों और सेक्स के ज़रिए इसकी जानकारी जुटाने के बीच का नाता उतना ही पुराना है, जितना कि जासूसी करना. सेक्स महिलाओं का हथियार है. इस दौरान इधर-उधर की बातें करना इनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए भी एक ख़ास क़िस्म के साहस की ज़रूरत पड़ती है. बात सिर्फ़ अपने दुश्मन के साथ सोने की नहीं है, बल्कि सारा फ़ोकस ख़ुफ़िया जानकारी हासिल करने पर होता है.

इस तरह मोसाद अपने मिशन के प्रति जज़्बे और जुनून के लिए जानी जाती है. सफलता हासिल करने के लिए वह न सिर्फ़ जोख़िम उठाती है, बल्कि हर तरह के हथकंडे भी अपनाती है. हथकंडे इसलिए कि दुश्मनों की तमाम अहम जानकारियां उसके पास रहें, जिससे किसी भी मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके. जैसा हमने आपको बताया कि मोसाद के मिशन के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है. आख़िर मोसाद के बारे में ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ़ भगवान ही सारी बातें जानते हैं और वह सिर्फ़ मोसाद के लिए काम करते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

छोटी उंगलियों में छुपा रहस्य

महिलाएं पुरुषों की तुलना में क्यों अधिक संवेदनशील होती हैं? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि दरअसल यह रहस्य उंगलियों में छुपा है. उन्होंने शोध में पाया कि ख़ूबसूरत उंगलियों को छूने से अधिक सेंस विकसित होता है, जिसके कारण वे अधिक संवेदनशील होते हैं.

निष्कर्ष बताता है कि स्पर्श को महसूस करने की क्षमता पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है, क्योंकि औसतन महिलाओं की उंगलियां छोटी होती हैं, जिसके चलते उनमें स्पर्श करने की संवेदनशीलता अधिक विकसित हो जाती है.

शोधकर्ता डैनियल गोल्डरिच ने कहा कि न्यूरोसाइंटिस्ट बहुत पहले से यह अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोगों को स्पर्श का अहसास अधिक होता है, लेकिन इसका अंतर काफ़ी रहस्यमय है. उन्होंने कहा कि हमारी खोज से पता चलता है कि स्पर्श का महत्वपूर्ण कारक उंगली का छोटा होना है.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुरुष और महिलाओं की उंगलियों में संवेदनशीलता अलग-अलग क्यों होती है, शोधकर्ताओं ने सबसे पहले एक सौ विश्वविद्यालयों में छात्रों की उंगलियों का आकार मापा, जिसमें प्रत्येक छात्र की स्पर्श संवेदनशीलता का परीक्षण किया गया. शोध से जुड़े ईदेन लर्नर ने कहा कि सेक्स में जो अंतर उत्पन्न होता है, वह लोगों की उंगली के आकार के कारण होता है. इसलिए अगर किसी पुरुष की उंगली का आकार छोटा है तो वह महिलाओं की अपेक्षा स्पर्श करने में अधिक संवेदनशील होता है.

93 प्रतिशत भारतीयों को चैन की नींद नहीं

हाल में हुए एक सर्वे के अनुसार, 93 फ़ीसदी भारतीय चैन की नींद नहीं ले पाते हैं. जबकि अच्छी सेहत के लिए कम से कम आठ घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है. अगर अच्छी नींद नहीं आती है तो उसका असर काम पर पड़ता है. वहीं 11 प्रतिशत लोग काम करने के दौरान कार्यालय में झपकी लेते हैं. फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के सर्वे के अनुसार, 11 फ़ीसदी भारतीय नींद पूरी न होने की वजह से अवकाश लेते हैं.

ग़ौरतलब है कि यह सर्वे नवंबर 2009 में नेल्सन कंपनी द्वारा कराया गया. इसमें 25 शहरों के 35-65 वर्ष की उम्र वाले 5,600 लोगों को शामिल किया गया.

सर्वे में शामिल 58 प्रतिशत लोगों का मानना था कि पूरी नींद न लेने का विपरीत असर उनके काम पर पड़ता है. 11 फ़ीसदी लोग काम करने के दौरान ही सो जाते हैं.

सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 74 फ़ीसदी लोग सोते वक़्त दो से तीन बार उठते हैं. 90 फ़ीसदी लोगों ने इसका कारण काम के प्रति जवाबदेही, 15 प्रतिशत ने काम का दबाव और दस फ़ीसदी ने घर के बाहर शोरगुल को बताया.

इस सर्वे का 62 प्रतिशत हाई रिस्क ऑब्सट्रैक्टिव स्लिप ऑप्निया (ओएसए) को दर्शाता है. इससे सोते वक़्त सांस लेने में दिक़्क़त होती है और हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है.

नरभक्षण के प्रमाण मिले

पुरातत्ववेत्ताओं को दक्षिण-पश्चिम जर्मनी में सात हज़ार साल पुराने क़ब्रिस्तान में सामूहिक नरभक्षण के प्रमाण मिले हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि यूरोप के नवप्रस्तर काल में नरभक्षण प्रचलित था. शोध का खुलासा एक पत्रिका में किया गया. इस पत्रिका के दावों में सच्चाई इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि उसने इसके पुख्ता सबूत दिए हैं. हर्क्सहेम नामक एक गांव के पास कोई 500 मानव अवशेष मिले हैं, जिनका भक्षण किया गया था. शोधकर्ताओं का कहना है कि इनमें बच्चों और भ्रूणों के अवशेष भी शामिल हैं. सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनके अंग जानबूझ कर काटे गए हैं. इस क़ब्रिस्तान की सबसे पहली खुदाई 1996 में हुई थी और फिर उसके बाद वर्ष 2005 और 2008 में. शोध दल के प्रमुख एवं फ्रांस के बोर्दो विश्वविद्यालय के ब्रूनो बोलस्टिन ने बताया कि उन्हें और उनके सहयोगियों को इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि मानव हड्डियों को जानबूझ कर काटा गया है. उन्होंने कहा कि हमें जानवरों की हड्डियों पर ऐसे नमूने मिले हैं, जिन्हें देखने से साफ़ पता चलता है कि उन्हें आग पर भूना गया था. इसी तरह के नमूने मानव अस्थियों पर भी मिले हैं. हालांकि डॉ. बोलस्टिन ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रमाणित करना मुश्किल है कि इन हड्डियों को पकाया गया. कुछ वैज्ञानिक नरभक्षण के इस अनुमान को सही नहीं मानते. उनका तर्क है कि हड्डियों से गोश्त हटाना नरभक्षण का प्रमाण न होकर दफ़नाने के अनुष्ठान का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन डॉ. बोलस्टिन का कहना है कि खुदाई में मिले मानव अवशेष यह दर्शाते हैं कि वे जानबूझ कर अंग-भंग किए गए और हड्डियों को चबाया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं बाबा ने अपनी साधना और मानव कल्याण का केंद्र शिरडी की एक टूटी-फूटी मस्जिद को बनाया, जहां एक ओर वह हिंदू संतों की तरह मस्जिद के भीतर धूनी रमाकर बैठते थे.

समाज को साईं कृपा की ज़रूरत

साईं बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति से तत्कालीन समाज को चमत्कृत कर दिया था. समाज में व्याप्त जातिपात, ऊंच-नीच के भेद को मिटाकर मानव मात्र में प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही साईं बाबा ने संसार में सबसे पहले इस बात की घोषणा की कि सबका मालिक एक है. साईं बाबा सभी धर्म, मज़हब और पंथों का एक समान आदर करते थे. यही कारण है कि आज तक जो भी संत, महात्मा, फ़क़ीर, पादरी, पैंगबर और गुरु हुए हैं, उनमें शिरडी के साईं बाबा का चरित्र सबसे अलग है.

साईं बाबा ने अपनी साधना और मानव कल्याण का केंद्र शिरडी की एक टूटी-फूटी मस्जिद को बनाया, जहां एक ओर वह हिंदू संतों की तरह मस्जिद के भीतर धूनी रमाकर बैठते थे, वहीं दूसरी ओर उनकी ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह मालिक है का वाक्य रहता था. जातिपात, ऊंच-नीच और तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करते हुए साईं बाबा ने अपने भक्तों के सामने भाईचारे, समानता और प्रेम का आदर्श स्थापित किया. सभी धर्मों के धार्मिक पर्व बाबा और उनकी द्वारका मस्जिद पूरे उल्लास के साथ मनाती थी. उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं था. मानव मात्र की सेवा ही उनका परम उद्देश्य था.

आज जहां सारा राष्ट्र और राष्ट्रभाषी अपनी ढपली अपना राग गाने में मशगूल है, जहां धर्म केवल व्यक्तिगत प्रभाव को मापने का माध्यम भर रह गया है, जहां रोज़ ही सांप्रदायिक दंगे में मानवता को कुचल रहे हैं, जहां ऊंच-नीच ने मानव को मानव द्वारा ही चाहरदीवारियों में कैद कर दिया है, जहां जातिपात के बंधन मानवीय कलंक की सीमा पर जा पहुंचे हैं, वहां शिरडी के साईं बाबा के चरित्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता. धर्म, मजहब, रीतिरिवाज और अंधविश्वास को तोड़कर यदि सारा राष्ट्र साईं बाबा के सिद्धांत सबका मालिक एक है पर चल पड़े तो एक अरब की जनसंख्या वाला यह राष्ट्र एक बार पुनः विश्व का सिरमौर और सोने की चिड़िया बन सकता है.

साईंभक्तों, यही शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन की स्थापना का आदर्शपूर्ण उद्देश्य और आधार है. यानी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ही सारे भारतवासियों को मित्रता और भाईचारे के एक पवित्र साईं नाम सूत्र में बांधना. इसमें कोई संदेह नहीं कि यह युग विज्ञान का है. विज्ञान की तरक़्क़ी ने सारे विश्व को चमत्कृत कर दिया है. विज्ञान के हर दिन समय की गति से भी तेज़ नए-नए आविष्कार हमारे सामने आ रहे हैं. विज्ञान की शक्ति परमात्मा की असीम शक्ति को कुंठित कर देने का दावा कर रही है, लेकिन जब एक शरीर से प्राण निकल जाते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, तब विज्ञान उसका मूकदर्शक बनने के अलावा और कुछ नहीं सोच पाता, कुछ कर नहीं पाता. विज्ञान व्यस्तता है, परंतु आध्यात्मिक शांति और जीवन के अंत में केवल शांति का मार्ग ही रह जाने वाला है. साईं इच्छा से इस महायज्ञ में हम, आप और सबकी भूमिका पूर्व निर्धारित है, बस आपको अपने सत्कर्मों की आहुति डालने के लिए इसमें शामिल भर होना है. आपके आते ही यह महान महायज्ञ सारे वातावरण को पवित्र करने की दिशा में अग्रसर हो जाएगा.

शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन और चौथी दुनिया आज एक साथ मिलकर आपको साईं भक्ति की पावन गंगा में डुबकी लगाने का पुनीत अवसर दे रहे हैं. आज से हम प्रति सप्ताह आपके लिए साईं सत्संग शीर्षक से एक नया पृष्ठ प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसकी विषयवस्तु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री सद्गुरु सच्चिदानंद शिरडीपुरीश्वर साईंनाथ महाराज के लौकिक एवं अलौकिक जीवन, भक्तों पर साईं कृपा की रोमांचक और भक्तिपूर्ण सामग्रियों के साथ ही वर्तमान के साईं भक्तों द्वारा साईं भक्ति प्रचार की दिशा में किए जा रहे पुनीत प्रयासों की सूचना से जुड़ी होगी.

मैं शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन की तरफ़ से आप सभी पाठकों, इस महायज्ञ में अपनी भक्ति की श्रद्धापूर्ण आहुति डालने वाले साईं भक्तों और विशेष रूप से फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी और परम साईं भक्त श्री विकास कपूर को बधाई देता हूं, जिनके साधु प्रयासों से आज यह सपना साकार हो रहा है.

ॐ साईं राम.

(मुख्य संस्थापक ट्रस्टी साईं भक्त ऑसिम खेत्रपाल की कलम से)

श्री सद्गुरु साईं बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन (रजि.)

फाउंडेशन के अध्यक्ष असीम खेत्रपाल

फाउंडेशन के उद्देश्य

- आम लोगों तक शिरडी के साईं बाबा का संदेश पहुंचाना.
- वृंदावन में मथुरा गिरिराज साईं मंदिर, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और धर्मशाला की स्थापना करना.
- चारों धामों में साईं मंदिर, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और धर्मशाला की स्थापना करना.
- उचित स्थानों पर साईं वेलनेस सेंटर स्थापना करना.
- शिरडी साईंबाबा फाउंडेशन के तहत संपूर्ण विश्व में साईं भक्तों का परिवार बनाना.
- स्वर्गीय लक्ष्मी बाई शिंदे, जिन्हें शिरडी की पवित्र भूमि पर साईं बाबा ने समाधि में जाने से पूर्व नौ स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, की स्मृति में मंदिर की स्थापना करना.
- प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की मदद करना.
- गांवों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना.
- ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए फंड की स्थापना करना.

सदस्यता योजनाएं

इस फाउंडेशन का सदस्य बनने वाले व्यक्ति को उपहारस्वरूप फाउंडेशन द्वारा निर्मित फिल्म शिरडी साईं बाबा की वीसीडी, ऑडियो सीडी और साईं सच्चरित्र की पुस्तक दी जाएगी. इसके साथ ही वृंदावन मंदिर के फ्रेम में साईं बाबा की तस्वीर और शीघ्र प्रकाशित होने वाली अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी. यह सब चुनी गई विभिन्न सदस्यता योजनाओं के आधार पर होगा.

आजीवन सदस्यता

कोई भी व्यक्ति या संस्था इस फाउंडेशन में आजीवन सदस्यता हासिल कर सकता है. इसके लिए आपको 25,000 रूपये का शुल्क देना होगा. इस योजना के तहत आपको मिलेगा:

- श्री शिरडी साईं बाबा की ताम्र की सिंहासन वाली प्रतिमा
- दो डीवीडी, साईं चरित्र (बड़ी)
- लॉकेट (बड़ा), चरण (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं बॉक्स, यूडीआई और घड़ी

विशेष सदस्य

फाउंडेशन का विशेष सदस्य बनने के लिए आपको 10,000 रूपये का शुल्क अदा करना होगा. और आपको मिलेगा:-

- सिंहासन के साथ साईं बाबा की प्रतिमा
- दो डीवीडी
- साईं चरित्र(बड़ी), लॉकेट (बड़ा), चरण (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं बॉक्स, यूडीआई और घड़ी

कार्यकारिणी सदस्य

कार्यकारिणी सदस्य बनने के लिए निर्धारित शुल्क 5,000 रूपये है. इसमें आपको मिलेगा:

- साईं बाबा की प्रतिमा
- दो डीवीडी, साईं चरित्र (बड़ी)
- लॉकेट (बड़ा), चरण (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं बॉक्स, यूडीआई और घड़ी

सामान्य सदस्य

सामान्य सदस्यता की अवधि तीन वर्ष और शुल्क 3,000 रूपये है. इसमें आपको मिलेगा:

- साईं बाबा की प्रतिमा
- दो डीवीडी, साईं चरित्र (बड़ी)
- लॉकेट (बड़ा), चरन (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं फोटो (कार के लिए), यूडीआई और घड़ी

नाम.....

पता.....

टेलीफोन.....मोबाईल.....

ई-मेल.....

हस्ताक्षर

सदस्य बनने के लिए अपना पूरा विवरण निम्न पते पर अपने ड्राफ्ट के साथ भेजें

156, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, फोन नं. 011-46567351/52

साईं सार्वभौम हैं

उस समय साईं बाबा सशरीर शिरडी में विराजमान थे. हर दिन वह अपनी झोली लेकर शिरडीवासियों से भिक्षा मांगने निकल पड़ते, परंतु उस दिन लीला बिहारी साईं के मन में एक नई लीला जन्म ले रही थी. दोपहर का वक़्त था, साईं बाबा अपनी झोली लिए अपनी परमभक्त लक्ष्मीबाई शिंदे के घर जा पहुंचे. अपने आराध्यदेव साईं को घर आया देखकर लक्ष्मीबाई निहाल थीं. बाबा ने आते ही कहा कि लक्ष्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? लक्ष्मी के तो मानों भाग्य ही खुल गए. उसने जल्दी-जल्दी भाखरी बनाई और बाबा के सामने थाली परोस कर स्वयं हाथ पंखा लेकर बैठ गईं. अल्लाह मालिक कहते हुए शिरडी के नाथ साईं बाबा ने पहला कौर तोड़ा और कालू-कालू करके पुकारने लगे. उनकी पुकार सुनकर एक काला कुत्ता न जाने कहां से भागता हुआ आया. बाबा ने एक-एक करके थाली का सारा भोजन उसके सामने डाल दिया. कुत्ता तो तृप्त हो गया, पर बाबा की मुंहलगी लक्ष्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा. उसने गुस्से से अपनी शिकायत दर्ज़ करवाई तो बाबा ने हमेशा की तरह मुस्करा कर कहा कि क्रोध न कर लक्ष्मी, कुत्ते की भूख शांत करना मेरी भूख शांत करने के बराबर है. कुत्ते में भी तो आत्मा है और उसकी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है. भले ही प्राणियों की आकृतियां भिन्न-भिन्न हों, भले ही वे बोल न सकते हों, परंतु भूख तो सबकी एक समान है. लक्ष्मी, तुम इस सत्य को जान लो कि जो भूखे को भोजन कराता है. वह सही मायने में मुझे ही भोजन कराता है. लक्ष्मीबाई को बाबा की सार्वभौमिकता का आभास हो चुका था. उन्होंने अपने देवा के चरण पकड़ कर भावविभोर स्वर में कहा कि मैं समझ गई देवा. आज मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहती हूं कि रोज़ एक भूखे को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करूंगी.

सोमनाथ से रथयात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, हाशिए पर पड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हिंदुओं का समर्थन बढ़ता जा रहा था. कहने वालों ने इस यात्रा को आडवाणी की दंगा-यात्रा तक कह डाला.

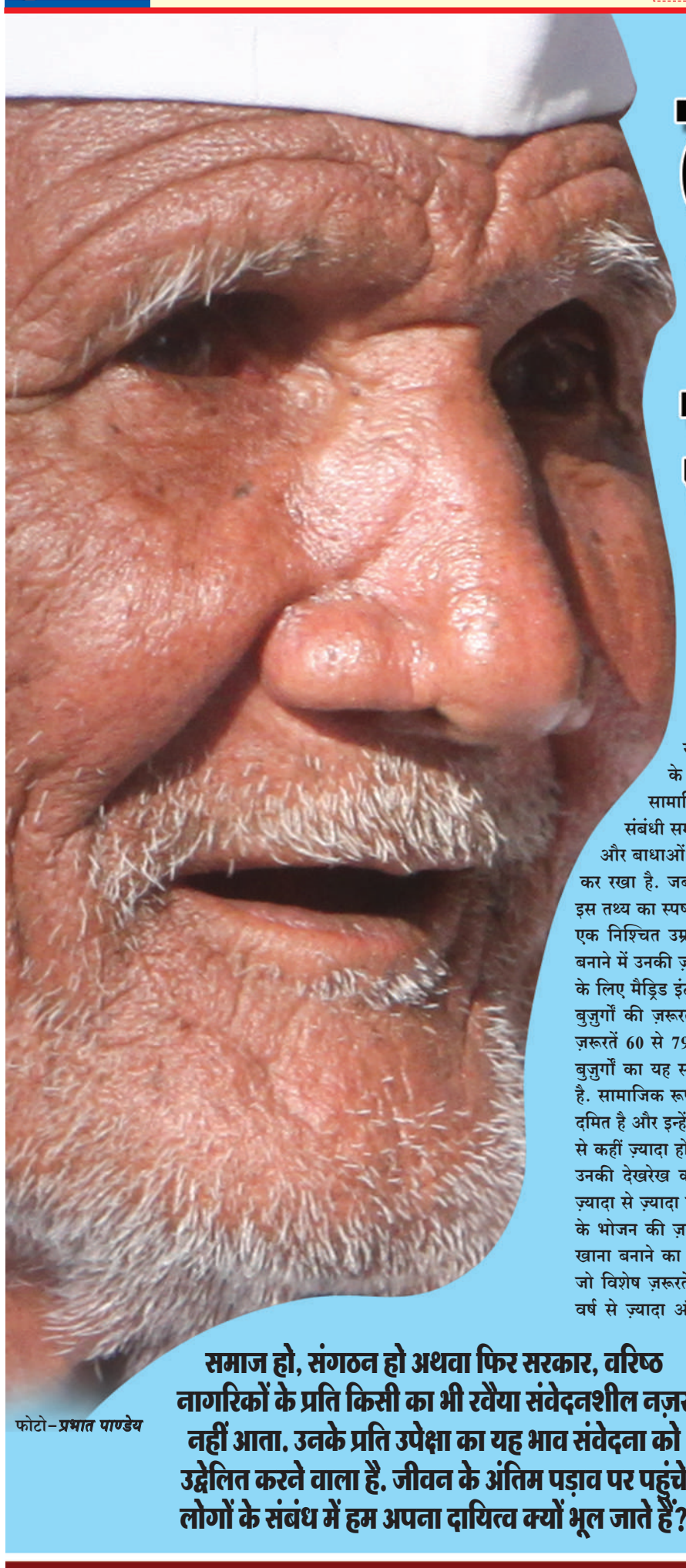

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बुज़ुर्गों के प्रति सभी ग़ैर ज़िम्मेदार

समाज हो, संगठन हो अथवा फिर सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति किसी का भी रवैया संवेदनशील नज़र नहीं आता. उनके प्रति उपेक्षा का यह भाव संवेदना को उद्वेलित करने वाला है. जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे लोगों के संबंध में हम अपना दायित्व क्यों भूल जाते हैं?

सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने के क्रम में 80 वर्ष की अवस्था पार कर चुके बुज़ुर्गों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर देती है. वह सभी बुज़ुर्गों को एक समान समूह में रखकर ही उनकी समस्याओं को देखती है. जबकि उम्र के आठवें दशक के पार ज़िंदगी जी रहे लोगों की सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भिन्न होती हैं. सरकार ने उनकी विशिष्ट ज़रूरतों और बाधाओं को ध्यान में रखकर कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रखा है. जबकि वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 1982 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि बुज़ुर्गों के लिए, ख़ासकर वे बुज़ुर्ग जो एक निश्चित उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, नीतियां और कार्यक्रम बनाने में उनकी ज़रूरतों का अलग से ध्यान रखा जाएगा. जबकि बुज़ुर्गों के लिए मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2002 अस्सी से ऊपर के बुज़ुर्गों की ज़रूरतों की परवाह नहीं करता. बावजूद इसके कि उनकी ज़रूरतें 60 से 79 वर्ष उम्र समूह की ज़रूरतों से काफ़ी अलग होती हैं. बुज़ुर्गों का यह समूह आर्थिक ज़रूरतों के लिए दूसरों पर ज़्यादा निर्भर है. सामाजिक रूप से ज़्यादा कटा हुआ है, मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा दमित है और इन्हें सेहत संबंधी एवं व्यक्तिगत देखभाल की ज़रूरत दूसरों से कहीं ज़्यादा होती है. ये अकेलापन महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उनकी देखरेख करने वाले एवं अन्य दूसरे लोग उनके पास बैठें तथा ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त व्यतीत करें. उन्हें दूसरों से अलग कुछ ख़ास तरह के भोजन की ज़रूरत होती है. जबकि गृहिणियां इनके लिए अलग से खाना बनाने का वक़्त न होने का रोना रोती हैं. इस परिदृश्य में उनकी जो विशेष ज़रूरतें समझ में आती हैं, वे सामान्य बुज़ुर्गों जिन्हें हम 60 वर्ष से ज़्यादा और 80 वर्ष से कम उम्र का मानते हैं, के लिए तैयार नीतियों और कार्यक्रमों के पैमाने पर सही नहीं बैठती हैं. जराविज्ञान अध्ययन केंद्र (सेंटर फॉर जेरेंटोलोजिकल स्टडीज) त्रिवेंद्रम के अध्यक्ष डॉ. पी के बी नायर कहते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए बनी कई योजनाएं जिनमें उनके सक्रिय व उत्पादक ज़िंदगी जीने, रोज़गार व नियोजन के कार्यक्रम बनाए गए हैं, की नीतियां 60 से ज़्यादा व 70 से कम उम्र के युवा बुज़ुर्गों और 70 से ज़्यादा व 80 वर्ष से कम उम्र के बुज़ुर्गों की तुलना में बुज़ुर्गों में भी बुज़ुर्ग लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखती हैं. बुज़ुर्गों में भी जो अति बुज़ुर्ग हैं यानी 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, वे कई लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं. उन्हें दिखाई कम देता है, उन्हें सुनाई भी कम देता है. उनके जोड़ों में हमेशा दर्द होता रहता है, उनके हृदय में तक़लीफ़ रहती है. उनकी याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, उनके दांत टूट चुके होते हैं. उन्हें मधुमेह और रक्तचाप उच्च रहने की शिकायत रहती है. जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनका चलना-फिरना तक़लीफ़देह होता जाता है. कई तो बिस्तर से उतर भी नहीं पाते हैं. वे जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और शारीरिक रूप से अपंग भी होते चले जाते हैं. यहां तक कि बिना छड़ी के सहारे चलने पर वे अक्सर गिर जाते हैं या किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. अकेलापन, अवसाद, अलग-थलग रहने की मजबूरी, समाज से कट जाना, समुचित देखरेख का अभाव, दुर्व्यवहार और उपेक्षा आदि कुछ ऐसे कष्टदायी कारक हैं, जिनसे वे अवसादग्रस्त रहते हैं और स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं.

अस्पतालों में बुज़ुर्गों और ज़्यादा बुज़ुर्गों के इलाज के लिए अलग वार्ड की ज़रूरत है. परिवार द्वारा उनके गहन देखरेख की ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है. परिवार के लोगों को चाहिए कि वे बुज़ुर्गों की सही देखरेख के लिए समर्पित केयर टेकर को रखें. अमूमन 60 वर्ष से ज़्यादा, लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के बुज़ुर्ग तो अपनी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग अपनी सामान्य देखभाल भी नहीं कर पाते हैं. 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है. उनमें से क़रीब तीन चौथाई बुज़ुर्ग वैधव्य की ज़िंदगी जी रही होती हैं.

आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दुनिया में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, वर्ष 2006 में 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों की संख्या जहां 89.4 मिलियन थी, वर्ष 2050 तक इसके 394 मिलियन हो जाने की उम्मीद है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले सरकारी संगठनों और सरकार को चाहिए कि वे संवेदनशील युवाओं को बुज़ुर्गों की समुचित देखभाल के लिए प्रशिक्षित करें, ताकि वे कोई बहाना न बना सकें. इससे पहले कि कोई बुज़ुर्ग इस दुनिया को अलविदा कहे, समाज उसे उचित सम्मान तो दे. यह उसका हक़ है और हमारा दायित्व.

(लेखक ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं)
डी आर आहूजा
feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

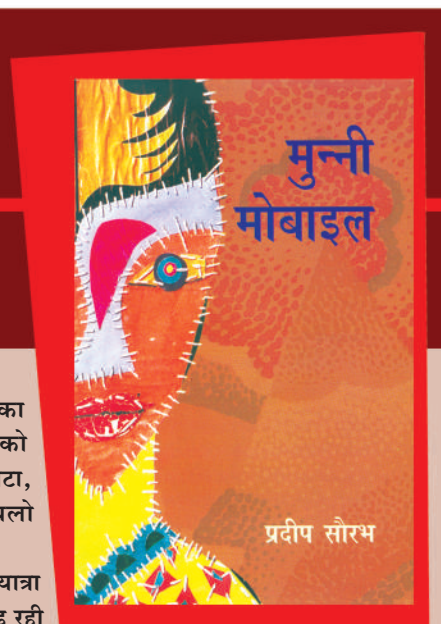

प्रदीप सौरभ

अहमदाबाद का उनका अनुभव सबसे अलग-थलग था. वहां की यादों से आनंद भारती अब भी सिहर उठते हैं. गोधरा कांड उनकी आंखों से गुज़रा था. उनकी कलम ने उस सच्चाई को बेख़ौफ़ अपनी रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाया था. अख़बार की लोकप्रियता भी बढ़ी थी पर स्वयं आनंद भारती के लिए उन दिनों की यादें मीठी कम और तीखी ज़्यादा रही हैं. वह कभी उन्हें याद नहीं करना चाहते, पर वे यादें ऐसी हैं जो कि रील की तरह उनके साथ चलती रहती हैं. बात उस साल की है जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में बलवाइयों द्वारा आग लगाने के बाद गुजरात सुलग रहा था. साबरमती एक्सप्रेस में हिंदू कारसेवक थे. ये कारसेवक अयोध्या में कारसेवा कर अयोध्या लौट रहे थे. गोधरा रेलवे स्टेशन पर कारसेवकों की लड़ाई हुई. इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि सिंगल फालिया पर गाड़ी रोक ली गई. बलवाइयों ने एस-6 कोच में आग लगा दी. आग लगने के और भी कारण बताए जा रहे हैं. जस्टिस बनर्जी से लेकर जस्टिस नानावटी तक कारणों की तह में गए और बिना गए अपने-अपने फ़ैसले दे चुके हैं. सेक्यूलरिस्ट कहते हैं कि कारसेवकों ने ख़ुद आग लगा ली. हिंदू ब्रिगेड कहती है कि मुसलमानों ने आग लगाई.

सिंगल फालिया मुस्लिम बहुल इलाक़ा है. इस आग के बाद गोधरा स्टेशन देश के नक़्शे में प्रमुख तौर पर उभर आया. इस अग्निकांड से पहले गोधरा में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे देश के लोग जानें. इसी गोधरा ने देश की राजनीति में तीव्र ध्रुवीकरण किया. वैसे ध्रुवीकरण की नींव तो छह दिसंबर, 1992 को ही पड़ गई थी. उस दिन बाबरी मस्जिद को भगवा ब्रिगेड ने ध्वस्त कर दिया था. हिंदू राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुखिया लालकृष्ण आडवाणी से लेकर भगवा सेना की तेज़ तर्रार साध्वी उमा भारती, सभी इस कथित राष्ट्रीय कलंक को ध्वस्त करने में शामिल थे.

अयोध्या में सिर्फ़ एक ही नारा था- बाबरी मस्जिद को एक धक्का और दो. हिंदू बवालियों का मानना था कि बाबरी मस्जिद जिस प्लॉट में थी उसी में उनके भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था. हिंदू इस ज़मीन पर रामलला का भव्य मंदिर बनवाना चाहते हैं. उनकी आस्था का सवाल था. ऐसी आस्था जो तर्कों से परे थी. उसके लिए ज़रूरी था कि बाबरी का ध्वंस किया जाए. पुलिस की सुरक्षा और संरक्षण में बाबरी का ध्वंस हुआ.

बाबरी ध्वंस की भूमिका तो पहले ही बन चुकी थी. लालकृष्ण आडवाणी दो साल पहले सोमनाथ से अयोध्या तक रामजन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए संकल्प रथ यात्रा निकाल चुके थे. फिजा में राम जन्म भूमि का मुद्दा तैरने लगा था. मंदिर निर्माण के पक्ष में चारों तरफ़ नारे गूंज रहे थे- बच्चा-बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो, बांध लंगोटा, थाम के सोटा, चलो अयोध्या.

सिंगल फालिया मुस्लिम बहुल इलाका है. इस आग के बाद गोधरा स्टेशन देश के नक्शे में प्रमुख तौर पर उभर आया. इस अग्निकांड से पहले गोधरा में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे देश के लोग जानें. इसी गोधरा ने देश की राजनीति में तीव्र ध्रुवीकरण किया.

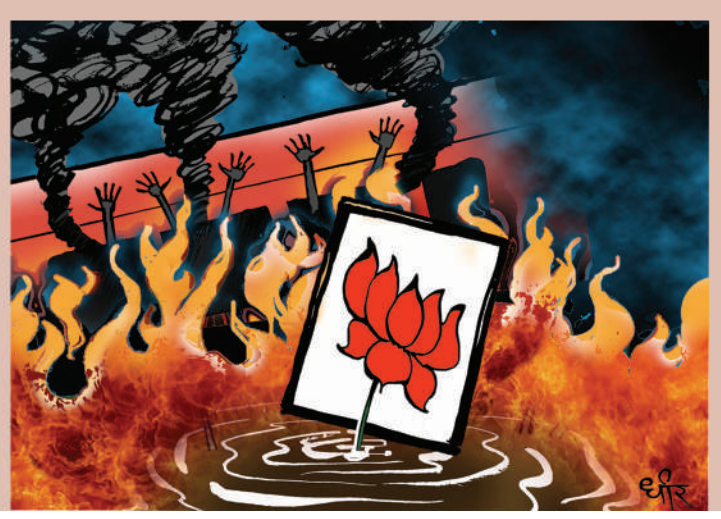

सोमनाथ से रथयात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थी, हाशिए पर पड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हिंदुओं का समर्थन बढ़ता जा रहा था. कहने वालों ने इस यात्रा को आडवाणी की दंगा-यात्रा तक कह डाला. रथ यात्रा के रथी आडवाणी का करिश्मा चल निकला था. बाद में रथयात्रा की परिणति बाबरी ध्वंस के साथ हुई. बाबरी तो ध्वंस हो चुकी थी. अब हिंदू ब्रिग्रेड के आगे सवाल था कि वहां रामलला का मंदिर कैसे बनाया जाए. केंद्र सरकार ने विवादित ढांचे पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दे दिए थे. असल में बाबरी तो एक बहाना था, भारतीय जनता पार्टी राम के कंधों पर चढ़कर देश की सत्ता पर क़ाबिज़ होना चाहती थी. इसीलिए वह और उसके सहयोगी संगठन मंदिर निर्माण के लिए तरह तरह के आंदोलनों में जुट गए. कभी शिला पूजन, तो कभी मंदिर का शिलान्यास, तो कभी साधू संतों के सम्मेलन आदि आदि.

चार साल से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर राम नाम की माला जपते रहे. पार्टी का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी के हर क़दम पर नज़र रखे हुए था. आज़ादी के बाद देश में इमरजेंसी को जन्म देने वाले जेपी आंदोलन से भी बड़ा रामजन्म भूमि का आंदोलन बन गया था. लाखों लोगों ने भगवान राम के नाम पर आंदोलन में भागीदारी की. बाबरी ध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके लगुवा-भगुवा संगठन राम के नाम पर आज़ादी के बाद देश को पहली बार सांप्रदायिक धरातल पर बांटने में कामयाब हो गए. 1996 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तेरह दिन की सरकार बनाने में कामयाब हुई. बहुमत न होने के चलते पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपने नाम के आगे भूतपूर्व लगाना पड़ा. इसके बाद आई देवगौड़ा की सरकार भी कुछ ही महीने चल सकी.

(अगले अंक में जारी)

feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

28 दिसंबर, 2009 –3 जनवरी, 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. निजी संबंधों में निकटता आएगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. अचानक कहीं यात्रा केयोग बन रहे हैं. धार्मिकआस्था में वृद्धि होगी.आर्थिकपक्ष मज़बूत होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
विरोधी सक्रिय रहेंगे. शासन सत्ता का भरपूर सहयोग मिलेगा. मौसम में बदलाव के प्रति सचेत रहें. निजी संबंधों में निकटता आएगी. नेत्र विकार की आशंका बनी हुई हैं. किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा. आय के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. किसी मित्र पर अधिक विश्वास करना घातक हो सकता है. इस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. साख पर नियंत्रण बनाए रखें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फिर भी मन अज्ञात भय से परेशान रहेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. दुर्घटना की आशंका है. धन, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी. सामाजिक कार्यों में आप अधिक व्यस्त रहेंगे. क्रोध और भावुकता पर नियंत्रण रखें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. लेकिन व्यर्थ का समय नष्ट हो सकता है. उपहार या सम्मान की प्राप्ति होगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी ज़रूरी है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव व वर्चस्व में वृद्धि होगी. जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. मैत्री संबंध मज़बूत होंगे. व्यवसायिक सफलता मिलेगी. ख़र्च अधिक हो सकता है. व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
भौतिक दिशा में प्रगति होगी. विरोधी परास्त होंगे. रुके कार्य संपन्न होंगे. दांपत्य जीवन में तनाव मिल सकता है. व्यावसायिक प्रगति होगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्कता है. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
मकान और संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी. कहीं यात्रा पर जाएंगे तो उसका लाभ अवश्य ही मिलेगा. पेट संबंधी शिकायत हो सकती है. आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. बिना किसी वजह के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल साबित होंगे. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. अपने सामान के प्रति सचेत रहें. मांगलिक कार्यों में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. आय के नए रास्ते खुलेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
नेत्र विकार या त्वचा के रोग की आशंका है. समय-समय पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें. अचानक कहीं से अप्रिय समाचार मिल सकता है. संतान से संबंधित कोई ख़ुशी मिल सकती है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
अचानक रुके कार्य पूरे होंगे. इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी. मैत्री संबंधों में निकटता आएगी, लेकिन व्यर्थ की परेशानियां व उलझनें फिर भी रहेंगी. आर्थिक क्षेत्र में कुछ नया करने की सोचेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
घर के कार्यों में व्यस्तता अधिक रहेगी. मनोरंजन के सुखद अवसर मिलने की उम्मीद है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. आर्थिक स्थिति ठीकठाक रहेगी. आपको सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

परंपरा है कि अलग-अलग कुंभनगरों में ग्रह-नक्षत्रों की भिन्न स्थिति के चलते कुंभ के प्रमुख स्नान की तिथियां भी अलग होती हैं. हरिद्वार में महाकुंभ का सबसे बड़ा और प्रमुख स्नान मेष संक्रांति को होता है.

अकादमी पुरस्कारों का खेल

अनंत विजय

साल के आख़िरी दिनों में साहित्यिक हलके में अकादमी पुरस्कारों को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो जाती हैं. राजधानी दिल्ली में तो अटकलों का बाज़ार इस कदर गर्म हो जाता है कि तथाकथित साहित्यिक ठेकेदारों की जेब में पुरस्कृत होने वाले लेखकों की सूची रहती है. जहां भी तीन-चार लेखक जुटते हैं, क़यासबाजी का दौर शुरू हो जाता है और गिनती चालू हो जाती है कि किस लेखक की पुस्तक पिछले तीन वर्षों में आई तथा किसका जुगाड़ इस बार फिट बैठ रहा है. किसने अपनी गोटी सेट कर ली है. साहित्य अकादमी और उसके अध्यक्ष को नज़दीक से जानने वालों का मानना है कि इस बार हिंदी लेखक को मिलने वाले पुरस्कार में हिंदी के भाषा संयोजक विश्वनाथ तिवारी की चलेगी. पिछले अध्यक्ष गोपीचंद नारंग के कार्यकाल में उनकी चलती थी और उन्होंने हिंदी के संयोजक एवं वरिष्ठ लेखक गिरिराज किशोर को पुरस्कारों के मामले में पैदल कर दिया था. गिरिराज किशोर को जब यह इलहाम हुआ था तो उन्होंने विरोध का झंडा उठाया था, पर वह कुछ कर नहीं सके थे और गोपीचंद नारंग ने जिसे चाहा, उसे पुरस्कार दे दिया.

अगर अकादमी के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो इस बार साहित्य अकादमी के पुरस्कारों की दौड़ में हिंदी के वरिष्ठ कवि रामदरश मिश्र और कैलाश वाजपेयी सबसे आगे चल रहे हैं. माना जा रहा है कि रामदरश मिश्र को उनके कविता संग्रह पर पुरस्कार मिलना लगभग तय है. लेकिन अगर अंतिम क्षणों में रामदरश मिश्र के नाम पर कोई जिच हुई तो कैलाश वाजपेयी को उनके कविता संग्रह हवा में हस्ताक्षर पर इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल सकता है. साहित्य अकादमी की परंपरा के मुताबिक़ इस बार कविता का नंबर है, क्योंकि पिछले साल गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था. संयोग यह था कि गोविंद मिश्र और हिंदी के संयोजक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी दोनों गोरखपुर इलाक़े के हैं. परंपरा के मुताबिक़ कविता संग्रह को अकादमी पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन भगवान दास मोरवाल का उपन्यास रेत भी एक प्रमुख दावेदार है. पिछले दिनों जब रेत को लेकर विवाद हुआ और मामला अदालत तक जा पहुंचा तो इस बात की भी जोर-शोर से चर्चा हुई कि साहित्य अकादमी ने अब तक किसी दलित लेखक को हिंदी के लिए पुरस्कार नहीं दिया. अगर साहित्य अकादमी अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोना चाहती है तो भगवान दास मोरवाल को इस बार अकादमी अवार्ड मिल सकता है, लेकिन इस किताब पर अदालत में चल रहा मामला मोरवाल को इस दौड़ में पीछे धकेल सकता है. दौड़ में विष्णु खरे, मंजूर ऐहतशाम एवं भगवत रावत आदि भी हैं, लेकिन इनकी संभावना न के बराबर है.

दरअसल साहित्य अकादमी के पुरस्कारों का खेल काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है. प्रक्रिया के मुताबिक़ अकादमी पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित कृतियों की एक आधार सूची बनाती है और हिंदी भाषा की सलाहकार समिति या एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों से उनमें से तीन किताबों का चयन कर सुझाव देने का अनुरोध करती है. एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों को तीन से ज़्यादा कृतियों की सिफ़ारिश करने की भी छूट होती है. जब इन सदस्यों की सिफ़ारिश अकादमी को प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद हर विधा की अलग-अलग सूची बनाई जाती है. मोटे तौर पर एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों की राय मिलने के बाद हर विधा की तीन-तीन किताबों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है. इन तीन किताबों में से तीन सदस्यीय जूरी एक कृति का चुनाव करती है, जिसे पुरस्कृत किया जाता है. लेकिन, किताबों की आधार सूची से लेकर जूरी के चयन तक में जोड़तोड़ और तिकड़मों का ऐसा

खेल खेला जाता है कि सियासत भी शरमा जाती है. अपनी या अपने गिरोह के लेखकों की किताब आधार सूची में डलवाने से इस खेल की शुरुआत होती है. उसके बाद की सारी मशक़्क़त एडवायज़री बोर्ड के सदस्यों के पास से अपने नाम की सिफ़ारिश भिजवाने की होती है. पुरस्कार की चाह में लेखक इसके लिए दिन-रात एक कर देते हैं. इस किले की घेरेबंदी के बाद शुरू होती है कि किसे फाइनल जूरी का सदस्य बनवाया जाए. इस कमिटी के सदस्यों का औपचारिक चुनाव अध्यक्ष की मर्जी से होता है, लेकिन अगर अध्यक्ष की रुचि हिंदी भाषा में न हो या फिर वह इसे लेकर तटस्थ रहे तो फिर हिंदी भाषा के संयोजक का काम आसान हो जाता है और वह अपनी मर्जी के लोगों को जूरी में नामित करवा लेता है. पुरस्कार के लिए किताबों के अंतिम चयन के लिए जूरी की जो बैठक होती है, उसमें भाषा के संयोजक की कोई भूमिका नहीं होती, वह सिर्फ़ बैठक का संयोजन और शुरुआत करते हैं. हालांकि जब नामवर सिंह हिंदी के संयोजक हुआ करते थे तो यह स्थिति नहीं थी. तब नामवर जी की ही मर्जी चला करती थी. एक बार फिर से गोपीचंद नारंग के अध्यक्ष पद से हटने और विश्वनाथ तिवारी के हिंदी के संयोजक बनने के बाद स्थिति लगभग वैसी हो गई है. नामवर जी जैसी दबंगई से तो तिवारी जी काम नहीं करते हैं, लेकिन अंदरखाने चलती तो उन्हीं की है. जबसे विश्वनाथ तिवारी हिंदी भाषा के संयोजक बने हैं, तबसे हिंदी में तो उनकी ही मर्जी चल रही है. अपने पसंदीदा लेखक गोविंद मिश्र को उनकी कमज़ोर कृति पर पुरस्कार दिलवा कर उन्होंने पिछले वर्ष इसे साबित भी किया. जब जूरी के सदस्य फ़ैसला ले लेते हैं तो उसके बाद उस फ़ैसले को एक्ज़ीक्यूटिव कमिटी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अंतिम मुहर अध्यक्ष लगाते हैं, जो सिर्फ़ प्रक्रिया का एक हिस्सा भर है.

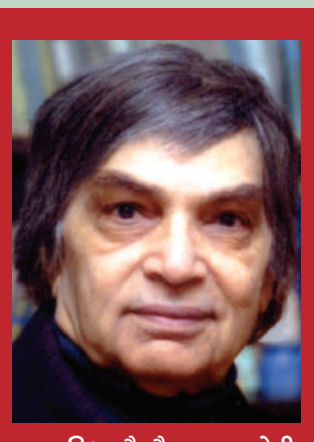

पुरस्कार के दौड़ में सबसे आगे : रामदरश मिश्र और कैलाश वाजपेयी

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय आबादी में नीग्रो

भारत की आबादी के बारे में हम जान चुके हैं कि अलग-अलग समय में दूर देशों से आने वाली जातियों की वजह से यहां की संस्कृति बहुरंगी हुई. आर्य और द्रविड़ भारत की प्रमुख आबादी हैं. मंगोल प्रजाति के लोगों का भी यहां अच्छी संख्या में संकेंद्रण है और थोड़ी संख्या में यहां नीग्रो भी रहते हैं. अटकल और अनुमान से जो बातें अभी तक सामने लाई जा सकी हैं, उनके आधार पर साधारणतः यह समझा जाता है कि भारत आने वाली पहली जाति नीग्रो थी. यह जाति भारत में अरब-ईरान के किनारे-किनारे चलकर पश्चिम से अथवा संभवतः अफ्रीका से आई थी. इसकी एक शाखा भारत से निकल कर ऑस्ट्रेलिया भी गई, जहां उसके वंशज अब तक मौजूद हैं. भारत से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए रास्ते में इंडोनेशिया, पोलीनेशिया और मलेनेशिया में भी इस जाति की टुकड़ियां रह गईं. मलाया, फिलीपाइन, न्यूगिनी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो नीग्रो हैं, वे भी भारत से ही गए हुए हैं. लेकिन भारत में नीग्रो लगभग खत्म हो चुके हैं. अनुमान यह है कि या तो वे अपने पीछे आने वाले आग्नेय लोगों के द्वारा मार डाले गए अथवा उनमें मिलकर एक हो गए और उनकी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रह गई. अब इनके थोड़े से निशान दक्षिण भारत की आदिम जातियों अथवा असम की नागा जाति में बचे हुए हैं. नीग्रो लोग सभ्यता के आरंभिक सोपान पर थे. कहने का तात्पर्य सीधा है कि वे जंगली और असभ्य जीवन जीते थे. सांस्कृतिक तौर पर वे पिछड़े थे. वे अपना भोजन खेतों से उत्पन्न न करके जंगलों में घूमते हुए फल-फूल तोड़कर या जीवों को मारकर प्राप्त करते थे. आखेट उनकी आजीविका का मुख्य जरिया था. जब आर्य इस देश में आए, उस समय तक नीग्रो जाति या तो समाप्त हो चुकी थी या काफी कम संख्या में छिटपुट थी. नीग्रो जाति का काल विद्वान आज से सात हजार वर्ष पूर्व मानते हैं, किंतु संभव है कि यह काल आज से दस हजार वर्ष पूर्व रहा हो.

भारत के दक्षिणतम भाग में बसने वाले कडार और उरली लोग, बहुत संभव है नीग्रो संस्कृति से संबद्ध थे. इस अनुमान का क्षीण आधार यह भी है कि मलाया में सेमांग नामक जंगलों में रहने वाली जो जाति है, वह बांस की कंघी का प्रयोग करती है. इन कंघियों के डिजाइन ठीक वैसे हैं, जैसे कडार जाति की औरतों की कंघियों के होते हैं. लेकिन सिर्फ इस समानता के आधार पर अंतिम और मान्य निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते.

इतिहासकार इस जाति के लोगों को प्राचीन प्रस्तर कालीन मनुष्यों में गिनते हैं. प्राचीन पाषाणकालीन मनुष्यों की आजीविका मुख्यतः शिकार पर निर्भर थी. वे जीवों को मारकर उनके मांस से अपनी भूख मिटाते थे. कोई साहित्य न होने के कारण उनकी प्राचीन भाषा के बारे में कुछ भी अनुमान करना कठिन है, लेकिन दूसरे समुदायों से वे अलग-थलग रहते थे, इसलिए दूसरी संस्कृति या भाषाओं का उनकी संस्कृति या भाषा पर कोई व्यापक प्रभाव पड़ा होगा, इसकी उम्मीद कम ही है. उनकी भाषा का नमूना अब सिर्फ अंडमान में ही शेष है. इसकी वजह भी यही है कि अंडमान में जिन द्वीपों पर ये रहते हैं, वे आज भी दुनिया से एक तरह से कटे हुए हैं. बाकी जगहों पर ये पड़ोसियों की भाषाओं को कुछ बिगड़े रूपों में बोलते हैं.

नीग्रो जाति के बाद आग्नेय, आग्नेय के बाद द्रविड़ और द्रविड़ के बाद आर्य जाति के आने के बाद इस देश में सांस्कृतिक समन्वय का काम शुरू होता है. किंतु, नीग्रो और आर्य, इन दो जातियों के बीच समय की काफी दूरी पड़ती है. इसलिए आर्यों ने हमें जो सभ्यता सौंपी, उस पर नीग्रो सभ्यता का कहां, क्या प्रभाव है, यह आसानी से जाना नहीं जा सकता है. फिर भी

डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी का अनुमान है कि बादुड़ शब्द (जिसका प्रयोग बंगाल और बिहार में एक प्रकार के चमगादड़ के अर्थ में होता है.) नीग्रो भंडार का होगा. एक अन्य विद्वान का अनुमान है कि धनुष चलाने की कला नीग्रो की देन है. नीग्रो जाति सभ्यता से दूर होते हुए भी बड़ी साहसी रही होगी, अन्यथा नावों के सहारे वह भारतीय समुद्र की सैर करने की हिम्मत नहीं करती.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कुंभ मेला शुरू होने में अब देर नहीं

डॉ.कमलकांत बुधकर

हरिद्वार में उत्तराखंड के पहले महाकुंभ का शासकीय मेलाकाल शुरू होने में अब चंद दिन शेष हैं. सरकारी भाषा में कहें तो सदी का दूसरा महाकुंभ बस शुरू ही होने वाला है. सदी का पहला महाकुंभ 2001 में प्रयाग में हुआ था.

हरिद्वार महाकुंभ 2010 का सरकारी मेलाकाल एक जनवरी से 30 अप्रैल 2010 के बीच चार महीनों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन 120 दिनों में केवल तीन दिन ही कुंभ स्नान होना है. सरकारी मेला कैलेंडर में यूं तो इस बीच कुल मिलाकर 11 स्नानों की सूची जारी की गई है, पर कुंभ के मुख्य स्नान तो तीन ही होते हैं, जब संन्यासियों की शाही सवारियां निकलती हैं. उनमें भी एक स्नान ही सर्वप्रमुख माना जाता है.

परंपरा है कि अलग-अलग कुंभनगरों में ग्रह-नक्षत्रों की भिन्न स्थिति के चलते कुंभ के प्रमुख स्नान की तिथियां भी अलग होती हैं. हरिद्वार में महाकुंभ का सबसे बड़ा और प्रमुख स्नान मेष संक्रांति को होता है. गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश के चलते यह दिन सूर्य के मेष राशि में संक्रमण का यानी मेष संक्रांति का दिन होता है. इसी समय हरिद्वार में फ़सल कटने के उल्लासपर्व बैसाखी का परंपरागत स्नान भी संपन्न होता है. इस प्रमुख स्नान के अलावा संन्यासियों के तेरह अखाड़े हरिद्वार में महाशिवरात्रि और चैत्र अमावस्या का स्नान भी करते हैं. लेकिन इन तीन स्नानों के अलावा शासन अपने द्वारा घोषित मेलाकाल के चार महीनों में पड़ने वाले विभिन्न सामान्य पर्व-स्नानों को भी कुंभ स्नान कहकर प्रचारित करता है. ऐसे प्रचार सरकारी स्तर पर कुंभ स्नानार्थियों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर बताने में भी सहायक होते हैं.

सरकारी मेला अवधि के चार महीनों के लिए हरिद्वार एक नए, पर अस्थायी कुंभ ज़िले में परिवर्तित हो जाएगा. जिन दिनों हरिद्वार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का हिस्सा था, तब हरिद्वार के अलावा बिजनौर, टिहरी, पौड़ी और देहरादून ज़िलों से थोड़ा-थोड़ा भाग काटकर अस्थायी कुंभ ज़िला बनाया जाता था. बाद में 1988 में हरिद्वार जब ज़िला बन गया तो बिजनौर का वह हिस्सा, जो कुंभ के निमित्त हरिद्वार में मिलाया जाता था, स्थायी रूप से हरिद्वार का हिस्सा बन गया. वस्तुत: कुंभ क्षेत्र हरिद्वार से ऋषिकेश और उसके भी आगे लक्ष्मण झूला तक फैला हुआ है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र की सीमाएं उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार के अलावा अब अन्य तीन ज़िलों देहरादून, टिहरी और पौड़ी से मिलती हैं. अस्थायी कुंभ ज़िले में पूरा हरिद्वार और उसके सीमावर्ती इन्हीं तीन ज़िलों के कुछ हिस्से मिला दिए जाएंगे. इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा कुंभ मेलाधिकारी और सुरक्षा एवं क़ानून व्यवस्था का जिम्मा पुलिस उपमहानिरीक्षक-कुंभ के पास रहेगा. उत्तराखंड शासन ने मेलाधिकारी के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंदवर्द्धन और कुंभ पुलिस प्रमुख के रूप में डीआईजी आलोक शर्मा की नियुक्ति महीनों पहले करके उन्हें हरिद्वार में तैनात कर दिया है.

प्रशासनिक दृष्टि से मेला अवधि के चार महीनों के लिए संपूर्ण कुंभ ज़िले को बत्तीस सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा. हर सेक्टर को एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक पुलिस उपाधीक्षक के सुपुर्द कर दिया जाएगा. हर सेक्टर में प्रशासन एक थाना, एक अस्पताल और राशन की एक दुकान खोलेगा. सभी सेक्टरों में बिजली और पानी का समुचित प्रबंध किया जाएगा. बड़ी संख्या में अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था सारे कुंभ क्षेत्र में की जाएगी. सामान्य बीमारियों और महामारियों से बचाव के लिए साफ़-सफाई के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएंगे. देश भर से कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले साधु-संतों, उनके अखाड़ों और महामंडलेश्वरों के लिए सुविधायुक्त अस्थायी टेंट कॉलोनियां विकसित की जाएंगी.

इन सारे कार्यों के साथ-साथ पूरे मेला क्षेत्र की अनेक सड़कों की मरम्मत और कुछ के नवनिर्माण, अनेक स्थायी व अस्थायी पुलों के निर्माण, नए विद्युत उपकेंद्रों और जलापूर्ति के लिए पानी की टंकियों के निर्माण आदि कार्य हुए हैं और हो रहे हैं. लेकिन यह सारा काम अख़बारी चर्चाओं और सुर्ख़ियों का विषय बनता रहा है, बन रहा है और कुंभ मेले के दौरान भी बनता रहेगा. मज़े की बात यह है कि पिछले कई महीनों से कुंभ, उससे जुड़ी विभिन्न विभागीय योजनाओं की चर्चा, संबंधित निर्माण और विकास कार्य, उन कार्यों की गुणवत्ता, उनमें प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों का स्तर, उनका विस्तार से वर्णन, उन कार्यों के पूरा होने की अवधि, इसके बहाने किए गए तथाकथित लेनदेन की मसालेदार गपशप आदि कुंभ की अख़बारी चर्चाओं के प्रिय विषय रहे हैं. फिर धीरे-धीरे ये सब राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं के बीच विवाद और परस्पर विरोधी बयानबाजिज़ों का रूप भी ले चुके हैं.

इन दिनों केंद्र और उत्तराखंड राज्य के रिश्तों में भी बड़ी नज़ाकत है. आज़ादी के बाद पहला मौक़ा है कि हरिद्वार के जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य में मंत्रिपदों पर सुशोभित हैं. हरिद्वार के सांसद हरीश रावत केंद्र सरकार में मंत्री हैं तो हरिद्वार के विधायक प्रदेश काबीना के वरिष्ठ सदस्य हैं. एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं तो दूसरे वरिष्ठ भाजपाई. प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो दिल्ली में कांग्रेस का बोलबाला है. दोनों दल, दोनों सरकारें और दोनों ओर के राजनेता कुंभ कार्यों का श्रेय लेने के चक्कर में एक दूसरे की थुक्का-फजीहत करने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ते.

राज्य सरकार के पास पिछले कई दिनों से लगातार एक ही मुद्दा बना हुआ था कि केंद्र सरकार कुंभ के नाम पर कोई सहायता नहीं दे रही है और 400 करोड़ रुपये देने का वादा करके भी मुकर रही है. छोटा सा राज्य उत्तराखंड अकेले अपने सिर महाकुंभ का इतना भारी बोझ ले तो कैसे ले. राज्य का आरोप था कि केंद्र जो 300 करोड़ रुपये की सहायता राशि वार्षिक अनुदान के रूप में देता है, उसी में से कुंभ सहायता निकालने की चालबाजी कर रहा है. लेकिन केंद्र से हरिद्वार आई योजना आयोग की टीम ने 14 दिसंबर को ही स्पष्ट कर दिया था कि पिछले वर्ष जो 300 करोड़ रुपये राज्य की सहायता के लिए दिए गए थे, वह राशि इस वर्ष दस प्रतिशत बढ़ाकर यानी 330 करोड़ रुपये करके दी जा रही है. इसके अलावा 400 करोड़ रुपये की कुंभ सहायता भी केंद्र राज्य को अलग से दे रहा है.

इस घोषणा से गेंद दोबारा राज्य के पाले में आ गिरी है. बहरहाल स्वयं को देवता और दूसरे को दानव साबित करने में जुटे दोनों राजनीतिक दल कुंभ के अमृत कलश से निजी और पार्टी के कलश को भर लेना चाहते हैं. पुराकथा यह है कि सागर मंथन में पहले लक्ष्मी आईं और बाद में अमृतकुंभ. सो, आज के देवता और दैत्य दोनों ही पहले लक्ष्मी पूजन कर लेना चाहते हैं. इसलिए कुंभ कार्यों में भी इन दिनों पहले लक्ष्मी पूजन को ही तरजीह दी जा रही है. अंदरूनी जानकारों का यहां तक कहना है कि अमृत छकने के मामले में दिल्ली और देहरादून दोनों के मंत्रिगण मित्र हैं! कुंभ कार्यों के बहाने हर बार हटाए जाने वाले शहरी अतिक्रमण में भी राजनीति हावी है. अपने वोट बैंक को प्रभावित होता देखकर मंत्रिगण नहीं चाहते कि अतिक्रमण हटाया जाए. यह बात व्यवस्था में अवरोध बन रही है.

उधर मीडिया में कुंभ कार्यों की छीछालेदर होते देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. निशंक चिंतित हैं और अपनी हर हरिद्वार यात्रा में मीडिया को उपदेश दे जाते हैं कि विश्व के इस महानतम मेले के आयोजन को प्रेस वाले आलोचना का नहीं, गौरव का विषय बनाएं. व्यवस्थापकों को खलनायक नहीं, बल्कि नायक बनाएं. आरोप-प्रत्यारोप के बीच जो कुछ चल रहा है, उससे अंतत: आम जनता और कुंभ मेले को ही प्रभावित होना है. इसलिए जनता के मुंह पर एक ही बात है, प्रभु करें, मेला ठीकठाक निबट जाए.

kk@budhkar.in

चर्चा कुंभनगर की

श्री गंगा मंदिर (बाएं) 1880 में और (दाएं) 1930 में

आनंद वर्धन
मेला अधिकारी

आलोक शर्मा
डीआईजी, कुंभ

शासकीय महाकुंभ मेला (एक जनवरी से 30 अप्रैल 2010) महाकुंभ के शाही स्नानों की तिथियां

प्रथम शाही स्नान : महाशिवरात्रि, शुक्रवार, 12 फरवरी 2010

द्वितीय शाही स्नान : चैत्र अमावस्या (सोमवती), सोमवार, 15 मार्च 2010

तृतीय एवं प्रमुख शाही स्नान : मेष संक्रांति कुंभपर्व, बुधवार, 14 अप्रैल 2010

अन्य सामान्य स्नान पर्व

मकर संक्रांति : गुरुवार, 14 जनवरी 2010

मौनी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण : मंगलवार, 15 जनवरी 2010

वसंत पंचमी : बुधवार, 20 जनवरी 2010

माघी पूर्णिमा : शनिवार, 30 जनवरी 2010

नव संवत्सर : मंगलवार, 16 मार्च 2010

रामनवमी : बुधवार, 24 मार्च 2010

चैत्र पूर्णिमा : मंगलवार, 30 मार्च 2010

बैसाखी पूर्णिमा : बुधवार, 28 अप्रैल 2010

शाही स्नान के लिए तेरह अखाड़ों का स्नानक्रम

दशनामी संन्यासियों के सात अखाड़े

- पंचायती श्रीतपोनिधि निरंजनी अखाड़ा
- पंचायती श्री आनंद अखाड़ा (श्री निरंजनी अखाड़े के साथ)
- पंच दशनाम श्रीजूना भैरव अखाड़ा
- पंचायती श्री अग्नि अखाड़ा (श्रीजूना भैरव अखाड़े के साथ)
- पंचायती श्री आवाहन अखाड़ा (श्रीजूना भैरव अखाड़े के साथ)
- पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा
- पंचायती श्री अटल अखाड़ा (श्री महानिर्वाणी अखाड़े के साथ)

बैरागी साधुओं के तीन वैष्णव अखाड़े

- श्री निर्वाणी अणि अखाड़ा
- श्री दिगंबर अणि अखाड़ा
- श्री निर्मोही अणि अखाड़ा

उदासीन साधुओं के दो अखाड़े

- श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन
- श्री पंचायती अखाड़ा छोटा उदासीन

सिख साधुओं का एक अखाड़ा

- श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा

यह है वाटर प्रूफ़ कैमरा. इसमें पांच-पांच मोड में वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा है. यह कैमरा आपको न्वाइज़ और ब्लर फ्री तस्वीर देता है, यानी यह बदलते ज़माने का बदलता हुआ कैमरा है.

दिल्ली, 28 दिसंबर 2009-3 जनवरी 2010
चौथी दुनिया

फोटो-प्रभात पाण्डेय

नई दिल्ली में अभिनेत्री सोहा अली ख़ान के साथ सन डायरेक्ट टीवी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टोनी डी सिल्वा सन हाई डिफिनेशन सेट टॉप बॉक्स लांच करते हुए.

माइक्रोवेव में यू ट्यूब

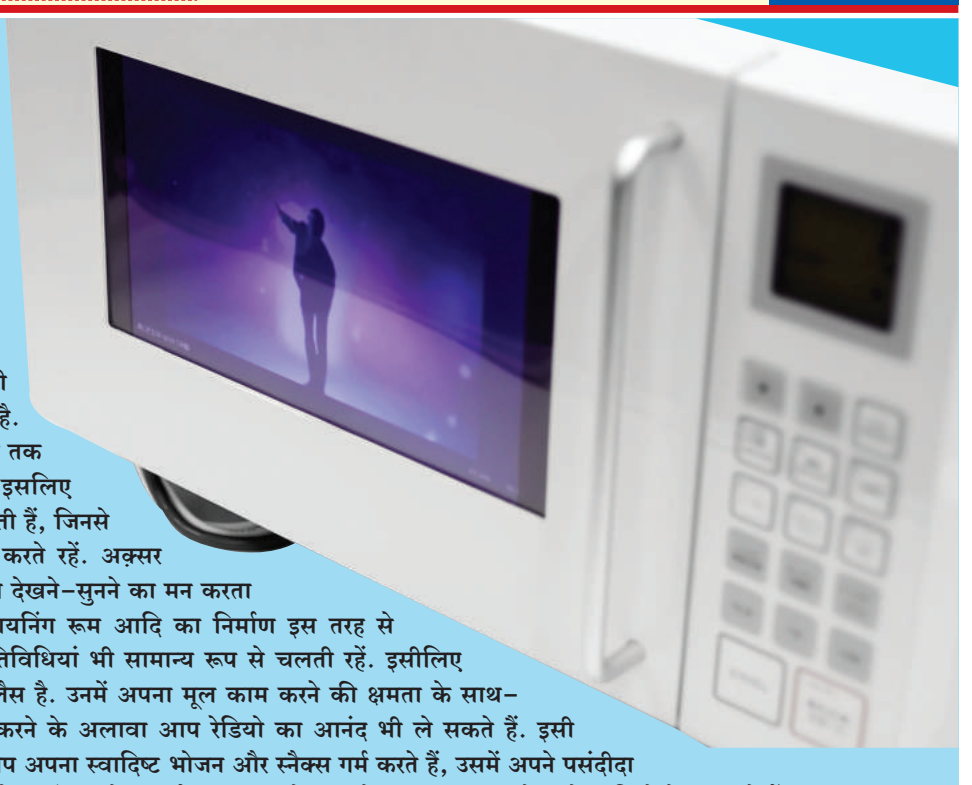

आज का युग व्यस्तता का युग है. हर किसी को अपना काम करने की जल्दी रहती है. टिकट बुकिंग से लेकर किचन की कुकिंग तक लोग जल्दबाज़ी में दिखाई देते हैं. इसलिए कंपनियां भी बाज़ार में इस तरह के उत्पाद उतारती रहती हैं, जिनसे लोग समय की बचत के साथ-साथ मनोरंजन भी करते रहें. अक़्सर खाना पकाते समय टीवी पर समाचार या गीत-संगीत देखने-सुनने का मन करता है. इसी वजह से आज लोग अपने किचन और डायनिंग रूम आदि का निर्माण इस तरह से करवाते हैं कि किचन में काम करते-करते अन्य गतिविधियां भी सामान्य रूप से चलती रहें. इसीलिए आज हर गैजेट और टेक्नोलॉजी कई सुविधाओं से लैस है. उनमें अपना मूल काम करने की क्षमता के साथ-साथ कई एक्सट्रा फ़ीचर भी हैं. मोबाइल पर बात करने के अलावा आप रेडियो का आनंद भी ले सकते हैं. इसी तरह कभी आपने सोचा था कि जिस माइक्रोवव में आप अपना स्वादिष्ट भोजन और स्नैक्स गर्म करते हैं, उसमें अपने पसंदीदा वीडियो भी देख सकेंगे? यक़ीनन नहीं. लेकिन, अब ऐसा संभव हो गया है. आप अपने माइक्रोवव पर यू ट्यूब के सारे वीडियो देख सकते हैं. यह करिश्मा हुआ है कीटा वॉटेनेबल और शोटा मत्शूदा के संयुक्त प्रयास से. इन दोनों ने मिलकर इस माइक्रोवेव को ईज़ाद किया है. इसमें कोई मीडिया प्लेयर इन बिल्ट नहीं है. इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके इस सुविधा का मज़ा लिया जा सकता है. इसके लिए कंपनी ने 10 इंच का एलसीडी डिस्प्ले दिया है. यह स्क्रीन उस स्थान पर है, जहां सामान्यत: पारदर्शी शीशे की मदद से हम अपने फूड आइटम को ग्रिल होते हुए देखते हैं. अब इस स्क्रीन में आप सेटिंग के ज़रिए जो भी वक़्त सेट करेंगे, उसी के दौरान यह कंप्यूटर से वीडियो सर्च करेगा. साथ ही समय पूरा होते ही आपको सूचित कर देगा कि आपकी डिश तैयार है. है न डबल मज़ा! इसको बनाने वाले शोटा का कहना है कि आमतौर पर हम माइक्रोवेव का प्रयोग करते समय उसी के इर्द-गिर्द रहते हैं, ताकि जो भी चीज़ गर्म कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग का ख्याल रहे और वह जल न जाए. लेकिन, इस सबके दौरान बोरियत महसूस होने लगती है. ऐसे में हमें विचार आया कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए, जिससे लोग बोर न हों और काम भी हो जाए. लोगों की रुचि आजकल कंप्यूटर में वीडियो देखने की है. बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें कंप्यूटर कनेक्टिविटी की सुविधा दी है. इसके कुछ मॉडल चुने हुए स्टोर्स के शोकेस में रखे गए हैं, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद ही कंपनी इसे पूरी तरह बाज़ार में उतारेगी.

मल्टी टच सिस्टम लाने की कोशिश

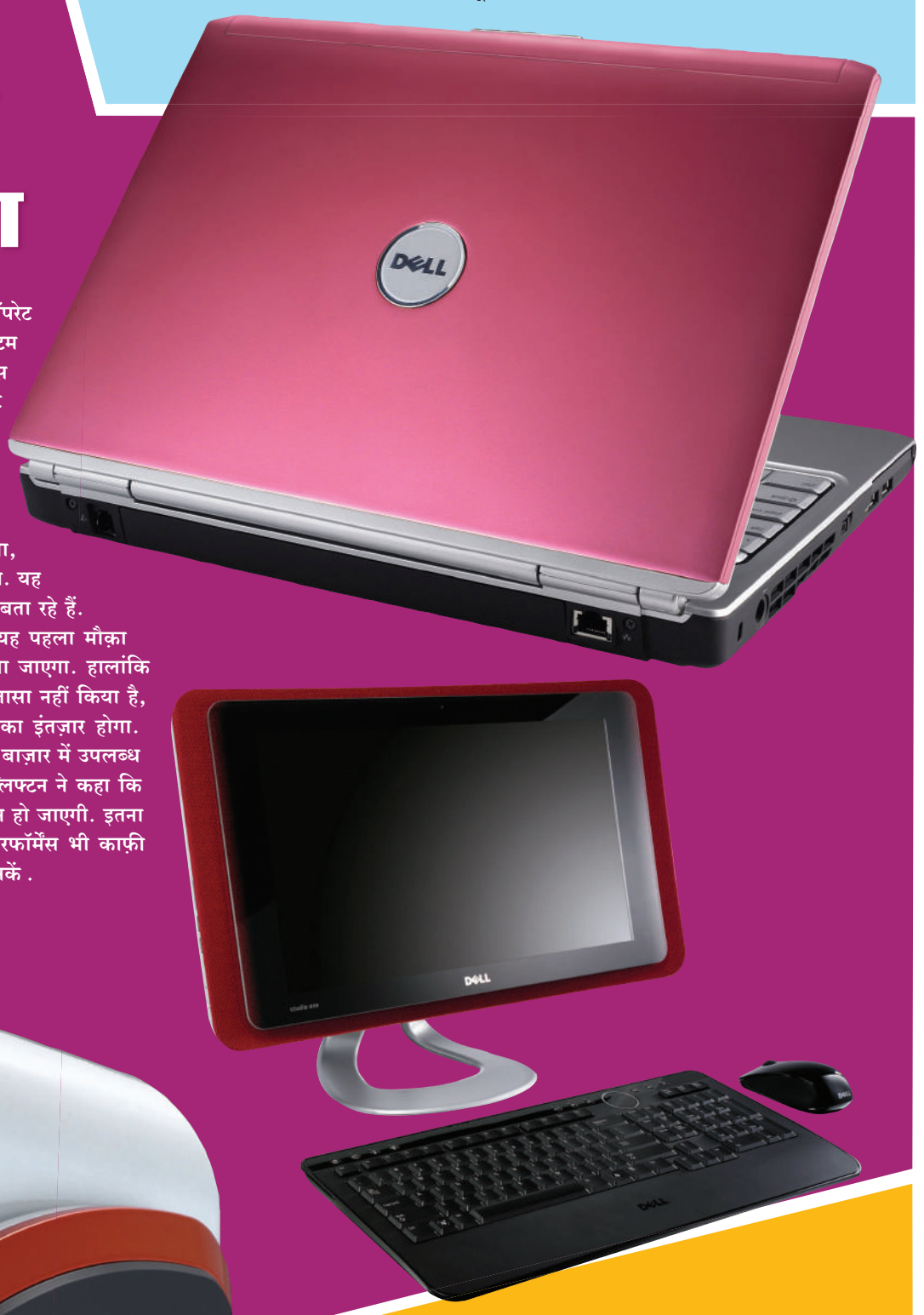

डेल ने टच स्क्रीन सिस्टम लांच करने की घोषणा की है, जिसे ऑपरेट करने में काफ़ी सहूलियत होगी. ऐसा नहीं है कि टच स्क्रीन सिस्टम सिर्फ़ नोटबुक में होगा, बल्कि डेस्कटॉप भी इस सुविधा से लैस होगा. ग़ौरतलब है कि दोनों सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़-7 (टच प्लेटफॉर्म) का उपयोग किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक़, डेस्कटॉप मॉडल इंस्पिरियोन वन-19 ऑल-इन-वन सिस्टम से लैस होगा. इस सिस्टम में 19 इंच का स्क्रीन होगा. ताकि आपको बड़ी स्क्रीन और स्पष्ट रेजॉल्यूशन में काम करने का आनंद मिले. हालांकि इसकी क़ीमत के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अनुमान के मुताबिक़, इसका मूल्य लगभग 499 पौंड होगा. यह तो हुई डेस्कटॉप की बात. अब हम आपको नोटबुक के बारे में बता रहे हैं. नोटबुक सिस्टम को स्टीडियो-17 के नाम से जाना जाएगा. यह पहला मौक़ा होगा, जब डेल की तरफ़ से टच इंटरफेस सिस्टम लांच किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने इस 17.3 इंच के मॉडल की क़ीमत के बारे में ख़ुलासा नहीं किया है, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि लोगों को बेसब्री से इसका इंतज़ार होगा. उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक यह मॉडल बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा. डेल यूरोप के कंज्यूमर मार्केटिंग हेड डेविड क्लिफ्टन ने कहा कि टच स्क्रीन से सभी उम्र के लोगों के लिए कंप्यूटिंग आसान हो जाएगी. इतना ही नहीं, दोनों प्रोडक्ट का लुक काफ़ी स्टाइलिश है. परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, ताकि लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें.

नोकिया का नया मॉडल 5235

नोकिया 5230 के बाद अब समय है नोकिया के नए मोबाइल 5235 के स्वागत का. वैसे संगीत प्रेमियों के लिए यह फोन काफ़ी अच्छा है. हालांकि यह म्यूजिक एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन संगीत प्रेमी इससे निराश नहीं होंगे. अब आप इस नए मोबाइल फोन 5235 से अपने दोस्तों को हेलो कहिए. हालांकि न तो 5230 ब्रांडेड एक्सप्रेस म्यूजिक फोन था और न ही 5235 है. बावजूद इसके यह संगीत की सुविधा से लैस है.

नोकिया 5235 की मार्केटिंग *कम्स विद म्यूजिक* मोबाइल फोन के तौर पर की जा रही है. मतलब यह कि इस मोबाइल में ऑडियो ट्रैक पहले से लोड है. यह सुविधा उपभोक्ताओं को म्यूजिक लाइब्रेरी एक्सेस करने और फ्री में ट्रैक डाउन लोड करने की स्वीकृति देगी. यह फोन देखने में कुछ हद तक 5230 की तरह ही लगता है. इसके फ़ीचर्स भी ऐसे हैं, जिन्हें देखकर आप काफ़ी ख़ुश होंगे. इसमें 3.2 इंच का प्रतिरोधक टच स्क्रीन लगा हुआ है, जो सिम्बियन एस 6-वी 5 स्टैंडर्ड का रेजॉल्यूशन देता है. इतना ही नहीं, इसमें 3जी कनेक्टिविटी और ओवीआई भी है, जो 3जी को सपोर्ट करता है. हालांकि इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है. इसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है. इसमें 16 जीबी तक एक्सटरनल मेमोरी आप लगा सकते हैं. इसकी अनुमानित क़ीमत दस हज़ार रुपये है और उम्मीद की जा रही है कि यह 2010 के मार्च तक बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा.

सान्यो का वाटरप्रूफ कैमरा

भारत में डिजिटल कैमरों का बाज़ार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर रही हैं. इसमें अब सान्यो का नाम भी जुड़ गया है. जापान की इस कंपनी ने हाल ही में डिजिटल कैमरों की नई रेंज जारी करने की घोषणा की है. इस रेंज में एक्स एसीटीआई सीए-6 कई मायनों में ख़ास है. इस स्पोर्ट मॉडल में 6 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके वेदरप्रूफ़ और वाटरप्रूफ़ फ़ीचर्स. अगर आप पानी में खेलने और यात्रा-देशाटन के शौक़ीन हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है. ख़राब मौसम में भी यह काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि इसकी वेदरप्रूफ़ तकनीक प्रकाश, अपर्चर और उपयुक्त मोड को अपने आप सेट कर आपको बेहतरीन इमेज देती है. इसके अलावा आप 640.480 रेजॉल्यूशन का वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा पाते हैं. साथ ही इसका वेब एसएचक्यू मोड भी लाजवाब है, जिसकी मदद से आप वीडियो आईपॉड (आर) और अन्य एमपीइजी-4 प्लेयर से भी वीडियो कैप्चर कर सकते हैं. इसमें पांच-पांच मोड में वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है. 2.0 इंच की टीएफटी स्क्रीन में पिक्चर की क्वालिटी और भी बेहतर दिखाई देती है. यह कैमरा आपको न्वाइज़ और ब्लर फ्री तस्वीर देता है. इसमें और भी कई ख़ूबियां हैं, जो ख़रीदने के बाद आपको मैनुअल फ़ीचर बुकलेट में दिखाई देंगी. रही बात क़ीमत की, आपको अपनी जेब से सिर्फ़ 399.99 डॉलर ही ढीले करने पड़ेंगे.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

क्रिकेट में जो दर्ज़ा सचिन तेंदुलकर को मिला है, उससे अधिक सम्मान और शोहरत टाइगर वुड्स को हासिल था, लेकिन उनकी एक ग़लती ने उनके ईमानदार और एक सभ्य इंसान के मुखौटे को उतार फेंका है.

टाइगर वुड्स ने तोड़ा दुनिया का भरोसा

खेलों की दुनिया में उत्थान के साथ-साथ पतन भी एक कड़वी सच्चाई है. जो खिलाड़ी एक पल सफलता के शिखर पर होता है, अगले ही पल उसकी सफलता का सिंहासन डगमगाने लगता है. यहां हम जिस सितारे की बात कर रहे हैं, उनका करियर तो बुलंदियों पर है, लेकिन निजी ज़िंदगी में आए भूचाल ने इनके करियर पर भी ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है. हम जिस सितारे की बात कर रहे हैं, वह दुनिया के सबसे महंगे खेल गोल्फ के खिलाड़ी टाइगर वुड्स हैं.

टाइगर वुड्स ने महज़ दो साल की उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया था और पिछले साल वुड्स ने अपने करियर का आख़िरी सबसे बड़ा ख़िताब यू एस ओपन जीता. इस दरम्यान वुड्स ने न जाने कितनी ख़िताबें अपने नाम कीं. यानी गोल्फ की दुनिया में वुड्स का डंका हर तरफ़ बोला. वुड्स अभी तक इतनी शोहरत हासिल कर चुके हैं कि हाल ही में उन्हें इस दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी घोषित किया गया है, लेकिन टाइगर वुड्स रूपी इस खिलाड़ी की शोहरत रातोंरात आसमान की बुलंदियों पर नहीं पहुंची. पदक दर पदक, साल दर साल और इ स खिलाड़ी का खेल के प्रति समर्पण ने ही वुड्स को टाइगर वुड्स बनाया. लेकिन इस खिलाड़ी को आसमां से ज़मीन तक आने में महज़ दो मिनट से भी कम वक़्त लगा. यह दो मिनट से भी कम का वक़्त वह है, जब वुड्स फ्लोरिडा के अपने आठ मिलियन डॉलर के घर से गाड़ी चलाते हुए बाहर निकले और अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर बैठे. दुनिया में हादसों का होना कोई नई बात नहीं है. इसके पहले भी कई मशहूर हस्तियों की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होती रही हैं. लेकिन वुड्स की इस एक ग़लती ने उनके चेहरे से उनकी ईमानदारी और एक सभ्य इंसान के मुखौटे को उतार फेंका. दुनिया जिसे अभी तक सबसे अमीर और बेहतरीन चरित्र वाला खिलाड़ी के तौर पर जानती आ रही थी, इस एक कार दुर्घटना ने उनके सभी चाल-चरित्रों की पोल पट्टी खोल कर रख दी. सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

पूरी दुनिया में जितनी चर्चा कोपेनहेगन में हो रहे जलवायु परिवर्तन बैठक की नहीं हुई, उससे कहीं अधिक टाइगर वुड्स प्रकरण की हुई है. भला हो भी क्यों नहीं. ज़रा सोचिए भारतीय क्रिकेट या कहें की क्रिकेट का भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर और इसी तेंदुलकर पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगे और वह साबित भी हो जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इससे भी बढ़कर यदि आपको यह पता चले कि तेंदुलकर के एक नहीं और न ही दो, बल्कि चौदह महिलाओं से अवैध संबंध हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हालांकि वुड्स ने मैच फिक्सिंग जैसी गुनाह नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी अख़बारों से आ रही ख़बरों की मानें तो वुड्स के 14 महिलाओं से अवैध शारीरिक संबंध ज़रूर रहे हैं. इस बात की तस्दीक वे महिलाएं भी कर रहीं हैं, जिनके संबंध टाइगर वुड्स से रहे हैं.

दुनिया के तमाम खेलों में साधारण से लेकर महान खिलाड़ी तक हुए हैं, यहां तक कि टाइगर वुड्स जैसे तेज़तर्रार खिलाड़ी भी हैं. लेकिन मैदान पर और उससे बाहर की अब तक की गतिविधियों ने ही वुड्स को बाक़ी खिलाड़ियों से विशिष्ट बनाया है. पर जिसकी वजह से वुड्स की निजी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बादी के कगार पर आ चुकी है. यहां तक कि उनकी पत्नी ने तलाक़ की बात कह दी है. ऐसे में लगता है कि जिसे हम अभी तक महान और बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर जान रहे थे, वह ठीक उसके उलट निकला है, तो एक खेल प्रशंसक ही नहीं पूरी दुनिया के यक़ीन को ठेस पहुंचता है. और यही काम टाइगर वुड्स ने किया है.

भारतीय फुटबॉल में बदलाव की ज़रूरत

पिछले दो साल में तीन ख़िताब और घरेलू मैदानों पर सौ फ़ीसदी सफलता दर. कुछ यही कहानी है भारतीय फुटबॉल टीम की, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देने का काम सिफ़र ही नज़र आ रहा है. भारत ने पिछले कुछ समय में मैच दर मैच यह साबित किया है कि यदि उसे कुछ बेहतर अवसर और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो आने वाले चंद दिनों में ही वह इस क्षेत्र में एक महाशक्ति के तौर पर उभर सकता है. हाल में भारतीय टीम का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, उससे इस बात में शक़ की कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती है. भारत ने अपने घर में दो बार नेहरू कप जीता. उसके बाद एएफसी कप अपने नाम किया, जिसकी वजह से 24 साल के लंबे अंतराल के बाद 2011 में होने वाले एशिया कप में इसे खेलने का मौक़ा मिला है. लेकिन इन सबके बावजूद कप्तान बाइचुंग भुटिया ख़ुश नज़र नहीं आ रहे हैं. इसकी ख़ास वजह भी है. घरेलू मैदानों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी भारतीय फुटबॉल टीम को विदेशों में खेलने का अवसर नहीं मिल रहा है. यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि फुटबॉल संघ इसे बढ़ावा देने पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा है. जिसका ख़ामियाज़ा भारतीय फुटबॉल को भुगतना पड़ रहा है. वह महज़ क्लब स्तर की टीम बनकर रह जा रही है. भारतीय कप्तान की मानें तो एशिया कप में बस 11 महीने का वक़्त बचा है और यदि भारतीय टीम इस ख़िताब को भी अपने नाम करना चाहती है तो उसे घरेलू मैदानों के बजाय विदेशी मैदानों पर अधिक खेलने की ज़रूरत है. हाल में ही फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और अध्यक्ष की कुर्सी प्रियरंजन दास मुंशी की जगह प्रफुल्ल पटेल ने संभाली है. उम्मीद है अध्यक्ष के बदलने के साथ ही इस संघ की कार्यप्रणाली में भी बदलाव होगा और नए साल में भारत को विदेशों में भी अधिक खेलने का मौक़ा मिलेगा, ताकि भारत फुटबॉल के क्षेत्र में भी एक ज़बरदस्त चुनौती बनकर उभर सके.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

spice
www.spice-mobile.com

अब सब खल्लास!

मल्टी-सिम M-4580 की आकर्षक कीमत और भरपूर खूबियाँ करे सबको खल्लास।

M-4580
किलर खूबी: बड़ी बैट्री
25 दिनों का स्टैंड-बाइ टाइम और 10 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी-सिम (GSM/GSM)
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
वन-टच टॉर्च और करैन्सी चैकर
4 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 2149

M-5252
10 दिनों का स्टैंड-बाइ टाइम और 4 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी-सिम (GSM/GSM)
डिजिटल कैमेरा
बिल्ट-इन FM एंटेना
ड्यूअल LED टॉर्च
8 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 3049

C-5300
सभी CDMA कनेक्शन के साथ चले
बड़ी स्क्रीन
डिजिटल कैमेरा
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
एक्सपैन्डेबल मैमोरी
वन-टच टॉर्च
BEST BUY PRICE: Rs. 2999

बड़ी स्क्रीन | बड़ी मैमोरी | बड़ा साउण्ड | बड़ी बैट्री

big series

Spice Mobiles come loaded with:
emergic email2sms Mail on Mobile | Shuffle Ring tone | mGurujee | ibibo i build · i bond | REUTERS | Mobile Tracker

Registered Office: Spice Mobiles Ltd., D-1, Sector-3, Noida 201301, Uttar Pradesh, India. Fax: +91-120-4363845. E-mail: contactus@spicemobile.in. Spice Mobile Phones are available at all leading telecom outlets. *Conditions apply. Price features and specifications are subject to change without prior notice. Some of the listed capacity is used for phone functions and thus available capacity could be less than the quoted figure. Battery operation time may vary depending on network usage, environment, music and video formats.
www.itsaugust.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया दिल्ली, 28 दिसंबर 2009–3 जनवरी 2010

साउंड ऑफ़ सोफ़ी एल्बम में मशहूर वीजे सोफ़ी ने अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा दिखाई है, वह भी पांच अलग अलग आवाज़ों में गाकर .

कंगना का संदेश

कंगना रानावत फ़िलहाल अपनी आनेवाली फ़िल्म *तनु वेड्स मनु* की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फ़िल्म में उनके साथ पहली बार आर माधवन नज़र आएंगे. वैसे कंगना इन दिनों समाज में महिलाओं को बराबरी का हक़ दिलाने के कामों में भी काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं. टेलीविजन सीरियल *प्रतिज्ञा* को सपोर्ट करती हुई वह कहती हैं कि बड़े शहरों की महिलाएं पढ़ी-लिखी होने के कारण वह सही ग़लत का फ़ैसला करने में सक्षम होती हैं. लेकिन गांवों और छोटे शहरों में रहने वाली महिलाएं कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ होने की वजह से अपना फ़ैसला ख़ुद करने में कमज़ोर पड़ जाती हैं. कंगना का मानना है कि देश के शहरों और महानगरों में तो महिलाओं का विकास हुआ है, पर गांवों में स्थिति अब भी गंभीर है. वहां लड़कियों के साथ घर और समाज हर जगह भेदभाव देखने को मिलता है. अपनी बहन रंगोली के साथ हुए हादसे को याद करते हुए वह कहती हैं कि अपने बचाव में लड़कियां कोई साहसिक क़दम नहीं उठा पाती हैं. एक्टिंग की दुनिया में व्यस्त रहने वाली कंगना सामाजिक सरोकारों के प्रति भी सजग हैं. यह देखकर अच्छा लगता है पर उनकी यह सोच राजनीति में उनकी दिलचस्पी का कोई संकेत तो नहीं है!

बॉलीवुड ही मंज़िल है

फ़िल्मों में आने वाली अभिनेत्रियों में अक़्सर दो बातें एक जैसी होती हैं. एक तो यह कि ये अभिनेत्रियां किसी सौंदर्य प्रतियोगिता से निकल कर सामने आई होती हैं या फिर वे मॉडलिंग जगत का जाना माना नाम होती है. उदाहरण के तौर पर प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता और दीपिका पादुकोण का नाम ले सकते हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं ख़ूबसूरत मॉडल दीप्ति गुजराल. जी हां, किंग फ़िशर के कैलेंडर पर अपनी ख़ूबसूरती दर्ज़ करा चुकीं दीप्ति अब बॉलीवुड में अपनी क़िस्मत आज़माएंगी. एक फर्नीचर कंपनी के विज्ञापन के फोटोशूट के दौरान हाल ही में उन्होंने इस बात का ख़ुलासा किया है. हालांकि उनके पास कई ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन वह जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहती हैं. बकौल दीप्ति किसी रोमांटिक फ़िल्म से वह बॉलीवुड में अपना आग़ाज़ करना चाहती हैं. चलिए इंतज़ार करते हैं दीप्ति के शानदार जलवों का.

लोगों को हंसाना पसंद करूंगी: अंजना

अमिताभ बच्चन के साथ कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट के विज्ञापन में काम कर चुकी अंजना सुखानी इन दिनों फ़िल्म *तुम मिलो तो सही* की शूटिंग में व्यस्त हैं. बॉलीवुड से उनका संबंध ज़्यादा पुराना नहीं है. जयपुर की रहने वाली अंजना ने बॉलीवुड की कई बड़ी फ़िल्मों में काम किया है. जिसमें *सलाम ए इश्क, गोलमाल रिटर्न* जैसी फ़िल्में प्रमुख हैं. फ़िल्म *सलाम ए इश्क* में अनिल कपूर के साथ उनके चुंबन दृश्य को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुईं थीं. बॉलीवुड में क़दम रखने से पहले सेक्सी सुखानी ने लगभग 40 विज्ञापन फ़िल्मों के साथ एक म्यूजिक विडियो एल्बम *दुल्हनियां मर जाएगी*, भी कर चुकी हैं. फ़िल्मों में उनके अंगप्रदर्शन के सवाल पर वह कहती हैं कि अंगप्रर्दशन से उन्हें ऐतराज़ नहीं है. फ़िल्म की स्क्रिप्ट में अगर इस तरह के दृश्यों की आवश्यकता होगी तो ही वह इन्हें करेगी, बेवजह नहीं करेंगी. हां, लोगों को हंसाना वह ज़रूर पसंद करेंगी. उनकी फ़िल्म *तुम मिलो तो सही* एक सोशल ड्रामा है. कबीर सदानंद द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म को लेकर अंजना बेहद उत्साहित हैं.

जीवन सपनों का सफ़र है

वह वीडियो जॉकी रह चुकी हैं. उन्होंने सिंगिंग भी की है. और हां, साथ में डांस और एक्टिंग में भी हाथपांव मार चुकी हैं. हम बात कर रहे हैं सोफी चौधरी की. वह एक बार फिर से संगीत का जादू चलाने वाली हैं. अपने लेटेस्ट म्यूजिक अल्बम *साउंड ऑफ सोफ़ी* में पांच अलग अलग प्रकार की आवाज़ें देकर उन्होंने लोगों को चकित किया है. लोग उनकी तुलना अब दो तरह की आवाज़ में गाना गाने वाले हिमेश रेशमिया से करने लगे हैं. बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि वह उनसे भी दो क़दम आगे निकल गई हैं. पांच तरह की आवाज़ में सुर लगाने का श्रेय सोफ़ी अपने जीवन के अनुभव को देती हैं. बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले सोफ़ी ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है. लंदन से मुंबई आने और यहां सेटल करने को वह अपनी जीवन यात्रा बताती हैं. वह कहती हैं- सपनों के इस सफ़र का मैं भरपूर लुत्फ़ भी उठा रही हूं. मैंने कई देशों की यात्राएं की हैं और सबके साथ मीठी यादें जुड़ी हैं. उन जगहों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. वक़्त वक़्त पर लोगों को मेरे काम में भी यह नज़र आता रहेगा. इसके अलावा अलग-अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने से भी मेरी आवाज़ में निखार आया है. *साउंड ऑफ सोफ़ी* को वह अपने अनुभवों का ही परिणाम मानती हैं. दुनिया के कई देशों का दर्शन कर चुकी सोफ़ी को भारत में गोवा मुझे बेहद पसंद है. सोफ़ी इसकी वजह भी बताती हैं, मुझे समुद्र के किनारों पर देर रात तक पार्टी करना काफ़ी अच्छा लगता है. उम्मीद है सोफ़ी ने नए साल की मस्ती के लिए गोवा के किसी होटल में अपनी जगह बुक करा ली होगी.

कायनात की क़यामत

अपने दिनों की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की चचेरी बहन कायनात अरोड़ा बॉलीवुड में क़यामत ढाने को तैयार हैं. लगभग दो साल पहले दिल्ली से मुंबई पहुंची कायनात को आप प्रियदर्शन की आने वाली फ़िल्म *खट्टा-मीठा* में देख पाएंगे. अक्षय कुमार इस फ़िल्म के नायक हैं और कायनात ने इस फ़िल्म में गज़ब का आइटम नंबर किया है. वैसे वह फ़िल्म *गुपचुप- गुपचुप* में भी नज़र आएंगी. कायनात बचपन से ही अपनी बहन दिव्या भारती की अभिनय प्रतिभा की कायल रही हैं. फिल्म इंडस्ट्री में वह दिव्या जैसी ही कामयाब होना चाहती हैं. सारंगपुर में पैदा हुई कायनात ने उसी सेंट मेरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की जहां से उसकी बहन दिव्या ने. बाद में कायनात ने दिल्ली के निफ्ट से पढ़ाई की और कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट पूरे किए और जब लगा कि हमें तो अभिनय करना है, फिर मुंबई आ गईं. दिव्या भारती के पति और अपने जीजा साजिद नाडियाडवाला से मिलने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी. प्रियदर्शन की फ़िल्म में आइटम नंबर करने से पहले कायनात ने उनके साथ तीन विज्ञापन फ़िल्में भी की हैं. कॉमिक थ्रिलर फ़िल्म गुपचुप गुपचुप में अकेली महिला किरदार होने से कायनात बेहद ख़ुश हैं. कायनात ने इंडस्ट्री में अभी-अभी क़दम रखा है और गुपचुप गुपचुप उनकी पहली फ़िल्म है. अब वह अपनी बहन दिव्या जैसा कमाल दिखा पाती हैं या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फ़िल्म प्रीव्यू

प्यार इंपॉसिबल

यश चोपड़ा ने अपने बेटे उदय चोपड़ा को स्टार बनाने की मानो कसम खा रखी है. तभी तो वह उसे तीसरी बार लांच कर रहे हैं. अपना लांचिंग स्टेशन और अपना ही रॉकेट. आठ जनवरी को प्रदर्शित हो रही फ़िल्म *प्यार इंपॉसिबल* में उदय और प्रियंका चोपड़ा पहली बार एक साथ काम करेंगे. फ़िल्म का निर्देशन एक्टर से डायरेक्टर बने जुगल हंसराज ने किया है. जुगल इससे पहले एनीमेशन फ़िल्म *रोड साइड रोमियो* से हाथ जला चुके हैं. ऐसे में यश चोपड़ा ने जुगल के हाथों निर्देशन का ज़िम्मा देकर जोख़िम का काम किया है. फ़िल्म रोमांटिक कॉमेडी है. हॉलीवुड की दो मशहूर फ़िल्में *नॉटिंग हिल* और *जस्ट फ्रेंड* से प्रभावित इस फ़िल्म में डीनो मोरिया और अनुपम खेर भी एक महत्वपूर्ण किरदार में नज़र आएंगे. संगीत सलीम-सुलेमान ने तैयार किया है. फ़िल्म की स्क्रिप्ट ख़ुद उदय चोपड़ा ने ही लिखी है.

दूल्हा मिल गया

फ़िल्म *दूल्हा मिल गया* से सुष्मिता सेन फ़िल्म निर्माण के क्षेत्र में क़दम रख रही हैं. हालांकि फ़िल्म के निर्माता के तौर पर विवेक वासवानी का नाम बताया जा रहा है, पर दरअसल वह फ़िल्म के सह निर्माता हैं. शाहरूख़ की व्यस्तता की वजह से फ़िल्म पूरा होने में काफ़ी समय लगा है, पर फ़ाइनली आठ जनवरी को फ़िल्म सिनेमाघरों में नज़र आएगी. शाहरूख़ और सुष्मिता के अलावा फ़िल्म में फरदीन ख़ान, इशिता शर्मा, मोहित चड्ढा, तारा शर्मा, सुचित्रा पिल्लई, जॉनी लीवर और विवेक वासवानी भी हैं. फ़िल्म का निर्देशन मुदस्सर अज़ीज़ ने किया है. ग़ौरतलब है कि मुदस्सर सुष्मिता के ब्वॉयफ्रेंड हैं. फ़िल्म जीवन साथी की तलाश में घूमते हुए तीन जोड़ों की कहानी कहती है. इसका बैकड्रॉप पंजाब और अमेरिका है. शुरूआत में सुष्मिता ने शाहरूख़ को फ़िल्म में गेस्ट अपीयरेंस के लिए राजी किया था. लेकिन उनकी फेस वैल्यू को देखते हुए फ़िल्म में उनका रोल बढ़ा दिया गया है. फ़िल्म में संगीत ललित पंडित (जतिन-ललित जोड़ी के ललित) का है. जबकि कहानी मुदस्सर और विवेक ने मिलकर लिखी है.

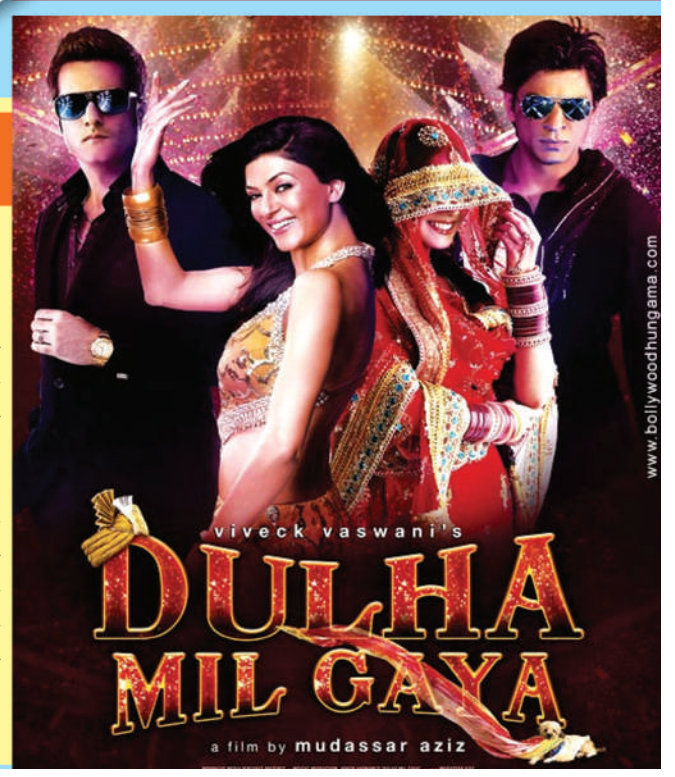

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 28 दिसंबर 2009–3 जनवरी 2010

www.chauthiduniya.com

दरकने लगी रिश्तों की दीवार

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

■ **भाजपा ने खोली सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल**

बिहार में भाजपा और जदयू सत्ता के भागीदार हैं. हैरानी की बात यह है कि भाजपा को नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है और नीतीश को भाजपाई सांप्रदायिक नज़र आ रहे हैं. यही बिहार की सियासत की कड़वी सच्चाई है.

बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनावी साल में प्रवेश करने से ठीक पहले ही भाजपा व जदयू के रिश्तों की दीवार दरकने लगी है. आम जनता से जुड़ी कई योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल विपक्ष ने नहीं, बल्कि सरकार में शामिल भाजपा ने खोलकर यह बात उजागर कर दी कि सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. जन वितरण प्रणाली, मिड डे मील व आंगन बाड़ी केंद्रों में कमीशनखोरी को उदाहरण बनाकर भाजपा ने गठबंधन सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. चार साल तक जदयू के साथ सत्ता सुख भोग चुकी, भाजपा का विपक्षी तेवर वाला यह चेहरा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है. भाजपा के इस नए पैंतरे से विपक्षी दलों को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है, जिसकी तलाश में वह चार सालों से लगे थे. गठबंधन के कमज़ोर होने का नफा- नुक़सान विपक्षी दल समझ रहे हैं और जनता की अदालत में वे इसे भुनाने की तैयारी में जुट गए हैं.

इस सारे विवादों की जड़ में भाजपा के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र झा द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया वह पत्र है, जिसमें उन्होंने कुछ योजनाओं में फैले भ्रष्टाचार का ख़ुलासा किया है. चार पृष्ठों का यह पत्र इस बात का गवाह है कि भाजपा अपनी ही सरकार द्वारा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए चलाई जा रही कुछ योजनाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं है. पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार की दो कल्याणकारी योजनाएं आंगन बाड़ी और मिड डे मील भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई हैं.

रामविलास पासवान

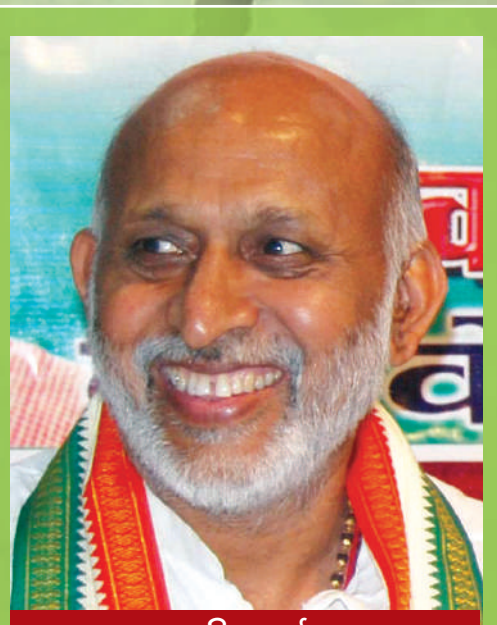

अनिल शर्मा

श्याम रजक

पत्र में यह भी कहा गया है कि जन वितरण प्रणाली में कमीशनखोरी संस्था का रूप ले चुकी है. इसमें उसके बदले में डीलरों को मिलने वाले सरकारी संरक्षण पर भी सवाल उठाए गए हैं. पत्र में पूछा गया है कि एसडीओ के कार्यकलापों की जांच उनके समकक्ष या कनिष्ठ अधिकारियों को देना कैसे मुनासिब है? आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकलाप पर प्रहार करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि बतौर कमीशन एक सीडीपीओ एक आंगनबाड़ी केंद्र से दो हज़ार रुपये प्रतिमाह लेता है. इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति में 40 हज़ार से लेकर सवा लाख रुपये तक लिए जा रहे हैं. इसी तरह मिड डे मील में भी मची लूट की चर्चा पत्र में की गई है. पत्र में कहा गया है कि सरकार ने अलग से प्रति विद्यार्थी नकद राशि देने का प्रावधान किया है, जिसका ग़लत उपयोग हो रहा है. वर्ग में न आने वाले छात्रों को भी उपस्थित दिखाकर उसके नाम से अनाज और राशि उठाए जा रहे हैं.

भाजपा के इस पत्र से राजनीतिक तूफान आ गया है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दकी कहते हैं कि हमलोग तो बार- बार यह कहते आ रहे हैं कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है. आज भ्रष्टाचार का मसला उठाकर भाजपा अपनी ज़िम्मेदारी से कैसे बच सकती है? राज्य में भाजपा और जदयू की मिली जुली सरकार है और इस पाप के लिए दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं. सिद्दकी का कहना है कि भाजपा को सरकार के जाने का अहसास हो चुका है, इसलिए वह पिंड छुड़ाकर भागना चाहती है, लेकिन भाजपा के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र झा कहते हैं कि गठबंधन में दरार जैसी कोई बात नहीं है. हमारा गठबंधन जदयू से है और आगे भी रहेगा पर जनता से जुड़े मसलों से सरकार को अवगत कराने की ज़िम्मेदारी हर किसी की है. इधर जदयू प्रवक्ता श्याम रजक का मानना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मामले में नीतीश सरकार ने बेजोड़ काम किया है. अगर पत्र में किसी इलाक़े का मामला उठाया गया है तो सरकार इसकी पूरी जांच कराएगी और दोषी लोगों को इसकी सज़ा भी मिलेगी. भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाने के लिए तो सरकार ने क़ानून बनाकर केंद्र के पास भेजा है. देरी तो दिल्ली से हो रही है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा को लगता है कि भाजपा का यह पत्र जदयू से दूर होने की पहली कड़ी है. शर्मा का कहना है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर कुछ मंत्रियों को बैठा देने के दिन से भाजपा जदयू से ख़फा है. भाजपा अपना कोई एजेंडा लागू नहीं कर पा रही है. सरकार में भ्रष्टाचारी अफसरों का बोलबाला है. भाजपा को लगता है कि नीतीश सरकार इसे खा जाएगी. इसलिए अब भ्रष्टाचार का मसला उठाकर ख़ुद को साफ़-सुथरा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. जनता के सामने भाजपा का चेहरा बेनक़ाब हो चुका है. लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान दो टूक कहते हैं कि यह सरकार अब जाने वाली है, इसलिए भाजपा ने यह नाटक शुरू किया है. हम बार-बार कह रहे हैं कि यह घोटालेबाजों व समाज को तोड़ने वालों की सरकार है और इसने पिछले चार सालों में जनता के लिए कुछ नहीं किया है.

सूबे की राजनीति को जानने व समझने वाले विश्लेषकों की मानें तो भाजपा के पत्र के बहुत सारे मायने हैं. चुनावी साल में भाजपा जनता को यह संदेश देना चाहती है कि भले ही पार्टी सत्ता में भागीदार है, पर निचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी. स्वच्छ छवि भाजपा की विरासत है और उसे किसी भी क़ीमत पर बरक़रार रखा जाएगा. इसके लिए भले ही उसे अपने ही गठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ सार्वजनिक पत्र क्यों न लिखना पड़े. उपचुनाव के नतीजों व पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व परेशान है. इन चार सालों में भाजपा की छवि ऐसी पार्टी के रूप में बनी जो नीतीश के हां में हां मिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई.

भाजपा अब चाहती है कि कार्यकर्ताओं तक यह संदेश जाए कि जो हुआ सो हुआ, आगे अब ऐसा कुछ न होगा. अगर सरकार में कुछ गड़बड़ी है तो उसे उजागर किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता का भला हो सके. कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के तेवर को पार्टी ज़रूरी मान रही है, क्योंकि किसी वजह से अगर अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आ जाए तो नुकसान की भरपाई की जा सके. अनुमान है कि भाजपा अभी से ही जदयू पर दबाव बनना चाह रही है, ताकि सीटों के बंटवारे में उसे लाभ मिल सके.

अब वजह चाहे जो भी हो पर भाजपा के पत्र से यह बात तो साफ़ हो ही गई है कि सरकार व गठबंधन में सबकुछ सही नहीं है. भाजपा सरकार में है. अगर वह चाहती तो भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किए बिना जदयू पर दबाव बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. हालांकि पिछले चार सालों में कई बार ऐसा हुआ. मगर, चुनावी साल में प्रवेश करने से ठीक पहले इस धमाके से भाजपा व जदयू के रिश्तों में तो दरार आ ही गई.

भाजपा के इस पत्र से राजनीतिक तूफान आ गया है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दकी कहते हैं कि हमलोग तो बार- बार यह कहते आ रहे हैं कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है. आज भ्रष्टाचार का मसला उठाकर भाजपा अपनी ज़िम्मेदारी से कैसे बच सकती है? राज्य में भाजपा और जदयू की मिली जुली सरकार है और इस पाप के लिए दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं.

feedback@chauthiduniya.com

हाल के दिनों में दूसरे दलों में चले गए कांग्रेसियों के पुन: अपने दल में शामिल होने, ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के कांग्रेस में आने और सवर्ण, अल्पसंख्यक एवं बुद्धिजीवी वर्ग के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ़ बढ़ने से पार्टी नेताओं का उत्साह बढ़ गया है.

फेंसीड्रील तथा कोरेक्स नामक कफ़ सीरप के साथ-साथ फोर्टवीन नामक सूई की मांग काफ़ी अधिक है. फोर्टवीन दर्द निवारक तथा अनिद्रा को दूर करने की दवा है, जबकि कफ़ सीरप फेफड़े में जमा बलगम को निकालने की दवा है, लेकिन युवा वर्ग अधिक नशा के लिए इसका सेवन करते हैं.

चौथी दुनिया

जड़ मज़बूत करने में जुटी कांग्रेस

जय कुमार पालित

अवधेश सिंह

अरुण कुमार

कांग्रेस को अपने पुराने गढ़ गया में पिछले दो दशकों के दौरान राजद से दोस्ती का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा, लेकिन अब वह नए सिरे से अपनी ज़मीन मज़बूत करने में जुट गई है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ज़िले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में पुन: अपना आधार मज़बूत करने में लगी है. इसके लिए अप टू बूथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ पर कम से कम पचास सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है. इस तरह से पूरे ज़िले में डेढ़ लाख सदस्य बनाए जाएंगे. ऐसा करके कांग्रेस यह संकेत देना चाहती है कि इस बार वह किसी को वाकओवर देने के मूड में नहीं है.

राजद से अलग होने के बाद लोकसभा चुनाव में बढ़े वोट प्रतिशत और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को मिले मतों ने कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया है. कभी गया के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस का क़ब्ज़ा हुआ करता था, लेकिन राजद से दोस्ती ने कांग्रेस का जनाधार धीरे-धीरे कम कर दिया और यही उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ. पिछले दो दशकों के दौरान गया से कांग्रेस की पूरी ज़मीन ही खिसक गई, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में मुफस्सिल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने सफलता प्राप्त कर एक नई उम्मीद जगाई. हाल के दिनों में दूसरे दलों में चले गए कांग्रेसियों के पुन: अपने दल में शामिल होने, ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के कांग्रेस में आने और सवर्ण, अल्पसंख्यक एवं बुद्धिजीवी वर्ग के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ़ बढ़ने से पार्टी नेताओं का उत्साह बढ़ गया है. इसी का नतीजा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक दर्ज़न से अधिक लोग टिकट के दावेदार हैं. कई विधानसभा क्षेत्रों में तो पचास से अधिक लोग टिकट का दावा कर रहे हैं. कांग्रेस के बढ़ते उत्साह ने मतदाताओं को भी इस दल की ओर देखने पर विवश कर दिया है. विशेष कर गया शहर और सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों इमामगंज एवं बाराचट्टी पर कांग्रेस की विशेष नज़र है. कांग्रेसियों का मानना है कि इन क्षेत्रों में मतदाताओं का रुझान वर्तमान प्रतिनिधियों के ख़िलाफ़ है, इसलिए इन क्षेत्रों पर

कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर का स्वागत करते कांग्रेसी कार्यकर्ता.

विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकुमार पालित ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज़रूर सफलता प्राप्त करेगी. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ेगी. इस बार अच्छी सफलता हासिल होगी, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है. पूर्व सांसद एवं मंत्री रणजीत सिंह ने भी दावा किया है कि पूरी मज़बूती के साथ कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट दिया तो वह चुनाव लड़ेंगे, नहीं दिया तो पार्टी को जिताने के लिए जी-जान से मेहनत करेंगे. उन्होंने नए लोगों को मौक़ा देने की भी बात कही.

ज़िला स्कूल के प्रांगण में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा एवं पूर्व सांसद अरुण कुमार के नेतृत्व में लोजपा के ज़िलाध्यक्ष अलेक्जेंडर खां एवं अमित गुप्ता समेत विभिन्न दलों के लगभग पचास से अधिक नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए. मगध महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आकर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जगदीश टाइटलर ने यह बता दिया कि गया पर कांग्रेस आलाकमान की नज़र है और यहां कांग्रेस के खिसके जनाधार को पुन: वापस लाने के लिए पार्टी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अरुण कुमार की मानें तो नीतीश कुमार से राज्य के लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने राज्य के साथ विकास का छलावा किया. लोगों को ऐसी आशा थी कि जंगलराज से छुटकारे के बाद उन्हें शासन-प्रशासन और विकास के नए रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके चलते बिहार की जनता का नीतीश कुमार से मोहभंग हो चुका है और वह विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही है.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गया में कांग्रेस की तरफ़ से एक ऐसी ज़मीन तैयार करने की कोशिश हो रही है, जहां से पूरे बिहार में पार्टी का परचम लहराया जा सके. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी नेताओं को निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़नी होंगी और एक स्वर में बोलना होगा, ताकि जनता उन्हें गंभीरता से ले.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

अब बिहारी शिमला मिर्च

दिव्या कुमारी

हिमाचल की वादियों की पहचान रही शिमला मिर्च अब बिहार की मिट्टी में भी अपनी ख़ुशबू बिखेरेगी. राज्य में शीघ्र ही शिमला मिर्च की पैदावार हो सकेगी. कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. वे पिछले आठ सालों से यहां के उष्ण तापमान में शिमला मिर्च उगाने को लेकर शोध कर रहे थे. आख़िरकार उनकी मेहनत रंग लाई और अब यह सपना सच होता दिख रहा है. इससे किसान काफ़ी उत्साहित हैं.

संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही राज्य के किसानों को शिमला मिर्च की खेती के लिए सरकार प्रोत्साहित कर सकती है. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक डॉ. मेवालाल चौधरी के प्रयासों से वर्षों पुराना सपना हक़ीक़त में बदलता दिख रहा है. राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ एवं पूसा में शिमला मिर्च की खेती को लेकर अनुसंधान किया जा रहा था. बाढ़ के अगवानपुर विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक डॉ. उमेश सिंह की देखरेख में एक टीम इसका बारीकी से अध्ययन कर रही है. इसकी खेती के लिए औसतन 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, जबकि सूबे का औसत तापमान इससे कहीं अधिक है. हालांकि इस समस्या का समाधान भी वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है. उन्होंने पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. लिहाजा प्रयोग के तौर पर कृषि वैज्ञानिकों ने पॉली हाउस (तापमान नियंत्रक घर) का निर्माण कर शिमला मिर्च की खेती शुरू कर दी है. पहले चरण में क़रीब 500 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉली हाउस का निर्माण कराया गया, जबकि 200 वर्गमीटर में इसकी खेती की जा रही है. अब तक के परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं. मिर्च के पौधों में उम्मीद से भी बेहतर फल आने से कृषि वैज्ञानिक राहत की सांस लेते नज़र आ रहे हैं.

कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम समन्वयक एवं वैज्ञानिक डॉ. उमेश सिंह के मुताबिक़, शिमला मिर्च की खेती करने के लिए तापमान 12 से 18 डिग्री के बीच होना चाहिए. तापमान के इस स्तर को बरक़रार रखने के लिए पॉली हाउस का विकल्प तैयार किया गया. पॉली हाउस लोहे के खांचे में बना तापमान नियंत्रक घर है, जिसका बाहरी आवरण पारदर्शी एवं उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक से तैयार किया जाता है. इस पॉली हाउस में तापमान को मेंटेन किया जाता है. अत्यधिक गर्मी की हालत में पानी के फुहारे देकर इस हाउस के तापमान को कम किया जाता है, जिससे पौधों को नुक़सान नहीं पहुंचता. वैज्ञानिकों के मुताबिक़, शिमला मिर्च की खेती के लिए अगस्त से मार्च तक का समय बिहार में सबसे उपयुक्त हो सकता है. अनुमानत: 500 वर्गमीटर के पॉली हाउस का निर्माण कराने में क़रीब साढ़े चार लाख रुपये का ख़र्च आता है. आम किसानों के लिए यह काफ़ी महंगा ज़रूर है, लेकिन इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को क़रीब पचास फ़ीसदी सब्सिडी दी जा रही है. ज़िला उद्यान पदाधिकारी नितेश कुमार राय के अनुसार, 1000 वर्गमीटर में शिमला मिर्च की खेती किए जाने पर 67,500 रुपये सरकार द्वारा बतौर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है. इस राशि के अतिरिक्त भी सरकार किसानों को अलग से प्रोत्साहन राशि देगी. यदि किसान पॉली हाउस को पूरी तरह सुविधासंपन्न बनाते हैं तो उन्हें एक लाख रुपये इसके लिए अलग से दिए जाएंगे. हालांकि लागत ख़र्च को देखते हुए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

डॉ. उमेश सिंह ने बताया कि सबसे पहले मिर्च के बीज से बिचड़ा तैयार किया जाता है. उसके बाद उन्हें मोटी-मोटी क्यारियां बनाकर लगाया जाता है. दो पौधों के बीच की दूरी अमूमन दो से लेकर चार इंच तक होती है. बिचड़ा लगाने के क़रीब साठ दिनों के बाद पौधों में फल लगने शुरू हो जाते हैं. एक पेड़ में तीन फल तक लगते हैं. फ़िलहाल राज्य भर में शिमला मिर्च की खेती कहीं नहीं की जाती, जबकि बिहार में इसकी मांग और ख़पत काफ़ी अधिक है. राजधानी पटना इसका सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है, जहां 120-140 रुपये प्रतिकिलो की दर से शिमला मिर्च ख़रीदी जा सकती है. किसान भी इस ख़ुशख़बरी से बेहद उत्साहित हैं. कृषि वैज्ञानिक फ़िलहाल यह जानने में जुटे हैं कि इसकी खेती पर आने वाले भारी-भरकम ख़र्च को कैसे कम किया जाए, ताकि सूबे के ग़रीब किसान खेती के इस नए विकल्प को अपना सकें. उमेश सिंह बताते हैं कि शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए वरदान के समान है. इसमें मुनाफ़े की काफ़ी अधिक गुंज़ाइश है, जिससे किसानों की माली हालत सुधर सकती है. लागत में थोड़ी सी भी कमी आई तो यह बिहार के साथ-साथ अन्य ग़रीब प्रदेशों के किसानों के लिए जीने का आधार बन सकती है. मोकामा प्रखंड आत्मा के अध्यक्ष चंदन कुमार भी शिमला मिर्च की खेती को किसानों के लिए उत्साहवर्द्धक मानते हैं और कहते हैं कि इससे आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो रहे किसानों को बेहतर कमाई का अवसर मिलेगा. यदि सामूहिक खेती की जाए तो फिर लागत ख़र्च बंटेगा और किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा. मोकामा के बीडीओ राजेश कुमार भी इसे एक उपलब्धि मानते हैं, लेकिन लागत ख़र्च की अधिकता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसान इसकी खेती में रुचि दिखाते हैं तो सरकार द्वारा अतिरिक्त मदद दिलाए जाने की व्यवस्था की जाएगी.

विधायक अनंत सिंह भी इसे परंपरागत खेती पर आश्रित किसानों के लिए शुभ संकेत बताते हैं. अनंत सिंह इस बात पर ख़ुशी जताते हैं कि बिहार में पहली बार शिमला मिर्च की खेती उनके इलाक़े मोकामा में हो रही है. मोर के प्रगतिशील किसान एवं प्रखंड राजद अध्यक्ष कन्हैया चंद्रवंशी सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को नाकाफ़ी बताते हैं. उनकी मांग है कि जब कृषि पर सरकार का रोडमैप है तो कुल लागत की पचास फ़ीसदी राशि बतौर अनुदान और पच्चीस फ़ीसदी ऋण के तौर पर दी जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें.

पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती का मुआयना करते कृषि वैज्ञानिक.

feedback@chauthiduniya.com

मुख़बिरी का पैसा मुसीबत बना

कहते हैं, क़ानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. इसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता. हां, देर लग सकती है. कुछ ऐसा ही मामला झारखंड में देखने को मिला. यहां क़ानून के एक रखवाले ने ही क़ानून को तोड़ा और मुख़बिरी के पैसों का खुलकर दुरुपयोग किया.

झारखंड के डीजीपी वी डी राम आख़िरकार क़ानून के फंदे में आ ही गए. गुप्त सेवा फंड के दुरुपयोग के मामले में हाईकोर्ट में दर्ज़ तीन जनहित याचिकाओं की सुनवाई शुरू होने के साथ ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई है. वी डी राम के अलावा इस मामले में स्पेशल ब्रांच के पूर्व एडीजी राजीव कुमार भी फंसते नज़र आ रहे हैं.

नियमत: इस राशि की निकासी और व्यय के पदाधिकारी स्पेशल ब्रांच के एडीजी होते हैं. 2005-06 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान नियमों और प्रावधानों की अनदेखी कर गुप्त सेवा फंड की राशि निकाल ली गई. आरोप है कि महज़ 14 दिन के अंदर ही वी डी राम ने इस फंड से औसतन प्रतिदिन 28 लाख रुपये के हिसाब से निकासी कर डाली. इसी तरह स्पेशल ब्रांच के पूर्व एडीजी राजीव कुमार के हस्ताक्षर से मार्च 2008 में ढाई करोड़ रुपये की निकासी को भी संदिग्ध माना गया है. यह मामला पहली बार पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के कार्यकाल में नियम के विरुद्ध डीजीपी के हस्ताक्षर से 5.6 करोड़ रुपये की निकासी के बाद सामने आया.

16 मार्च 2006 को इतनी बड़ी राशि निकाल कर उसे मात्र 14 दिनों में ख़र्च कर दिया गया, जबकि इसकी उपलब्धियां नगण्य रहीं. राज्यपाल के सलाहकार एवं गृह मंत्रालय के प्रभारी टी पी सिन्हा ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की सिफ़ारिश की थी. इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने डीजीपी वी डी राम को फटकार भी लगाई, लेकिन अचानक डीजीपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव से क्लीन चिट हासिल कर ली. उसके बाद प्रशासनिक सरगर्मी लगभग थम सी गई थी. हालांकि पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु ने अवकाश ग्रहण करने के पूर्व इस मामले की फाइल पर अपनी टिप्पणी में उच्चस्तरीय जांच की सिफ़ारिश की थी, लेकिन उसके बाद भी राज्यपाल के बदलने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया. अब हाईकोर्ट की पहल पर फिर यह मामला सुर्ख़ियों में आ गया है.

उल्लेखनीय है कि 2006 से 2008 के बीच एसएस फंड (गुप्त सेवा धन) से 14 करोड़, 18 लाख, 50 हज़ार रुपये की निकासी हो चुकी थी. जानकारी के मुताबिक़, जुलाई 2005 में 2.6 करोड़ रुपये, मार्च 2006 में 5.6 करोड़, मई 2006 में 60 लाख, जून 2006 में 88.5 लाख, मई 2007 में एक करोड़, सितंबर 2007 में पुन: एक करोड़ और मार्च 2008 में आठ करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. इन निकासियों के पूर्व तक बिहार वित्त नियमावली के नियम 39 के तहत मुख्य सचिव प्रशासनिक ऑडिट कराकर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजते रहे, लेकिन इसके बाद भी इस नियम की अनदेखी की गई. महालेखाकार ने मुख्य सचिव से कई बार इस संदर्भ में जानकारी मांगी, मगर वह इसका जवाब देने में असमर्थ रहे. दरअसल इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से मुख्य सचिव के पास कोई जानकारी नहीं भेजी गई.

ग़ौरतलब है कि 2006 के मार्च में बजट सत्र के दौरान प्रश्न और ध्यानाकर्षण सूचना के तहत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने इस मामले को सदन में उठाया था, लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को कार्यसूची से ही ग़ायब कर दिया गया. काफ़ी हंगामे के बाद भी इस पर बहस नहीं हो सकी. हालांकि इंदर सिंह नामधारी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वह ख़र्च का ब्योरा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस मद की राशि में अचानक कई गुना हुई बढ़ोतरी और निकासी की पद्धति के संबंध में जानकारी मांगी है. उनका कहना था कि गुप्त सेवा धन के नाम पर साल में पहले 30 लाख रुपये ख़र्च होते थे, मगर अचानक यह ख़र्च 870 लाख रुपये कैसे हो गया. इससे पूर्व जब नामधारी स्पीकर हुआ करते थे, तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा सदन में देखने को मिला था. हालांकि नामधारी पर भी एसएस फंड के दुरुपयोग के मामले को दबाने का आरोप लगा था. उसकी वजह यह बताई गई थी कि उस वक़्त राधाकृष्ण किशोर से नामधारी की गहरी दोस्ती थी. जब उनके बीच राजनीतिक मतभेद उभरे तो नामधारी ने मौक़ा ताड़कर इस मामले को सदन में उठाया.

इस मामले में पहली बार सामाजिक कार्यकर्ता राजू कुमार ने 14 अक्टूबर 08 को लोकायुक्त की अदालत में वी डी राम को प्रतिवादी बनाते हुए याचिका दायर की. याचिका में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्य सचिव पी पी शर्मा, पूर्व वित्त आयुक्त मुख्तियार सिंह, गृह सचिव जे वी तुविद और पूर्व गृहमंत्री सुदेश महतो को भी प्रतिवादी बनाया. याचिका में इस वित्तीय घोटाले के लिए इन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया. हालांकि इस याचिका पर चार माह बाद भी सुनवाई नहीं हो सकी. उसके बाद राजू ने सूचना के अधिकार का सहारा लिया. फिर भी उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली. सूचना अधिकार की धारा 8 के तहत देय नहीं बताया जाता है. इस मामले में राजू ने 27 फरवरी 09 को राज्यपाल सचिवालय को पत्र भी सौंपा था. उन्होंने डीजीपी की ओर से लगातार धमकियां और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रांची के समक्ष 27 नवंबर 08 को परिवाद संख्या 396-08 दर्ज़ कराकर अपनी

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthiduniya.com

गुप्त सेवा धन की बंदरबांट

वीडी राम

गुप्तचरी के क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही गुप्त सेवा धन की अहम भूमिका रही है. इस राशि के ज़रिए मुख़बिरों का जाल बिछाया जाता है और सूचनाएं एकत्र की जाती हैं. भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की गुप्तचर संस्थाएं अपनी सरकारों के जरिए एसएस फंड प्राप्त करती हैं. इसके बगैर गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव नहीं होता. चूंकि मुख़बिरों का नाम गुप्त रखा जाता है, इसलिए इस ख़र्च का विशेष लेखाजोखा नहीं रखा जाता है. इसके दुरुपयोग की पूरी गुंज़ाइश रहती है. यह अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है. उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित इलाक़ों में यह धनराशि ज़्यादा होती है. इसके अलावा अंडरवर्ल्ड और सामान्य अपराध से संबंधित सूचनाओं के संकलन के लिए भी इसका प्रावधान किया जाता है. राज्य गठन के बाद झारखंड में उग्रवादी गतिविधियों पर क़ाबू पाने के लिए सरकार ने एसएस फंड के मद में समुचित राशि उपलब्ध कराई. इसके बावजूद उग्रवाद का दायरा निरंतर बढ़ता ही गया. उग्रवादी संगठनों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित नहीं हो सकीं. जाहिर है, इस राशि का उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा होता आया है. बढ़ते उग्रवाद के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से एस एस फंड के मद में पूर्व की तुलना में तकरीबन बीस गुना बढ़ोतरी तो करवा ली, लेकिन मुख़बिरों के बीच वितरित करने के बदले इस फंड के अधिकांश हिस्से की बंदरबांट कर ली जाती रही.

दवा को दारू बना डाला

आप और हम ख़ांसी पर क़ाबू पाने के लिए जिस कफ़ सीरप का उपयोग करते हैं, कुछ युवा उसे एक बार में ही गटक जाते हैं. जी हां, वे ऐसा इलाज के लिए नहीं, बल्कि नशे के लिए करते हैं. इतना ही नहीं, सामान्य ऑपरेशन के पूर्व मरीज़ों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन जब नशेड़ी ख़ुद अपनी नसों में उतारते हैं तो यह देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. बेगूसराय और खगड़िया ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में युवा इस तरह दवाओं और इंजेक्शनों का इस्तेमाल स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं, बल्कि नशे के लिए कर रहे हैं. जानकार कहते हैं कि नशेड़ी अगर इन दवाओं का सेवन करना बंद कर दें तो शायद वे ज़िंदा लाश बन जाएं. चलना-फिरना तो दूर, उनका शरीर हिलना-डुलना भी बंद कर देगा. ऐसा नहीं है कि इस तरह की दवाओं का सेवन करने वाले लोग इनके दुष्प्रभाव से अवगत नहीं हैं. लेकिन, शुरुआत में शौक़िया तौर पर इन्हें इस्तेमाल करने वाले अब इन दवाओं-इंजेक्शनों के गुलाम बन चुके हैं. अगर दवा छोड़ी तो नींद नहीं आएगी, चलना-फिरना तक बंद हो जाएगा. दवा न मिलने पर नशेड़ी अपराध करने से भी गुरेज़ नहीं करते, इसीलिए उनके परिवार वालों ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं.

स्वयंसेवी संस्था सर्वहितम एजूकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक़, सिर्फ़ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लगभग 48 प्रतिशत युवा इस तरह की दवाओं के नशे की गिरफ़्त में फंस चुके हैं. हालांकि इस तरह की आदत सबसे पहले किशोर वर्ग में ही पनपी. कल तक किशोरों के लिए यह महज़ शौक़ था, लेकिन अब कफ़ सीरप और इंजेक्शन लेना उनकी मजबूरी बन गई है. खगड़िया ज़िला अंतर्गत अस्पताल रोड स्थित एक मेडिकल हॉल के मालिक राजेश कुमार बताते हैं कि इन दिनों फेंसीड्रील और कोरेक्स नामक कफ़ सीरप के साथ-साथ फोर्टविन नामक इंजेक्शन की मांग काफ़ी अधिक है. फोर्टविन दर्द निवारक एवं अनिद्रा को दूर करने की दवा है, जबकि कफ़ सीरप फेफड़े में जमा बलगम को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कुमार बताते हैं कि फेंसीड्रील का इस्तेमाल नशे के तौर पर होने के कारण जब इसकी ज़्यादा मांग बढ़ी तो कालाबाज़ारी शुरू हो गई. फेंसीड्रील की क़ीमत खुले बाज़ार में 78 रुपये है, जबकि कालाबाज़ारी के कारण यह सौ से लेकर एक सौ दस रुपये तक में मिल रही है. बढ़ती मांग के कारण थोक विक्रेताओं ने सुलभ तरीक़े से फेंसीड्रील बेचना बंद कर दिया है. यही कारण है कि मेडिकल की सामान्य दुकानों पर फेंसीड्रील उपलब्ध नहीं है. वैसे मार्केट में कफ़ सीरप के नाम पर इतनी दवाएं उपलब्ध हैं कि लोग फेंसीड्रील जैसी महंगी दवा ख़रीदने से परहेज करते हैं. नशे के तौर पर लोग फेंसीड्रील या कोरेक्स का ही सेवन इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोनेरियम 4 एमजी एवं कोडिन फोसफेट 10 एमजी भी मिश्रित है. नशा ऐसा कि शराब भी इसके सामने बौनी साबित हो जाती है. हालांकि उक्त दोनों कंपोजीशन एक स्वस्थ आदमी के लिए घातक हैं, लेकिन बलगम निकालने के लिए इससे बढ़िया कंपोजीशन नहीं हो सकता है.

खगड़िया के रसौंक नया गांव निवासी मो. साजिद फेंसीड्रील पीने के आदी हो चुके हैं. वह कहते हैं कि कॉलेज के दिनों में एक छात्र-नेता ने कफ़ सीरप पीने की लत लगाई. अब यह उनके लिए शौक़ के बजाय आदत बन चुकी है. अगर रोज़ इसका सेवन न करूं तो शायद भगवान ही मुझे बचाए. ग़रीबी के कारण परिवार के लोग दोनों वक़्त भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं. बावजूद इसके मुझे रोज़ फेंसीड्रील चाहिए. कारपेंटर का काम करने के बाद भी रोज़ इतनी कमाई नहीं होती कि घर-परिवार चलाने के साथ-साथ वह रोज़ फेंसीड्रील भी ख़रीद सकें. फेंसीड्रील के लिए उन्हें कभी-कभी घर का कोई सामान तक बेचना पड़ता है. फेंसीड्रील न पीने पर पैरों में झुनझुनी, दिमाग में सूनापन और एक अलग तरह की झल्लाहट पैदा हो जाती है. ऐसा लगता है कि बस ज़हर ही पी लो! साजिद ऐसे कोई अकेले युवा नहीं हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोग इस तरह के नशे की गिरफ़्त में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं. नशा न मिलने के कारण कई नशेड़ियों की मौत हो चुकी है और कई पागलखाने में भर्ती हैं. फोर्टविन लेने के आदी हो चुके कृष्णानगर निवासी गौतम और मंजीत के मुताबिक़, वे प्रतिदिन फोर्टविन के चार से पांच इंजेक्शन लेते हैं. शुरुआत में तो आनंद मिलता था, लेकिन अब यह मजबूरी है. इंजेक्शन न लेने पर भूख तक नहीं लगती. इसलिए रोज़ इंजेक्शन लेना पड़ता है. पहले कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन अब स्वयं इंजेक्शन लेता हूं. खगड़िया सदर अस्पताल के समीप स्थित सुलभ शौचालय नशेड़ियों का केंद्र बन चुका है. हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच प्रसाद ने बताया कि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कि अगर अभिभावक बच्चों की देखभाल सही तरह से नहीं करेंगे तो वे इस तरह के नशे के शिकार हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि मां-बाप के सामने बच्चे कफ़ सीरप का सेवन यह कहकर करते हैं कि ख़ांसी से निजात पाने के लिए उन्होंने डॉक्टर के परामर्श से कफ सीरप ख़रीदा है. जबकि हक़ीक़त कुछ और होती है. प्रसाद ने कहा कि अब तो नशेड़ी प्रवृत्ति के युवक सुलेशन, फेविकॉल और आयोडेक्स आदि का भी इस्तेमाल करने लगे हैं. सुलेशन को सिगरेट के काग़ज़ पर रखकर उसकी गंध को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फेविकॉल पिया जाता है. आयोडेक्स को ब्रेड के साथ खाया जा रहा है. प्रसाद के मुताबिक़, सौ ग्राम आयोडेक्स का एक बार सेवन कर रहे लोग एक कोबरा दंश के समान नशा कर रहे हैं. अगर वह किसी इंसान के शरीर में दांत गड़ा दें तो शायद उसे बचा पाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की दवाओं का सेवन करने वाले लोग अल्पायु हो जाते हैं. उनका फेफड़ा, किडनी और शरीर के अन्य अंग बेकार हो जाते हैं. इसलिए किसी भी इंसान को क्षणिक मज़े के लिए इस तरह के नशे की गिरफ़्त में नहीं फंसना चाहिए. इससे कैंसर होने का ख़तरा भी मंडराने लगता है. दूसरी तरफ़ पुलिस का कहना है कि इसके लिए अभिभावक ही ज़िम्मेदार हैं. बावजूद इसके उसकी नज़र इस तरह की दवाएं बेचने और सेवन करने वालों पर टिकी रहती है.

राजेश सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 28 दिसंबर 2009 –3 जनवरी 2010

7-8 माह पहले पूर्णिया के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक बच्चू सिंह मीणा ने गुलाबबाग स्थित लड्डू गोपाल इंटरप्राइजेज से लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी सुपारी बरामद की थी.

सुपारी तस्करों की चांदी

सीमांचल के विभिन्न इलाक़ों में इन दिनों सुपारी तस्करों की चांदी है. निगरानी करने वाली एजेंसियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर सुपारी की तस्करी हो रही है. नेपाल से लाई गई सुपारी को जोगबनी, गुलाबबाग, फरबिसगंज और कटिहार में इकट्ठा करके उसे नागपुर और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भेजा जाता है, जहां इसका उपयोग गुटखा फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से किया जा रहा है. भारत में चीनी, दाल और रासायनिक खाद समेत अन्य सामानों की क़ीमत बढ़ाने में इन तस्करों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है.

इन दिनों नेपाल से तस्करी करके लाई जाने वाली सुपारी सीमांचल में चर्चा का विषय है. जानकारी के अनुसार, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से नेपाल आने वाली सुपारी की ख़पत यहां पर नाममात्र है. सस्ती होने के कारण इसे तस्कर भारत ले आते हैं. यहां से सुपारी को प्रमुख शहरों की पान मसाला एवं गुटखा फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है. ग़ौरतलब है कि भारत में पान मसाला एवं गुटखा के बढ़ते प्रचलन के कारण सस्ती विदेशी सुपारी की जबर्दस्त मांग है. वहीं भारतीय सुपारी की क्वालिटी उच्च होने के कारण उसकी क़ीमत अधिक होती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार एवं नेपाल सीमा के बीच अररिया ज़िले का जोगबनी और उसके आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल से तस्करी के लिए काफी सुरक्षित है. तस्कर सबसे पहले नेपाल से सड़क मार्ग द्वारा जोगबनी, फरबिसगंज, अररिया, गुलाबबाग और कटिहार आदि स्थानों पर सुपारी एकत्रित कर लेते हैं. उसके बाद उसे ट्रक द्वारा नागपुर और कानपुर जैसे शहरों में भेज देते हैं. लेकिन हाल के दिनों में सड़क मार्ग से सुपारी लाना सुरक्षित नहीं रहा, जिसके चलते उन्हें रेलमार्ग का रुख करना पड़ा. कटिहार एवं जोगबनी के बीच लगभग 130 किलोमीटर का रेलमार्ग उनके लिए वरदान साबित हो रहा है. सुपारी अब ट्रेन की विभिन्न बोगियों के शौचालयों, सीटों और गार्ड के केबिन में छुपाकर लाई जाती है. इसमें जीआरपी से लेकर रेलवे कर्मचारियों तक की मिलीभगत रहती है. स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन को चेन खींचकर या फिर ड्राइवर और गार्ड के सहयोग से रोककर बीच में ही सुपारी उतार ली जाती है. कभी-कभी तो पूर्णिया जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर खुलेआम सुपारी उतारी जाती है और वहां मौजूद अधिकारी और सुरक्षाबल मूकदर्शक बने रहते हैं.

इन दिनों पूर्णिया जंक्शन और उससे पहले स्थित पूर्णिया सिटी रेलवे स्टेशन विदेशी सुपारी उतारने के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. आलम यह है कि स्थानीय लोग सिटी रेलवे स्टेशन को सुपारी स्टेशन कहकर पुकारते हैं. यहां से सुपारी ठेलों, रिक्शों और छोटे ट्रकों के ज़रिए गुलाबबाग स्थित गोदामों में पहुंचती है. इसके बाद फर्जी कागजात तैयार करके उसे ट्रकों द्वारा नागपुर और कानपुर जैसे शहरों को भेज दिया जाता है. .

गौरतलब है कि विगत 7-8 माह पहले पूर्णिया के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक बच्चू सिंह मीणा ने गुलाबबाग स्थित लड्डू गोपाल इंटरप्राइजेज से लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी सुपारी बरामद की थी. बाद में सुपारी की हेराफेरी का आरोप तत्कालीन थाना प्रभारी पर लगा था और उसकी गाज उन पर गिरी थी. मालूम हो कि सदर थाने की दूरी सिटी ढाला से लगभग 500 मीटर है. कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त डी के सिन्हा से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने लोगों का अपेक्षित सहयोग न मिलने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया. वहीं पूर्णिया के कस्टम अधीक्षक ए सी मिश्रा ने इस संबंध में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. उन्होंने इतना जरूर कहा कि विदेशी सुपारी को छापामारी करके सीज किया जाएगा.

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

अपना सपना मनी-मनी

ग्लैमर और पैसों की चकाचौंध भरी फ़िल्मी दुनिया में शादी के बाद अभिनेत्रियां अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती हैं, क्योंकि स्किन शो के इस खेल में ढलती उम्र के साथ उनकी चमक कम होने लगती है तथा बला की ख़ूबसूरत नई तारिकाएं उनका सिंहासन हिलाने लगती हैं. इसीलिए आज की अभिनेत्रियां अपने अच्छे दौर में ही ढेर सारा पैसा कमाकर अपनी तिजोरी भर लेती हैं. इसके लिए वे शादियों, मेहमान भूमिकाओं और आइटम नंबर से लेकर स्टेज शो तक में शिरकत करती हैं. ऐसा ही कुछ अपनी मदहोश अदाओं से दर्शकों का दिल जीतने वाली सेक्सी बाला शीला कर रही हैं. उन्होंने अपना साइनिंग अमाउंट बढ़ा दिया है, जिससे निर्माताओं को पसीना आ रहा है. वह मुख्य भूमिकाओं के अलावा आइटम नंबर के ऑफर भी स्वीकार कर रही हैं, लेकिन इसके बदले मोटी फीस ले रही हैं. अभी तक नेक्स्ट डोर गर्ल की छवि में क़ैद शीला अचानक बोल्ड हो गई हैं. हाल ही में उनका भोजपुरी सेक्सी आइटम नंबर काफ़ी लोकप्रिय हुआ है. इसके अलावा उनकी फ़िल्में भी ठीकठाक बिज़नेस कर रही हैं. यही नहीं, भोजपुरी फिल्मों के अलावा उनकी तमिल फ़िल्म *परूगु* भी धूम मचा रही है. ऐसे में उनके साइनिंग अमाउंट का सातवें आसमान पर पहुंचना लाजिमी है. शीला कहती हैं कि वह अपने स्टारडम के मुताबिक़ ही फीस ले रही हैं. वह अकेली नहीं हैं, जो अन्य भाषाओं की फ़िल्मों और डांस कार्यक्रमों के ज़रिए पैसा कमा रही हैं. भोजपुरी सुपर स्टार दिनेशलाल यादव निरहुआ ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली है और वह कई तेलुगु फ़िल्मों से गाढ़ी कमाई कर रहे हैं. ऐसे में अगर शीला का सपना मनी-मनी है तो इसमें बुराई क्या है!

मिथिलांचल की मांग ने ज़ोर पकड़ा

विकास कुमार

तेलंगाना पर केंद्र ने सहमति क्या जताई, अलग मिथिलांचल राज्य की मांग ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ लिया. बिहार के सोलह ज़िलों को मिलाकर बनने वाले इस राज्य की मांग से जुड़े नेताओं ने पुरानी फाइलें खोलकर संघर्ष की नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किसी भी तरह के बंटवारे की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन अलग मिथिलांचल आंदोलन से जुड़े नेता हार मानने को तैयार नहीं हैं. उत्तर बिहार को विकसित करने के इरादे से मिथिलांचल की पृष्ठभूमि तैयार की गई. एक समय था, जब मिथिलांचल राज्य का नारा भाजपा नेता एवं विधान परिषद के तत्कालीन सभापति ताराकांत झा ने बुलंद किया था. उनकी राय में मिथिलांचल के मुद्दे पर सभी पार्टियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मिथिलांचल भी अलग राज्य बनाने की कसौटी पर खरा उतरता है, मगर अलग राज्य का निर्माण नीतिगत आधार पर होना चाहिए. ताराकांत झा का मानना है कि अलग राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक एकता, पिछड़ापन और विकास के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से, जैसा कि तेलंगाना के मामले में हुआ. झा ने कहा कि जहां तक मिथिलांचल की बात है तो यह छोटे राज्य की गिनती में आएगा ही नहीं, क्योंकि यह देश के मौजूदा कई राज्यों से बड़ा होगा. भौगोलिक रूप से इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में महानंदा और पश्चिम में गंडक नदी है. इसकी सीमा बेतिया से किशनगंज तक फैली है. अतीत में मिथिला राज्य की राजधानी बेतिया के पास सुगांव रही थी.

पृथक मिथिलांचल राज्य निर्माण के लिए दरभंगा प्रमंडल आयुक्त कार्यालय पर बीती 14 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद के तत्वावधान में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया. परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. राममोहन झा ने कहा कि जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उसी समय मिथिलांचल की उपेक्षा की गई. आज जब आर्थिक पिछड़ेपन को राज्य के गठन का आधार बनाया गया है, तब भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिथिलांचल की उपेक्षा की जा रही है. आज़ादी के बाद जहां देश के अन्य हिस्से विकसित हुए, वहीं मिथिलांचल दिन- प्रतिदिन पिछड़ता गया. किसी ने भी मिथिलांचल के विकास के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई. नए उद्योग-धंधों की स्थापना और विकास की जगह यहां के कल-कारखाने एवं व्यवसाय चौपट हो गए. हर साल कोसी, करेह, बागमती, बूढ़ी गंडक, वाया, बलान एवं गंगा नदी की बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से त्रस्त मिथिलांचल के 16 ज़िले विकास की पटरी से पूरी तरह नीचे उतर चुके हैं. डॉ. झा ने कहा कि मिथिलांचल के अस्तित्व की रक्षा की खातिर उसके आर्थिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास के लिए पृथक राज्य के गठन हेतु आंदोलन को धारदार बनाया जाएगा. जब तक मिथिलांचल राज्य का गठन नहीं होता, तब तक पूरे दमखम के साथ आंदोलन जारी रहेगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शकील अहमद भी पृथक मिथिलांचल राज्य के पक्षधर हैं. उन्होंने तेलंगाना की तरह पृथक मिथिलांचल के गठन पर बल देते हुए कहा कि लोग इसके लिए राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं. डॉ. अहमद ने कहा कि छोटे राज्यों के गठन की एक परिकल्पना है और मिथिलांचल उसकी सभी शर्तों एवं अर्हताओं को पूरा करता है. केंद्र सरकार और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के प्रति मिथिलांचल के लोगों में अगाध प्रेम की भावना है. दरभंगा ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. कमरूल हसन का कहना है कि पृथक मिथिलांचल राज्य के गठन के लिए दरभंगा से दिल्ली तक लोगों की कतार खड़ी हो जाएगी.

अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के महासचिव डॉ. वैद्यनाथ चौधरी उर्फ बैजू ने पिछले दो दशकों से आंदोलन छेड़ रखा है. डॉ. चौधरी ने ऐलान किया है कि प्राचीनकाल में मिथिला राज्य था. अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान मिथिलांचल को अंग-भंग कर डाला था. 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग होने लगा, तभी से मिथिला राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन जारी है.

अंतरराष्ट्रीय मैथिली परिषद ने इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रभावकारी रणनीति बनाई है, जिससे राज्य एवं केंद्र सरकार मुकर नहीं सकती है. उसने तेलंगाना, बुंदेलखंड और पूर्वांचल आदि राज्यों के गठन का समर्थन किया और मिथिलांचल के लोगों से दिल्ली के आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान किया है.

समस्तीपुर के समाजसेवी अजय कुमार सिन्हा का मानना है कि आज़ादी के बाद छोटे-छोटे प्रांत हरियाणा, पंजाब और गुजरात आदि विकसित हुए. झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उक्त प्रांत के लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं. इसे देखते हुए मिथिलांचल के लोगों में भी पृथक मिथिलांचल राज्य के गठन की लालसा बलवती हो रही है. मिथिला राज्य अभियान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सुरेश्वर झा का भी मानना है कि मिथिलांचल अलग राज्य के सारे मापदंडों को पूरा करता है. इसलिए विकास के लिहाज़ से इसे अलग अस्तित्व प्रदान न करना करोड़ों मिथिलावासियों का अपमान होगा.

feedback@chauthiduniya.com

नव वर्ष 2010 मंगलमय हो

शरद यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू

नीतीश कुमार (मुख्यमंत्री, बिहार)

राजीव रंजन सिंह
प्रदेश अध्यक्ष जदयू (बिहार)

दिनेश चन्द्र यादव
सांसद (खगड़िया)

नीतीश सरकार के चार साल पूरा होने
के साथ-साथ नववर्ष 2010 के सुअवसर
पर तमाम अमन व विकास पसंद बिहार वासियों
तथा जदयू के समर्पित कार्यकर्त्ताओं को

हार्दिक बधाई

नीतीश सरकार ने कुशासन की गुलामी से दिलायी निजात,
सुशासन का कराया एहसास फक्र है बिहार के मुखिया नीतीश जी पर,
जिन्होंने बिहारी होने पर महसूस कराया गर्व
नववर्ष 2010 तमाम बिहार वासियों के लिए लेकर आए नयी सौगात

इन्ही शुभकामनाओं के साथः-

-:निवेदक:-

राजू फोगला
वार्ड पार्षद
सह सदस्य
अनुश्रवण समिति
खगड़िया

अरविन्द मोहन
सदस्य
जिला बीस सूत्री
कमेटी खगड़िया

पुरुषोतम अग्रवाल राजू गुप्ता
सामाजिक
कार्यकर्त्ता
खगड़िया

सदस्य अनुमंडल
अनुश्रवण समिति
खगड़िया

सुनील कुमार
चौथम प्रखंड
अध्यक्ष जदयू
सह बीस सूत्री
अध्यक्ष चौथम